श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया
विक्रम संवत 2081

लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, हल्द्वानी, अयोध्या व कानपुर से प्रकाशित

बुधवार, 24 जुलाई 2024
वर्ष 34, अंक 177, पृष्ठ 18
2 राज्य, 6 संस्करण
मूल्य 5 रुपये

# अमृत विचार

लखनऊ

एक सम्पूर्ण अखबार

www.amritvichar.com

बजट 2024

₹ 48.21 लाख करोड़ रुपये का बजट

## मध्मय वर्ग को राहत

**7.75** लाख तक की आय पर कोई कर नहीं

## युवाओं के लिए खास

**05** योजनाएं युवाओं के लिए इस बजट में

# निर्मल बजट

**बजट में मध्यम वर्ग को कर राहत, रोजगार सृजन, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन पर जोर**

**सीतारमण ने अपना सातवां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया**

यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। गांव को समृद्धि पर ले जाने वाला बजट है और नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। आम बजट 2024-25 से जनजातीय समाज, दलित और पिछड़ों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। देश में करोड़ों नए रोजगार पैदा होंगे।

–नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

## सहयोगी दलों के बिहार और आंध्र को 75 हजार करोड़

नई दिल्ली, एजेंसी/ ब्यूरो

आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग एवं नौकरीपेशा लोगों को राहत के साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों- बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई परियोजनाओं का भी ऐलान किया। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया। वहीं आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बजट में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है। मध्यम वर्ग को 7.75 लाख की सालाना कमाई पर कोई कर नहीं देगा होगा, वहीं युवाओं के लिए पांच नई योजनाएं भी इस बजट में शामिल की गईं।

सीतारमण ने अपना सातवां और नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए स्टार्टअप में सभी श्रेणी के निवेशकों के लिए एंजल कर समाप्त करने की घोषणा की। जब कोई गैर-सूचीबद्ध या स्टार्टअप कंपनी शेयर जारी कर पूंजी जुटाती है और उसका मूल्य कंपनी के उपयुक्त बाजार मूल्य से अधिक होता है, तब उस पर एंजल कर लगाया जाता है। बजट में मोबाइल फोन एवं सोने पर सीमा शुल्क में कटौती की गई है और पूंजीगत लाभ कर को सरल बनाया गया है। बिहार के लिए एक्सप्रेसवे, बिजलीघर, हेरिटेज कॉरिडोर और नए हवाई अड्डों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन करने की घोषणा की। बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू राज्य के लिए आर्थिक पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। आंध्र प्रदेश के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता के रूप में 15,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

सीतारमण ने कहा कि सरकार का राजकोषीय घाटा 2024-25 में जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह 2024-25 के लिए फरवरी में पेश अंतरिम बजट में अनुमानित 5.1 प्रतिशत से कम है। इसका कारण मजबूत कर संग्रह और भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षा से अधिक लाभांश प्राप्ति है। उन्होंने सकल बाजार उधारी को मामूली रूप से घटाकर 14.01 लाख करोड़ रुपये कर दिया। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन करोड़ किफायती आवासों के निर्माण के लिए सहायता, छोटे और मझोले उद्यमों को कर्ज सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमों के लिए कर्ज सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये, 12 औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ और व्यय 48.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। शुद्ध कर प्राप्ति 25.83 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।

### केन्द्रीय बजट 2024-25 (पैसे में)

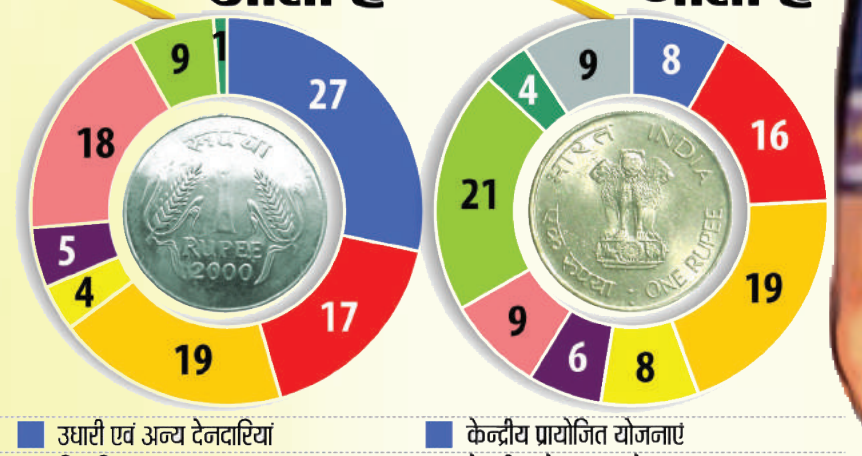


| आता है | | जाता है | |
|---|---|---|---|
| उधारी एवं अन्य देनदारियां | 27 | केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं | 8 |
| निगमित कर | 17 | केन्द्रीय योजना आयोजना | 16 |
| आयकर | 19 | ब्याज भुगतान | 19 |
| सीमाशुल्क | 4 | रक्षा | 8 |
| केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | 5 | आर्थिक सहायता | 6 |
| माल और सेवा कर | 18 | वित्त आयोद एवं अन्य अंतरण | 9 |
| गैर कर राजस्व | 9 | कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा | 21 |
| गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां | 1 | पेंशन | 4 |
| | | अन्य व्यय | 9 |

यह बजट सहयोगी दलों के तुष्टिकरण का बजट है। बजट में सहयोगियों को खुश करने के लिए अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए गए। अपने मित्रों को खुश किया गया, 'एए' को लाभ दिया गया, लेकिन आम भारतीय को कोई राहत नहीं दी गई।

–राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा

**32.7** लाख करोड़ बजट अनुमान, ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां

**4.9%** जीडीपी का वित्तीय घाटा इस बार देखा गया

### युवाओं को मिली उम्मीद

वित्त मंत्री ने कहा कि 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसर उपलब्ध कराने की योजनाओं और उपायों के लिए पांच साल की अवधि में दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का निर्धारण किया गया है। उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए मानक कटौती को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75,000 रुपये करने के साथ नई आयकर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के लिए कर स्लैब में बदलाव किया। इससे करदाताओं को नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 17,500 रुपये तक की बचत होगी। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में कंपनियों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया है। इसमें पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महीने के वेतन का भुगतान और रोजगार के पहले चार वर्षों में उनके सेवानिवृत्ति निधि अंशदान के संबंध में नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक का 'रिम्बर्समेंट' शामिल हैं। कौशल में सुधार के साथ छात्रों के लिए इंटर्नशिप के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाएगा।

**4.5%** से घाटे को अगले साल तक नीचे लाने का लक्ष्य

**25.83** लाख करोड़ सकल कर प्राप्ति

**12** लाख करोड़ (जीडीपी का 3.4%) का प्रावधान पूंजीगत व्यय के लिए

### बजट की प्राथमिकताएं

- खेती में उत्पादकता
- रोजगार और क्षमता विकास
- समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
- विनिर्माण और सेवाएं
- शहरी विकास
- ऊर्जा सुरक्षा
- अधोसरंचना
- नवाचार, शोध और विकास
- अगली पीढ़ी के सुधार

### ये सस्ता

जूता चप्पल, सोना-चांदी, अन्य कीमती धातु, कपडा, कैंसर औषधियां, एक्सरे उपकरण, मोबाइल फोन, चार्जर, मोबाइल फोन कल पुर्जे, सौर ऊर्जा के उपकरण, मछली, मछली चारा, प्राकृतिक ग्रेफाइट, प्राकृतिक रेत, धातु, दुर्लभ धातु, निकल, पोटेशियम, लिथियम, टिन, युद्धपोत उपकरण और कलपुर्जे, पशुओं की खाल शामिल है।

### ये मंहगा

महंगी होने वाली वस्तुओं में प्लास्टिक, पीवीसी- फ्लैक्स सीट, बडे छाते, प्रयोगशाला रसायन, भुना सूखे मेवा, सौर ऊर्जा ग्लास और टिन शामिल है।

**20%** प्रतिशत टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्ताव म्युचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुन : खरीद पर

**6%** सीमा शुल्क घटा सोने और चांदी पर, प्लेटिनम पर 6 .4 प्रतिशत



**1,000** करोड़ की उद्यम पूंजी निधि मिलेगी अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुणा बढ़ेगी



**50,000** रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक छूट करने का प्रस्ताव

**4.1** करोड़ युवाओं के लिए पांच साल में रोजगार

**2.78** हजार करोड़ रुपये की लागत से देश भर में बनाए जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग

**15** हजार रुपये तक के एक महीने का वेतन ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन राशि

**3** दवाइयां कैंसर की ट्रेस्टूजुमाब डिरूक्सटीकेन, ओसिमर्टिनिब और डुर्वालुमैब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट



**1.52** लाख करोड़ रुपये का आवंटन कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए



**15,000** से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती पर

# सीतारमण ने रिकॉर्ड सातवीं बार लगातार पेश किया बजट

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश कर दिया है। यह उनका रिकॉर्ड 7वां बजट था। वह लगातार 7 बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। उन्होंने मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं कीं। सफेद सिल्क साड़ी में वित्त मंत्री का बजट भाषण 1 घंटा और 25 मिनट तक चला। उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड भी बनाया था। आइए एक नजर उनके सभी बजट भाषणों समेत अन्य रिकॉर्ड पर डाल लेते हैं।

### पहला पेपरलेस बजट भी पेश कर चुकी हैं सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट साल 2019 में दिया था। उनका यह बजट भाषण पूरे 2 घंटे और 15 मिनट तक चला था। उसके अगले साल ही 2020 में बजट पेश करते हुए उन्होंने भारत के सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड बना दिया था। उस दौरान वित्त मंत्री 2 घंटे 42 मिनट तक बोली थीं। साल 2021 का बजट भाषण 1.40 मिनट का था। हालांकि, इसने भारत के पहले पेपरलेस बजट होने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2023 में निर्मला सीतारमण का बजट भाषण 1 घंटा और 30 मिनट चला था। इसके बाद इसी साल फरवरी में उन्होंने अंतरिम बजट के दौरान 57 मिनट का भाषण दिया था।

### मनमोहन सिंह ने बोले थे सबसे ज्यादा शब्द

भारत के इतिहास में शब्दों के हिसाब से सबसे लंबा बजट भाषण मनमोहन सिंह ने साल 1991 में दिया था। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान 18,700 वर्ड बोले थे। उनके ठीक बाद अरुण जेटली का नंबर आता है। उन्होंने 18,604 शब्दों में अपना बजट भाषण दिया था। देश का सबसे छोटा बजट सिर्फ 800 शब्दों का था। इसे साल 1977 में हीरूभाई एम पटेल ने पेश किया था। यह अंतरिम बजट था। निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषणों के जरिए देश के आर्थिक विकास के बदलते परिदृश्य का उल्लेख करती रही हैं।

## प्रदेश की विकास योजनाओं पर खर्च होगी रकम, पुरानी पेंशन बहाली न होने पर राज्य कर्मियों में निराशा

# उप्र को मिलेंगे 2.24 लाख करोड़

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

**अमृत विचार:** देश के आम बजट में इस बार प्रदेश को लगभग पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रकम की व्यवस्था की गई है। ये रकम प्रदेश की विकास योजनाओं पर खर्च होगी। रोजगार, औद्योगिक विकास, महिलाओं के उत्थान समेत विभिन्न योजनाएं तेजी से आगे बढ़ सकेंगी।

लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। इस बजट में केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 2.18 लाख करोड़ था जो इस बजट में बढ़कर 2.24 लाख करोड़ हो गया है। शासन के अधिकारियों के अनुसार बजट से सोलर पैनल, सोलर सेल, कैंसर की दवाएं, एक्सरे मशीन, मोबाइल फोन, चार्जर, इलेक्ट्रिक वाहन, चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स आदि सस्ते होंगे, इससे आम लोगों को सीधा फायदा होगा। बजट में ग्रामीण विकास के लिये 2.66 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर रू. 20 लाख की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिये 10 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे। 100 शहरों में या उसके आस-पास निवेश के लिए तैयार प्लग एण्ड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण शुरू होगा। बजट में राज्य कर्मियों के पुरानी पेंशन की घोषणा न किये जाने से कर्मियों में निराशा है। ऊर्जा क्षेत्र के वितरण क्षेत्र के विकास के लिए कोई रकम आवंटित नहीं की गई है।

### रोजगार को बढ़ावा देने को ईपीएफओ के जरिये तीन योजनाओं की घोषणा

नई दिल्ली। संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नये कामगारों के लिए ईपीएफओ के जरिए तीन योजनाओं की घोषणा की। रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गईं इन योजनाओं के लिए कुल केंद्रीय परिव्यय 1.07 लाख करोड़ रुपये है। ये योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार इससे जुड़ने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देंगी। इनसे कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया सभी संगठित क्षेत्रों में पहली बार ईपीएफओ की योजनाओं से जुड़ने वालों को योजना-क के तहत एक महीने का वेतन सरकार देगी। ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में एक महीने का वेतन दिया जाएगा, जो अधिकतम 15,000 रुपये तक होगा।

**100** शहरों में या उसके आस-पास निवेश के लिए तैयार प्लग एण्ड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित होंगे

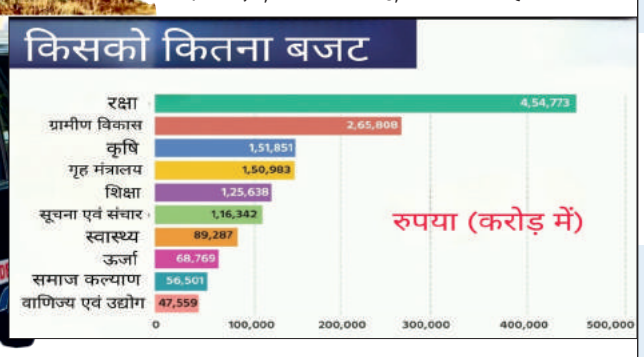


**32** कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी किसानों की खेतीबाड़ी के लिए

### इन बदलावों पर नजर जरूरी

- गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना
- 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से अगले पांच वर्ष में एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान
- 100 साप्ताहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता अगले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में
- विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा और राजगीर का व्यापक विकास।
- टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 60 लाख रुपये, दो करोड़ रुपये और पांच करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव
- सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3000 हजार रुपये हर महीना
- पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए नई योजना
- 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना
- सरकार की योजनाओं और नीतियों के तहत किसी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले युवाओं को घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण
- तीन साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने हेतु कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू किया जाएगा।
- अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास
- जनजातीय-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक-आर्थिक विकास के 63,000 गांवों के पांच करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोलना
- तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख
- इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध होगा बिहार में कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता
- सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता देगी
- ओडिशा के मंदिरों, स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभयारण्य, प्राकृतिक भू-दृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता।
- अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के वित्तीय पूल व्यवस्था
- सभी भू-खण्डों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) अथवा भू-आधार
- कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना वन स्टॉप समाधान के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोड़ना
- नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों के योगदान से एक योजना के रूप में एनपीएस वात्सल्य
- चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत एक्सरे ट्यूब और मेडिकल एक्सरे मशीनों में इस्तेमाल हेतु फ्लैट पैनल डिडेक्टरों पर मूलभूत सीमा शुल्क में बदलाव
- 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट
- सोलर सैल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली भारी वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से बाहर
- लौह, निकेल और ब्लिस्टर तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटा
- तांबा स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत रियायती मूलभूत सीमा शुल्क
- रेजिस्टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटा
- अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत
- प्लास्टिक पीवीसी फ्लैक्स बैनरों पर मूलभूत सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत
- दूरसंचार उपकरण के पी.सी.बी.ए. पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत
- फ्यूचर्स और ऑप्सन्स के विकल्पों पर सिक्यूरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

# नौकरीपेशा लोगों को राहत, मानक कटौती बढ़ाकर 75,000 रुपये

नई दिल्ली, एजेंसी

बजट में आयकर प्रावधानों में कुछ बदलावों की घोषणा करते हुए मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को राहत दी। मानक कटौती को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव बजट में रखा गया। इन घोषणाओं को नौकरीपेशा लोगों के हाथ में कुछ और पैसा देने की कोशिश माना जा रहा है। इससे खपत को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

सीतारमण ने कहा कि बजट में किये गये बदलावों से नई कर व्यवस्था अपनाने वाले कर्मचारियों को 17,500 रुपये तक की कर बचत हो सकती है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह पेंशनधारकों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये का भी प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 2023-24 में दो-तिहाई से अधिक व्यक्तिगत करदाताओं ने नई आयकर व्यवस्था को चुना है। पिछले वित्त वर्ष में 8.61 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किये गये। नई आयकर व्यवस्था के तहत कर के नए स्लैब एक अप्रैल, 2024 (आकलन वर्ष 2025-26) से प्रभावी होंगे। सीतारमण ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत तीन लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट मिलती रहेगी। प्रस्ताव के मुताबिक, तीन से सात लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत, सात से 10 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत और 10-12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत कर लगेगा। हालांकि, 12-15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर पहले की तरह 30 प्रतिशत कर लगता रहेगा। नई आयकर व्यवस्था के मौजूदा प्रावधानों के तहत तीन से छह लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाता है। जबकि छह से नौ लाख रुपये के बीच की आय पर 10 प्रतिशत कर लगता है। वहीं, नौ से 12 लाख रुपये और 12 से 15 लाख रुपये के बीच की आय पर क्रमशः 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत कर लगता है। 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगता है।

| नए टैक्स सिस्टम के तहत प्रस्तावित टैक्स स्ट्रक्चर इस प्रकार है | |
|---|---|
| इनकम | टैक्स |
| **3,00,000** तक की आय | कोई टैक्स नहीं |
| **3,00,001** से **7,00,000** तक | **3,00,000** से ज्यादा पर 5% टैक्स |
| **7,00,001** से **10,00,000** तक | **20,000 + 7,00,000** से ज्यादा पर 10% टैक्स |
| **10,00,001** से **12,00,000** तक | **50,000 + 10,00,000** से ज्यादा पर 15% टैक्स |
| **12,00,001 से 15,00,000** तक | **80,000 + 12,00,000** से ज्यादा पर 20% टैक्स |
| **15,00,000** से ज्यादा | **1,40,000 + 15,00,000** से ज्यादा पर 30% टैक्स |
| **मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर इस प्रकार है** | |
| इनकम | टैक्स |
| **3,00,000** तक की आय | कोई टैक्स नहीं |
| **3,00,001** से **6,00,000** तक | **3,00,000** से ज्यादा पर 5% टैक्स |
| **6,00,001** से **9,00,000** तक | **15,000 + 6,00,000** से ज्यादा पर 10% टैक्स |
| **9,00,001** से **12,00,000** तक | **45,000 + 9,00,000** से ज्यादा पर 15% टैक्स |
| **12,00,001** से **15,00,000** तक | **90,000 + 12,00,000** से ज्यादा 20% टैक्स |
| **15,00,000** से ज्यादा | **1,50,000 + 15,00,000** से ज्यादा पर 30% टैक्स |

### ये है टैक्स में राहत पाने का फॉर्मूला

नई दिल्ली। वित्त मंत्री ने आयकर में स्टैंडर्ड डिडक्शन मद में मिलने वाली 50 हजार रुपये की छूट की राशि को बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया है। यानी अगर किसी करदाता की सालाना आय 7 लाख 75 हजार रुपये तक है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपये घटाने के बाद उसकी आमदनी 7 लाख रुपये सालाना हो जाएगी। ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बजट से पहले की स्थिति में सालाना आमदनी 7,50,000 रुपये तक रहने पर ही करदाता को टैक्स देने से राहत मिलती थी। भले ही नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक की कमाई ही टैक्स फ्री है, लेकिन सात लाख तक कमाने वाले को भी टैक्स नहीं देना होता है। इसका कारण है इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 87ए के तहत मिलने वाली छूट। धारा 87ए के अनुसार, किसी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये होने पर उसे टैक्स में छूट दी जाएगी और उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।

**15%** मूलभूत सीमा शुल्क घटाया मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेम्बली (पीसीबीए) और मोबाइल चार्जर पर

**30** लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी

**5%** टीडीएस दर घट कर 2 प्रतिशत टीडीएस दर विभिन्न भुगतानों पर

**40%** से घटाकर 35% होगी विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर दर

**500** करोड़ से घटाकर 250 करोड़ की गई खरीददारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा

**3** लाख करोड़ का आवंटन महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए

**01** करोड़ किसानों को प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग के साथ दो वर्षों में देश में प्राकृतिक कृषि से जुड़ेंगे

श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया
विक्रम संवत 2081

लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, हल्द्वानी, अयोध्या व कानपुर से प्रकाशित

बुधवार, 24 जुलाई 2024
वर्ष 34, अंक 177, पृष्ठ 18
2 राज्य, 6 संस्करण
मूल्य 5 रुपये

# अमृत विचार

लखनऊ

एक सम्पूर्ण अखबार

www.amritvichar.com

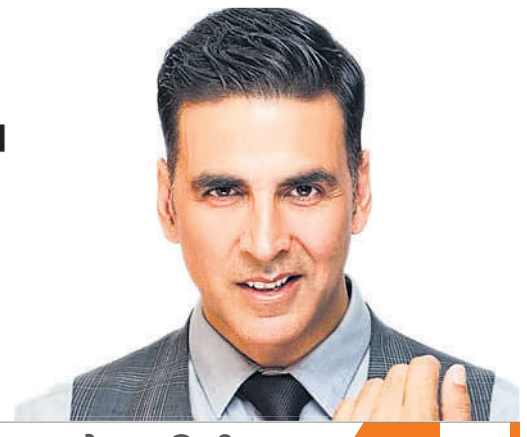

कनाडा में एक और मंदिर में तोड़फोड़ 16

फिल्म खेल-खेल में का मोशन पोस्टर रिलीज 15

# मोदी बोले- मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट, विपक्ष ने बताया नकलची

## प्रधानमंत्री मोदी ने कहा-भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में करेगा उत्प्रेरक का काम

नई दिल्ली, एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम बजट को नई उर्जा, बेहतर विकास और सुनहरे भविष्य के साथ ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर लेकर आने वाला बताया और कहा कि यह भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में 'उत्प्रेरक' का काम करेगा तथा विकसित भारत की ठोस नींव भी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए 2024-25 के बजट को उन्होंने समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला करार दिया और कहा कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन संबंधी योजना से देश में करोड़ों नए रोजगार पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेहतर वृद्धि (ग्रोथ) और सुनहरा भविष्य लेकर आया है। आज का बजट, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने और उस पूरी प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करेगा, विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है।

मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और इससे नया मध्यम वर्ग बना है, यह उनके सशक्तीकरण की निरंतरता का भी बजट है। उन्होंने कहा कि यह नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल (कौशल) को नई गति मिलेगी। यह मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है। यह जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और इससे छोटे व्यापारियों व लघु उद्योगों को प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसमें विनिर्माण और अवसंरचना विकास पर भी बल दिया गया है जिससे आर्थिक विकास को नयी गति मिलेगी और निरंतरता मिलेगी। रोजगार और स्वरोजगार के 'अभूतपूर्व' अवसर को अपनी सरकार की पहचान करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश में करोड़ों नए रोजगार उत्पन्न होंगे और जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह सरकार देगी। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर एक करोड़ नौजवानों को इंटेंसिव (प्रोत्साहन) की योजनाएं, इससे गांव के गरीब युवाओं को देश की शीर्ष कंपनियों में काम करने का अवसर मिलेगा, उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव में घर-घर उद्यमी बनाना है। बिना गारंटी मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए जाने का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि इससे छोटे कारोबारियों विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा।

### देशवासियों की आकांक्षाओं को सिद्ध करेगा बजट : योगी

**लखनऊ।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम बजट देशवासियों की आकांक्षाओं को सिद्ध करेगा। उन्होंने कहा कि यह रामराज की अवधारणा को साकार करेगा। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख, 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट आत्मनिर्भर व विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों की समृद्धि, कृषि व सहायक सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये और महिला सशक्तिकरण के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे सर्वाधिक लाभान्वित देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी होने वाली है।

### बजट में की गई उत्तर प्रदेश की उपेक्षा : अखिलेश यादव

**लखनऊ।** समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आम बजट में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार बचाने के लिए बिहार व आन्ध्र प्रदेश के विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। युवाओं को दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण व संविदा नौकरी को लेकर उन्होंने कहा कि युवाओं को एक-दो साल का प्रशिक्षण दिलाकर इस तरह की नौकरी के सपने दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस आधी-अधूरी नौकरी में आरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, उसके किसानों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? देश का नौजवान पक्की नौकरी चाहता है। जब तक किसान के मसले हल नहीं होंगे और नौजवानों की पक्की नौकरी नहीं होगी तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा।

### घटकों में रेवड़ी बांटकर कुर्सी बचाने का बजट : खरगे

**नई दिल्ली।** कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट 2024-25 को 'कुर्सी बचाए' रखने के लिए गठबंधन के सहयोगियों की बात मानकर उन्हें खुश करने वाला बजट करार दिया और कहा कि इसमें कांग्रेस के न्याय एजेंडे की नकल का विफल प्रयास किया गया है। खरगे ने कहा कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का यह 'नकलची बजट'। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी-अधूरी रेवड़ियां बाँट रहा है, ताकि राजग बची रहे। ये 'देश की तरक्की' का बजट नहीं, 'मोदी सरकार बचाओ' बजट है। गांधी ने कहा कि यह 'कुर्सी बचाओ' बजट है। सहयोगियों को खुश करें- अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे। अपने मित्रों को खुश करें- एए को लाभ, आमजन को कोई राहत नहीं। कॉपी और पेस्ट करें : कांग्रेस का घोषणापत्र और पिछले बजट।

## एक नजर

### तीन क्विंटल डोडा चूरा बरामद, दो तस्कर फरार

**उदयपुर।** राजस्थान में उदयपुर जिले के कानोड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार को एक स्कार्पियो गाड़ी से तीन क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस ने बताया कि कानोड लसाडिया मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान आई स्कार्पियो गाड़ी को रोक कर तलाशी ली। तलाशी में करीब तीन क्विंटल डोडा चूरा सहित स्कार्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया। दो तस्कर भागने में सफल हो गए।

### बलरामपुर में हाथियों का उत्पात, एक की मौत

**बलरामपुर।** छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हाथियों के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल है रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के बगरा गांव में सोमवार की रात राजा सिंह अपने दोस्त लक्ष्मण सिंह के साथ किसी कार्यक्रम से घर लौट रहे थे। इसी बीच दोनों का सामना हाथियों के दल से हो गया। राजा राम को हाथियों ने पटक-पटक कर मार डाला। वहीं लक्ष्मण सिंह को घायल कर दिया।

### मिसाइल परीक्षण से पहले 10 हजार लोग स्थानांतरित

**बालासोर।** ओडिशा के बालासोर प्रशासन ने बुधवार को किए जाने वाले मिसाइल परीक्षण से पहले 10 गांवों के 10,000 से अधिक लोगों को अस्थायी रूप से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। एक रक्षा सूत्र ने मंगलवार को यहां बताया कि डीआरडीओ ने चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) में मिसाइल परीक्षण के लिए आवश्यक तैयारी भी पूरी कर ली है।

# दोबारा नहीं होगी नीट-यूजी

## सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई परीक्षा को रद कर दोबारा कराने की गुहार

नई दिल्ली, एजेंसी

- अदालत ने कहा- जांच में नहीं मिले प्रश्नपत्रों के सार्वजनिक होने के सबूत
- दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश देना करीब 24 लाख छात्रों के लिए गंभीर परिणामों से भरा होगा

सुप्रीम कोर्ट ने स्नातक स्तर की मेडिकल एवं अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले से संबंधित 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 रद कर दोबारा आयोजित कराने की गुहार मंगलवार को ठुकरा दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग वाली याचिकाएं ठुकराते हुए कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़े प्रश्नपत्र के व्यवस्थित रूप से सार्वजनिक होने के संकेत नहीं देते हैं।

पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों की जांच में कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह पता चल सके की प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने समेत अन्य अनियमितताओं के पीछे परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की प्रणालिगत विफलता है।

पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों के आधार पर इस अदालत द्वारा प्रतिपादित स्थापित सिद्धांतों के आधार पर पूरी परीक्षा को रद करने का आदेश देना उचित नहीं है।

पीठ ने हालांकि कहा कि यदि जांच में में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि का पता चलने पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसी भी स्तर पर ऐसे किसी भी विद्यार्थी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी अभ्यार्थी इस धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है या लाभार्थी है, उसे नामांकन जारी रखने में किसी भी निहित अधिकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। पीठ ने कहा कि यह सच है कि नीट यूजी 2024 का प्रश्न पत्र हजारीबाग और पटना में सार्वजनिक हुआ था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि हजारीबाग और पटना के केवल 155 विद्यार्थी ही इसके (प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने और अन्य अनियमितताओं) के लाभार्थी थे।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए नए सिरे से नीट कराने का निर्देश देना इस परीक्षा में बैठने वाले करीब 24 लाख से विद्यार्थियों के लिए गंभीर परिणामों से भरा होगा। पीठ ने यह भी कहा कि दाखिले के कार्यक्रम में व्यवधान से भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर प्रभाव समेत अन्य पहलुओं पर विचार करने के बाद फैसला दिया गया। पीठ ने कहा कि नीट परीक्षा 05 मई को आयोजित की गई थी और परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे। परीक्षा में लगभग 23 लाख 33 हजार अभ्यर्थी उपस्थित हुए। मेडिकल स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए 1.08 लाख सीटें हैं, जिनमें से 56000 सीटें सरकारी कॉलेजों में और बाकी निजी संस्थानों में हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र और एनटीए का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्परा सहित अन्य की दलीलें चार दिनों तक सुनने के बाद फैसला सुनाया।

### विपक्ष ने अराजकता पैदा करने का प्रयास किया : प्रधान

**नई दिल्ली।** केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को विपक्ष पर नीट-यूजी मुद्दे का इस्तेमाल कर अराजकता एवं अशांति पैदा करने के प्रयास का आरोप लगाया और कहा कि विवादों में घिरी परीक्षा से संबंधित उच्चतम न्यायालय के फैसले से सत्य की जीत हुई। प्रधान ने कहा कि विपक्ष को छात्रों और उनके अभिभावकों को गुमराह करने के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) दो दिनों में नीट-यूजी के अंतिम परिणाम घोषित करेगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा की मेधा सूची में शीर्ष अदालत की टिप्पणियों के अनुसार संशोधन किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी 2024 के असफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए मंगलवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें विवादों में घिरी इस परीक्षा को रद कर दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई थी।

### फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 20 लोग गिरफ्तार

**नई दिल्ली।** दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है और सरकारी योजनाओं के तहत ऋण मुहैया कराने के बहाने लोगों को ठगने के आरोप में नौ महिलाओं सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अंकित चौहान ने मंगलवार को कहा कि अनुमान है कि 400 से अधिक पीड़ित कॉल सेंटर की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, जिसके कारण कुल 40 लाख रुपये की ठगी हुई है। पुलिस पहले ही देश भर में 50 से अधिक पीड़ितों की पहचान कर चुकी है। डीसीपी ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली के लाडो सराय इलाके से संचालित यह फर्जी कॉल सेंटर सरकारी योजनाओं के तहत लोन दिलाने के नाम पर लोगों को ठगता था। डीसीपी ने बताया कि वे एकत्रित किए गए विवरणों का इस्तेमाल अपने खातों में पैसे हस्तांतरित करने के लिए करते थे। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को नौ महिला टेली-कॉलर्स समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया गयाा है और उनके पास से कुल 32 मोबाइल फोन, 48 फर्जी सिम कार्ड, चार लैपटॉप और 23 बैंक खाते जब्त किए गए, जांच जारी है।

- सरकारी योजनाओं में ऋण दिलाने के बहाने ऐंठते थे रुपये

# बजट में रेलवे के लिए दो लाख 65 हजार 200 करोड़ का प्रावधान

नई दिल्ली, एजेंसी

- रेल संरक्षा पर खर्च होंगे एक लाख आठ हजार करोड़ रुपये : वैष्णव

रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि के बीच आए आम बजट में रेलवे के पूंजीगत आवंटन में एक लाख आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक संरक्षा के लिए व्यय करने का प्रस्ताव किया गया है। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को मीडिया को बजट प्रस्तावों की जानकारी देते हुए कहा कि बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड दो लाख 65 हजार 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जबकि वर्ष 2014 में रेलवे के लिए पूंजीगत आवंटन 35 हजार करोड़ रुपये के आसपास रहता था। उन्होंने कहा कि इस दो लाख 65 हजार 200 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय में से एक लाख आठ हजार 795 करोड़ रुपये संरक्षा के मद में खर्च किए जाने हैं। संरक्षा के मद में पुरानी रेल पटरियों को बदलना, कवच का नया 4.0 संस्करण लगाना, इंजन एवं कोचों के अनुरक्षण, ओवरब्रिज और अंडरपास बनाने आदि में यह धनराशि खर्च की जाएगी।

वैष्णव ने कहा कि रेलवे गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों की सवारी है। इसलिए जनरल एवं गैर एसी स्लीपर कोचों की मांग बढ़ी है। पूंजीगत व्यय से करीब 10 हज़ार जनरल एवं गैर एसी स्लीपर कोचों के उत्पादन किया जाएगा। कवच के नए संस्करण के बारे में उन्होंने कहा कि कवच 4.0 में भारतीय रेलवे के सभी तरह की प्रणालियों को समाहित करते हुए नया साफ्टवेयर बनाया गया है। जिसे दो तीन पहले ही आरडीएसओ लखनऊ से स्वीकृति हासिल हुई है। अब इसको तेजी से बड़े पैमाने पर उत्पादन करके अधिक से अधिक लाइनों पर लगाया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि रोज़गार की दृष्टि से देखें तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के 10 साल के शासनकाल में चार लाख 16 हजार नियुक्तियां हुईं थीं जबकि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में पांच लाख से अधिक लोगों को रेलवे की नौकरी मिली है। इस वर्ष भी 38 से 40 हजार लोगों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

### युवक थाईलैंड में बंधक 22 लाख फिरौती मांगी

**प्रयागराज।** जिले के एक युवक को थाईलैंड में बंधक बना लिया गया है। परिजनों का कहना है कि करीब दस दिनों से बेटे से बात नहीं हुई है। 22 जुलाई को युवक के फोन से 22 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई। रुपये डॉलर में ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए कहा है। अब युवक का फोन बंद है। परिजनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय व गृह मंत्रालय को पत्र लिखने के अलावा विदेश मंत्रालय से युवक को वापस लाने की गुहार लगाई है।

- पांच अन्य भारतीयों को बनाया गया बंधक

मामला विदेश से जुड़ा है। परिवार वालों से बातचीत कर जो भी उचित होगा किया जाएगा। -पुष्कर वर्मा, एसीपी प्रयागराज

प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र के दरियाबाद निवासी जिया पंजतन (26) दुबई की एक कंपनी में काम करता था। उसके साथ देश के अन्य चार युवक भी थे। जिया पंजतन और अन्य युवक दुबई से थाईलैंड के लिए 10 जुलाई को इंडिगो की फ्लाइट से गए थे। आखिरी बार उनकी 13 जुलाई को परिजनों से बात हुई थी। इसके बाद से जिया का संपर्क टूट गया। घरवालों का कहना है कि युवकों को बैंकॉक के एक मकान में बंधक बनाकर रखा गया है। जिया की बहन कनीज ने कहा- 22 जुलाई को भाई ने मुझे वॉट्सएप पर कॉल किया कि मुझे बंधक बना लिया गया है। ये लोग मुझसे 22 लाख रुपये डॉलर के रूप में मांग रहे हैं। मेरी तरह 5 लड़के यहां बंधक हैं। 23 जुलाई तक का समय दिया है। कनीज ने विदेश मंत्रालय और पीएमओ को ई-मेल के जरिए बेटे को छुड़ाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा है। जिया के बड़े भाई बक्शीश दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।

# जीएम फसलों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी

- अनुवांशिक रूप से संवर्धित सरसों पर रोक संबंधी याचिका पर दो जजों की पीठ का खंडित फैसला
- जीएम फसलों को पर्यावरण में छोड़े जाने संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सरसों की संकर (हाइब्रिड) किस्म डीएमएच-11 को बीज उत्पादन और परीक्षण के लिए पर्यावरण में छोड़ने के केंद्र सरकार के वर्ष 2022 के फैसलों की वैधता पर मंगलवार को खंडित फैसला सुनाया। हालांकि, दो जजों की पीठ ने आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का केंद्र को एकमत से निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने जीएम सरसों को पर्यावरण में छोड़े जाने की सिफारिश करने के जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) के 'ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड डीएमएच-11' को पर्यावरण में छोड़े जाने संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। जीईएसी आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) जीवों के लिए देश की नियामक संस्था है। इस मामले में दलीलें सुनने के बाद पीठ ने अलग-अलग राय दी। पीठ ने इस मामले को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखे जाने का निर्देश दिया, ताकि कोई दूसरी पीठ इस पर फैसला दे सके। हालांकि, दोनों न्यायाधीशों ने आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का केंद्र को एकमत से निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय जीएम फसलों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने से पहले सभी हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श करे और यदि इस प्रक्रिया को चार महीने में पूरा कर लिया जाए, तो बेहतर रहेगा। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने जीएम फसलों को पर्यावरण में छोड़े जाने के मुद्दे पर कहा कि 18 और 25 अक्टूबर, 2022 को दिए गए जीईएसी के निर्णय दोषपूर्ण थे, क्योंकि बैठक में स्वास्थ्य विभाग का कोई सदस्य नहीं था और कुल आठ सदस्य अनुपस्थित थे। दूसरी ओर, न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि जीईएसी के फैसले किसी भी तरह से मनमाने और गलत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जीएम सरसों फसल को सख्त सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए पर्यावरण में छोड़ा जाना चाहिए।

### यूट्यूबर एल्विश यादव ईडी के समक्ष पेश हुआ

**लखनऊ।** यूट्यूबर एल्विश यादव मंगलवार को लखनऊ स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय पहुंचा। एजेंसी ने उससे धनशोधन मामले के साथ ही कई मुद्दों पर पूछताछ की। एल्विश ने कहा कि मुझे जो कहना था, मैं पहले ही कह चुका हूं। जो मुझसे मांगा गया था, मैं उसे दे चुका हूं। अब हर उस सवाल का जवाब दूंगा, जो मुझसे पूछा जाएगा। ईडी ने बीती 10 जुलाई को यूट्यूबर को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन एल्विश ने ईडी से मोहलत मांगी थी।

यूट्यूबर एल्विश यादव लंबे समय से स्नैक वेनम (सांप का जहर) मामले को लेकर सुर्खियों में है। उसे पुलिस एक बार गिरफ्तार भी कर चुकी है। ईडी ने भी एल्विश को बीती 10 जुलाई को नोटिस जारी किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। मीडिया के सवाल पर एल्विश ने कहा कि मैं यूके गया था, जिसके कारण पेश नहीं हो पाया।

- कहा, यूके में था इसलिए 10 जुलाई को नहीं पहुंच सका

# पुंछ में घुसपैठ की कोशिश हाथरस के सुभाष शहीद

जम्मू, एजेंसी

- सेना के जवानों ने ध्वस्त किए आतंकियों के मंसूबे

जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार तड़के नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया, जिस दौरान एक जवान शहीद हो गया। सेना की 'व्हाइट नाइट कोर' ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि सतर्क सैनिकों ने तड़के तीन बजे बट्टल सेक्टर में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों की गोलीबारी का माकूल जवाब देकर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। कोर ने कहा कि भारी गोलीबारी के दौरान एक वीर जवान घायल हो गया। अभियान जारी है।

सूत्रों के अनुसार, सैनिकों को कृष्णाघाटी के बट्टल अग्रिम क्षेत्र में आतंकवादियों के समूह की गतिविधियों का पता चला और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सूत्रों ने बताया कि हाथरस (यूपी) के निवासी लांस नायक सुभाष कुमार भीषण मुठभेड़ में घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सैनिक का पार्थिव शरीर पोस्टमॉर्टम के बाद सेना को सौंप दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है। हाल के महीनों में जम्मू में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे क्षेत्र में आतंकवाद के फिर से सिर उठाने की आशंका बढ़ गई है।

**सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी**

### असाधारण परिस्थितियों में ही बेल पर लगाएं रोक

**नई दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अदालतों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जमानत आदेश पर रोक लगानी चाहिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए यह बात कही, जिसमें धन शोधन के एक मामले में एक आरोपी की जमानत पर रोक लगाई गई थी। पीठ ने कहा कि हालांकि, अदालत के पास जमानत पर रोक लगाने का अधिकार है, लेकिन ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि अदालतों को यांत्रिक तरीके से और बिना कोई कारण बताए जमानत आदेश पर रोक लगाने से बचना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह फैसला धन शोधन के एक मामले में आरोपी परविंदर सिंह खुराना की याचिका पर सुनाया।

- शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को किया खारिज

# शोध और टिकाऊ खेती को मिलेगा प्रोत्साहन

## कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन, 32 फसलों की 109 नई उच्च उपज देने वाली किस्में लाई जाएंगी

नई दिल्ली, एजेंसी

### किसानों के लिए सरकार का तोहफा

- देश के 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण होगा
- रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार होगी
- प्राकृतिक खेती के लिए एक करोड़ किसानों को किया जाएगा समर्थन



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि अनुसंधान, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने, तिलहन और दलहन उत्पादन को बढ़ाने और कृषि परिदृश्य में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। सीतारमण ने उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-सहिष्णु फसल किस्मों को विकसित करने के लिए कृषि अनुसंधान ढांचे की गहन समीक्षा पर बल दिया।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार कृषि अनुसंधान 'सेटअप' की व्यापक समीक्षा करेगी। शोध निधि चुनौती-आधारित होगी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खुली होगी। सीतारमण ने घोषणा की कि किसानों की जल्द ही 32 खेत और बागवानी फसलों में 109 नई उच्च उपज वाली, जलवायु-सहिष्णु किस्मों तक पहुंच होगी। महत्वपूर्ण फसलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, मंत्री ने दलहन और तिलहन पर केंद्रित मिशन की योजनाओं का खुलासा किया। सीतारमण ने कहा कि अंतरिम बजट में घोषित की गई रणनीति के अनुसार, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए 'आत्मनिर्भरता'हासिल करने के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है। अनुसंधान और फसल विविधीकरण पर सरकार का जोर टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ आता है। सीतारमण ने अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के तहत लाने की पहल की घोषणा की, जिसे प्रमाणन और ब्रांडिंग प्रयासों द्वारा समर्थित किया जाएगा। इस क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने तीन वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करते हुए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू करने की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। इस पहल में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और किसान और भूमि रजिस्ट्री का निर्माण शामिल है। सीतारमण ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सरकार 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करके खरीफ मौसम के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण करेगी। छह करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा।

बजट में प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित करने, आपूर्ति श्रृंखला में किसान-उत्पादक संगठनों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रावधान भी शामिल हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सीतारमण ने झींगा मछली उत्पादन और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। उन्होंने कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीचेट वर्म, झींगा और मछली चारे पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर पांच प्रतिशत करने तथा झींगा एवं मछली चारे के निर्माण के लिए विभिन्न आदानों पर सीमा शुल्क में छूट देने का भी प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने सहकारी क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति की योजनाओं का खुलासा किया। इसके अतिरिक्त, पांच राज्यों में जन समर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने को सक्षम किया जाएगा।

## एक नजर में

(करोड़ रुपयों में)

| | 2022-23 वास्तविक (अनंतिम) | 2023-24 बजट अनुमान | 2023-24 संशोधित अनुमान | 2023-24 Provisional Actuals | 2024-25 बजट अनुमान |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व प्राप्तियां | 2383206 | 2632281 | 2699713 | 2728412 | 3129200 |
| पूंजी प्राप्तियां | 1809951 | 1870816 | 1790773 | 1714130 | 1691312 |
| कुल प्राप्तियां | 4193157 | 4503097 | 4490486 | 4442542 | 4820512 |
| राजस्व लेखा | 3453132 | 3502136 | 3540239 | 3494036 | 3709401 |
| आयोजना व्यय | 740025 | 1000961 | 950246 | 948506 | 1111111 |
| पूंजीगत लेखा | 4193157 | 4503097 | 4490486 | 4442542 | 4820512 |
| राजस्व घाटा | 1069926 | 869855 | 840527 | 765624 | 580201 |
| राजकोषीय घाटा | 1737755 | 1786816 | 1734773 | 1653670 | 1613312 |
| प्राथमिक घाटा | 809238 | 706845 | 679346 | 589799 | 450372 |

पीटीआई ग्राफिक

# महिला हॉस्टल और बनेंगे क्रेच

नई दिल्ली, एजेंसी

### महिलाओं के लिए तीन लाख करोड़ का आवंटन



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिला-नीत विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के तहत महिलाओं और लड़कियों से संबंधित योजनाओं के वास्ते तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि यह (आवंटन) आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता का द्योतक है। उन्होंने कहा कि महिला-नीत विकास को बढ़ावा देने के मद्देनजर महिलाओं और लड़कियों से संबंधित लाभकारी योजनाओं के वास्ते बजट में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। सीतारमण ने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करेगी। बजट की मुख्य विशेषताओं में से एक है, औद्योगिक समूहों के साथ साझेदारी में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना और कामकाजी माताओं की सहायता के वास्ते क्रेच की स्थापना करना।

इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं के लिए कार्यस्थल और घर के बीच संतुलन को बढ़ाना है। बजट से यह पता चलता है कि नियोजन संबंधी हालिया आंकड़ों के अनुसार, कामकाजी महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मई 2024 तक लगभग 2.40 लाख नई महिला सदस्य जुड़ी हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में कामकाजी महिला सदस्यों की संख्या में 17.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो अधिक समावेशी कार्यबल की ओर सकारात्मक बदलाव का संकेत है।

# 7वीं बार पेश किया बजट प्रधानमंत्री ने दी बधाई

नई दिल्ली, एजेंसी

- 83 मिनट का बजट भाषण दिया रोजगार सृजन पर रहा जोर
- 71 बार सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर किया स्वागत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में अपना 7वां केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया और जब उन्होंने लाल रंग के बही-खाते जैसे कवर में रखे टैबलेट से अपना बजट भाषण पढ़ा तो आधुनिकता के साथ परंपरा का मिश्रण देखने को मिला। बैंगनी-सुनहरे रंग की किनारी वाली क्रीम रंग की मैसूर सिल्क साड़ी पहने सीतारमण ने अपने बजट भाषण में रोजगार सृजन पर अधिक जोर दिया।

इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से बार-बार मेज थपथपाई गई तो विपक्ष की ओर से बीच-बीच में नारेबाजी भी हुई। सीतारमण ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर बजट भाषण दिया और उनके बिल्कुल पास में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बैठे थे। वित्त मंत्री के 83 मिनट के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कम से कम 71 बार मेजें थपथपाकर बजटीय घोषणाओं का स्वागत किया। सीतारमण ने जब बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाओं की जानकारी सदन में दी तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा किया। बिहार में जदयू और आंध्र प्रदेश में सत्तासीन तेदेपा राजग के प्रमुख सहयोगी दल हैं। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने 'सरकार को बचाने वाला बजट' और 'सरकार बचाओ, कुर्सी बचाओ बजट' के नारे लगाए।

लोकसभा में पूर्वाह्न 11 बजे बजट भाषण शुरू होने से कुछ मिनट पहले जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में पहुंचे तो भाजपा के सांसदों ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। इस पर विपक्षी सदस्य 'जय संविधान' के नारे लगाते सुने गए। बजट भाषण पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वित्त मंत्री सीतारमण के पास आकर उन्हें बधाई दी।

### आज संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगा इंडी गठबंधन

**नई दिल्ली।** कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर मंगलवार को इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई जिसमें बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि बजट पर चर्चा के दौरान नेताओं ने कहा कि बजट में देश के तीन-चौथाई हिस्से को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि कल हम संसद के बाहर इसके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करेंगे और संसद के अंदर भी इस मुद्दे को लोकतांत्रिक तरीक़े से उठाएंगे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह भारत सरकार का बजट है, लेकिन इसे ऐसे पेश किया गया जैसे कि बीजेपी का बजट हो।

# रक्षा क्षेत्र के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपये आवंटित

नई दिल्ली, एजेंसी

**2023-24** के आवंटन की तुलना में 4.79 प्रतिशत अधिक

**1,72,000** करोड़ रुपये रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए

सरकार ने मंगलवार को 2024-25 में रक्षा व्यय के लिए 6,21,940 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के साथ-साथ रणनीतिक जलमार्गों में उभरती सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंताओं के बीच अंतरिम बजट में आवंटित की गई राशि के लगभग बराबर ही है। फरवरी में पेश अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन 6,21,540 करोड़ रुपये था। रक्षा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन 2023-24 में किए गए बजटीय प्रावधान की तुलना में 4.79 प्रतिशत अधिक है।

पूंजीगत व्यय के लिए सेना को 1,72,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे जिसमें मुख्य रूप से नए आयुध, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद शामिल है। दैनिक परिचालन लागत और वेतन के लिए राजस्व व्यय 2.82 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि रक्षा पेंशन के लिए 1,41,205 करोड़ रुपये चिह्नित किए गए हैं, जो 2023-24 में किए गए आवंटन से 2.17 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा क्षेत्र का कुल बजट भारत सरकार के कुल बजट का 12.9 प्रतिशत है। पूंजीगत परिव्यय पर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, घातक हथियार, लड़ाकू विमान, जहाज, पनडुब्बियां, प्लेटफॉर्म, मानव रहित वायु यान, ड्रोन, विशेषज्ञ वाहन आदि से लैस करने के उद्देश्य से होने वाले पूंजी अधिग्रहणों पर वार्षिक नकद व्यय की जरूरत को पूरा करेगा।

### गृह मंत्रालय को 2.19 करोड़, बड़ा हिस्सा केंद्रीय बलों को

केंद्रीय बजट 2024-25 में गृह मंत्रालय के लिए 2,19,643 .31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें 1,43,275 .90 करोड़ रुपये का बड़ा हिस्सा सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों के लिए चिह्नित है। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में गृह मंत्रालय को 2,02,868 .70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वर्तमान में केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। बजट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 5,985 .82 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 5,862 .62 करोड़ रुपये, लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये और दादरा नगर हवेल तथा दमन दीव को 1,490 .10 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

### रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भरता और गति मिलेगी : राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घरेलू पूंजी खरीद के लिए 1,05,518 करोड़ रुपये का आवंटन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और गति प्रदान करेगा। सिंह ने 'एक्स' पर लिखा कि मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 6,21,940 .85 करोड़ रुपये के सर्वाधिक आवंटन के लिए धन्यवाद देता हूं जो 2024-25 के लिए सरकार के कुल बजट का 12 .9 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि 1,72,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518 .43 करोड़ रुपये का प्रावधान आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देगा। कहा कि कि सीमा सड़क संगठन के लिए पूंजीगत मद में पिछले बजट की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक आवंटन किया गया है।



# स्वास्थ्य पर खर्च होंगे 90,958.63 करोड़ रुपये

**नई दिल्ली।** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 2024-2025 के बजट में 90,958.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान 80,517.62 करोड़ रुपये से 12.96 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने कैंसर के उपचार की तीन दवाओं - ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब पर सीमा शुल्क में छूट की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत मेडिकल एक्स-रे मशीनों में उपयोग के लिए एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बीसीडी (मूल सीमाशुल्क) में भी बदलाव का प्रस्ताव करती हूं। आयुष मंत्रालय के लिए बजट आवंटन को 3,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,712.49 करोड़ किया गया है।

# उच्च शिक्षा लिए 10 लाख रुपये तक मिलेगा ऋण

नई दिल्ली, एजेंसी



- यूजीसी के आवंटन में 60 प्रतिशत से अधिक की कटौती

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हालांकि उच्च शिक्षा नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिए अनुदान 60 प्रतिशत से अधिक घटा दिया गया है।

केंद्रीय बजट के अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के लिए आवंटन में भी लगातार दूसरे वर्ष कटौती की गई है। स्कूल शिक्षा के लिए बजट 535 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ाया गया है लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अनुदान पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान (आरई) से 9,600 करोड़ रुपये से अधिक कम हो गया। शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट आवंटन में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की कटौती की गई है। केंद्र ने 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय को 1.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान 1.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर दिए जाएंगे, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।

# एक करोड़ शहरी आवास के लिए दस लाख करोड़ रुपये

**नई दिल्ली।** केंद्रीय बजट में आवास योजना शहरी 2.0 के तहत दस लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ आवासों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के तहत शहरी आवास के विकास के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक कामगारों के लिए पीपीपी मोड में डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं एवं सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने अगले पांच साल में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक 'बाजार' के विकास में सहायता के लिए एक योजना की परिकल्पना की है।

# रोजगार के लिए दो लाख करोड़, शुरू होंगी 3 योजनाएं

नई दिल्ली, एजेंसी

### पहली नौकरी पर ईपीएफओ में तीन किस्त में 15 हजार जमा कराए जाएंगे



- टॉप-500 कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप का अवसर, पांच हजार प्रतिमाह भत्ता, 6 हजार की एकमुश्त मदद

### एक करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने को महत्वाकांक्षी योजना

**नई दिल्ली।** युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पांच साल की अवधि में 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए मंगलवार को एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस योजना के तहत युवाओं को 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। सीतारमण ने कहा, प्रधानमंत्री के पैकेज की पांचवीं योजना के तौर पर हमारी सरकार पांच साल में 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी। इन युवाओं को 12 महीने तक वास्तविक कारोबारी परिवेश, विविध व्यवसायों और रोजगार के अवसरों का अनुभव मिलेगा। कंपनियां अपनी सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व)निधि से प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10 प्रतिशत वहन करेंगी। कंपनी अधिनियम 2013 के मुताबिक, लाभ में चल रही कंपनियों के लिए किसी वित्त वर्ष में तीन साल के शुद्ध लाभ का कम-से-कम दो प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना जरूरी होता है।

वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में रोजगार सृजन, कौशल विकास और अन्य अवसरों के लिए दो लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में कहा कि अगले पांच वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में दो लाख करोड़ रुपये के आवंटन से रोजगार के लिए तीन योजनाएं शुरु होंगी। इनसे तीन करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। इनमें तीन योजनाओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से लागू किया जाएगा। ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह के वेतन का 15 हजार रुपये तक की तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार पाने के पहले चार वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्ष तक उनके प्रतिमाह तीन हजार रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। योजना में सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए कामगार के रूप में शामिल होने वाले सभी नवनियुक्त व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा।

ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तीन किस्तों में किया जाएगा, जो अधिकतम 15,000 रुपये होगा। इस योजना के अंतर्गत पात्रता सीमा एक लाख रुपये का मासिक वेतन होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से 2.1 करोड़ युवाओं के लाभान्वित होने की आशा है। इस योजना से पहली बार रोजगार पाने वाले 30 लाख युवा और उनके नियोक्ता लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि नियोक्ताओं पर केंद्रित इस योजना में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा। एक लाख रुपये प्रतिमाह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी। सरकार, प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें दो वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से 50 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

# बजट 48.21 लाख करोड़

## 16.13 लाख करोड़ की व्यवस्था उधार से

### राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.9% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के बजट में कुल 48.21 लाख करोड़ के व्यय का अनुमान लगाया है और राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.9% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। फरवरी में पेश अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया था। पिछले वित्त वर्ष में, संशोधित अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा 5.6 प्रतिशत था। बजट निर्माण में वित्त वर्ष 2024-25 में चालू कीमतों पर जीडीपी में 10.50 की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

नई दिल्ली, एजेंसी

संसद सत्र के दौरान पेश बजट पत्रों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 3,26.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 2023-24 के 2,95.36 लाख करोड़ की तुलना में 10.50 प्रतिशत अधिक है। बजट अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़, कर-भिन्न प्राप्तियां 5.46 लाख करोड़ तक रहेंगी तथा पूंजी प्राप्तियां 16.91 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

पूंजी गत प्राप्तियों में उधार और अन्य देयताओं के मद में प्राप्तियां 16.13 लाख करोड़ अनुमानित हैं। विनिवेश से 50 हजार करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है, जो अंतरिम बजट के बराबर है। पिछले वित्त वर्ष में विनिवेश से 33122 करोड़ प्राप्त हुए थे। चालू वित्त वर्ष में सरकार के कुल 4820512 करोड़ के अनुमानित व्यय में राजस्व खाते पर व्यय 3709401 करोड़, ब्याज भुगतान पर 1162940 करोड़ तथा पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदानों पर 3.91 लाख करोड़ के व्यय का प्रावधान है। प्रस्तावों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.9 प्रतिशत के रहेगा। सरकार की वित्तीय स्थिति को और मजबूत बनाने की राह पर आगे और प्रगति का विश्वास जताते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।

उन्होंने कहा चालू वित्त वर्ष में सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से बाजार से सकल 14.01 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटायेगी। वर्ष के दौरान जुटाया गया कर्ज शुद्ध रूप में 11.63 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि 2021 में उन्होंने राजकोष को मजबूत बनाने की जो वृहद योजना प्रस्तुत की, उससे अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी सेवा हुई है, और सरकार अगले वर्ष घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य रखेगी।

## सरकारी खजाने में 15 हजार करोड़ का इजाफा



**नई दिल्ली।** राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को कहा कि बजट में पूंजीगत लाभ कर की दरों में प्रस्तावित बदलाव से सरकारी खजाने को 15,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने बजट में पूंजीगत लाभ कर को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया। साथ ही प्रतिभूति और अचल संपत्ति समेत विभिन्न संपत्तियों को अपने पास रखने की अवधि को तर्कसंगत बनाया गया है। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर के लिए सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को एक वर्ष से अधिक समय तक जबकि असूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों तथा सभी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों को कम से कम दो वर्षों तक रखना होगा। विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें गैर-सूचीबद्ध बॉण्ड तथा डिबेंचर शामिल नहीं है उसमें मौजूदा स्लैब दरें लागू होंगी। सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद कहा कि सरकार कराधान व्यवस्था को सरल बनाना चाहती है। सीतारमण ने कहा कि औसत कराधान घटकर 12.5 प्रतिशत रह गया है... हम इसे न्यूनतम स्तर पर ले आए हैं जिससे बाजार में निवेश को बढ़ावा मिला है।



## सरकार ने भेदभाव के बिना सभी राज्यों को दी राशि

नई दिल्ली, एजेंसी

- सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ की सहायता का वादा, 50 वर्षों तक बिना ब्याज के रुपये देने का प्रावधान
- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना का प्रस्ताव रखा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष की इस आलोचना को खारिज कर दिया कि सरकार ने बजट में उन राज्यों को विशेष सुविधा दी है, जहां उसके सहयोगी दलों की सरकार हैं। उन्होंने कहा कि जिनके गठबंधन को 230 से सीटें मिली हैं, उन्हें इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि केंद्र ने सभी राज्यों को धन मुहैया कराया है। बिहार के लिए घोषित करोड़ की परियोजनाओं और आंध्र प्रदेश के लिए, बहुपक्षीय सहायता उपलब्ध कराने के वादे पर उन्होंने कहा कि बजट में सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की सहायता का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व गठबंधन के साथ, हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आराम से सरकार बनाई है। यह ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल में विकास के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिसमें राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज के 1.50 लाख करोड़ रुपये देने का प्रावधान शामिल है। यह वित्त आयोग की सिफारिश से अलग है। बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना का प्रस्ताव रखा गया है।

## पूंजीगत व्यय 15.02 लाख करोड़ रुपये तक

पूंजीगत व्यय के लिये राजस्व खाते से दिए अनुदानों को जोड़ें तो वर्ष के दौरान प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.02 लाख करोड़ तक रहेगा। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 16.13 लाख करोड़ (जीडीपी के 4.9% के बराबर) रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष, संशोधित अनुमानों में 16.54 लाख करोड़ (जीडीपी के 5.6%) के बराबर था। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले पांच साल तक अवसंरचना विकास को अपना ठोस समर्थन बनाये रखेगी। बजट में राज्यों को अवसंरचना विकास के लिये 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋण का प्रावधान किया गया है। बजट में केंद्र सरकार को करों से शुद्ध प्राप्ति प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में ग्रामीण इलाकों में 25,000 छोटी बस्तियों तक सड़क पहुंचाने का लक्ष्य है।



## आम आदमी के हितों पर दिया गया ध्यानः उद्योग जगत

**नई दिल्ली।** उद्योग जगत ने बजट 2024-25 को आम आदमी के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजकोषीय मजबूती के मार्ग पर अग्रसर बताने के साथ ही कहा कि इसमें भारतीय निवेशकों के लिए कुछ और कदम उठाए जा सकते थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज (इंडिया) के चेयरमैन अशोक हिंदुजा ने कहा कि बजट से पता चलता है कि मोदी सरकार का इस कार्यकाल में लक्ष्य राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की राह पर आगे बढ़ना है। कृषि क्षेत्र और किफायती एवं शहरी आवासीय अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करना ठोस कदम है और यह एक शुभ संकेत है। आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने कहा कि वित्त मंत्री ने आम आदमी के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए टीम इंडिया के लिए मैच जीतने वाला बजट पेश किया। उद्योग मंडल सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि यह बजट समावेश के साथ वृद्धि तेज करने के लिए भारत की सफल समग्र आर्थिक रणनीति को निरंतरता प्रदान करता है।

# बजट में बिहार को मिले 60,000 करोड़



**नई दिल्ली।** केंद्रीय बजट में मंगलवार को बिहार के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। इनमें राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया। इनमें तीन एक्सप्रेसवे, एक बिजली संयंत्र, विरासत गलियारों, नए हवाई अड्डे एवं खेल बुनियादी ढांचे के लिए योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन सड़क संपर्क परियोजनाओं - पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, तथा बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेसवे और बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त दो-लेन पुल के विकास के लिए केंद्र के समर्थन की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि इन चार परियोजनाओं की कुल लागत 26,000 करोड़ रुपये होगी। बिहार के लिए अन्य सौगातों में भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित करना शामिल है, जिसपर 21,400 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। इसके अलावा, केंद्र बिहार की बाढ़ में भी मदद करेगा। बिहार नेपाल से निकलने वाली कई नदियों की बाढ़ से अक्सर पीड़ित रहता है।

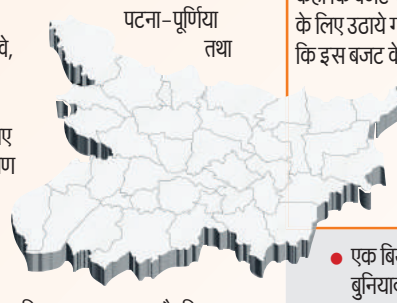

### विकास के लिए उठाए कदम सराहनीय

**पटना।** बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को सकारात्मक एवं स्वागत योग्य बताया और कहा कि बजट में बिहार के विकास की गति को बढ़ाने के लिए उठाये गए कदम सराहनीय है। कुमार ने कहा कि इस बजट के माध्यम से देश के साथ-साथ बिहार के विकास की गति को बढ़ाने के लिये कई कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय है। संतुलित बजट पेश करने के लिये मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है।

- एक बिजली संयंत्र, विरासत गलियारों, नए हवाई अड्डे एवं खेल बुनियादी ढांचे के लिए योजनाओं
- तीन सड़क संपर्क परियोजनाएं : पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे, तथा बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेस-वे
- बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त दो-लेन पुल के समर्थन की घोषणा

## जम्मू-कश्मीर के लिए 42,277.74 करोड़ आवंटित

**नई दिल्ली।** बजट में जम्मू-कश्मीर को 42,277.74 करोड़ आवंटित किए हैं जो पिछले वित्त वर्ष में दिए गए 41,751.44 करोड़ रुपये से 1.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि को दर्शाता है। जम्मू-कश्मीर को आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि के रूप में स्वीकृत 7,900 करोड़ भी हैं। सरकार ने प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया कोष में अनुदान के तौर पर जम्मू कश्मीर को 279 करोड़ आवंटित किए हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए होंगे। प्रदेश को 624 मेगावाट की किरु जल विद्युत परियोजना (एचईपी) के लिए इक्विटी योगदान के लिए 130 करोड़ आवंटित हुए हैं, 800 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना के लिए इक्विटी की खातिर 476.44 करोड़ मंजूर हुए हैं। झेलम और तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना (जेटीएफआरपी) के खर्च को पूरा करने के लिए 500 करोड़ का अनुदान दिया गया है।

## लद्दाख के लिए बजट आवंटन में 32 प्रतिशत की वृद्धि

**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषित केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के 4,500 करोड़ रुपये के आवंटन से 32 प्रतिशत अधिक है। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर से अलग हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अपने सचिवालय से संबंधित खर्चों और अन्य विभागों और कार्यालयों की स्थापना के लिए केंद्र से स्थापना व्यय के लिए 2,035.49 करोड़ रुपये मिले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में लद्दाख को अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय के लिए 3,922.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें कृषि और संबद्ध योजनाएं, जल आपूर्ति और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, बिजली, वानिकी और वन्यजीव, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अन्य विभाग शामिल हैं।

## रोजगार-अवसरों के नए युग की शुरुआतः शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को दूरदर्शी, जनहितैषी और विकासोन्मुखी करार दिया। उन्होंने कि यह रोजगार तथा अवसरों के एक नए युग की शुरुआत करेगा। देश को विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने की राह पर ले जाएगा। उद्यमशीलता बढ़ाने, व्यापार सुगम बनाने के साथ ही आर्थिक विकास को दिशा देने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें कर आकलन नियमों को सरल बनाकर करदाताओं को राहत दी गई है। उन्होंने हैशटैग बजटफॉरविकसितभारत के साथ एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों की शक्ति का उपयोग कर यह बजट रोजगार और अवसरों के एक नए युग की शुरुआत करेगा। देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और विश्वास को पूरा करेगा। यह मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के संकल्प का परिचायक भी है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये की घोषणा परिवर्तनकारी सिद्ध होने वाली है।

## बजट पक्षपातपूर्ण और गरीब विरोधीः ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और गरीब विरोधी करार दिया। उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल ने ऐसी कौन सी गलती है कि उसे केंद्र ने वंचित कर दिया। बजट में गरीबों के हितों का खयाल नहीं रखा गया है। यह दिशाहीन है। यह बस राजनीतिक मिशन को पूरा करने के लिए है।

## मायूस करने वाला बजट : मायावती

बसपा अध्यक्ष मायावती ने बजट को अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम बल्कि मायूस करने वाला ज्यादा बताया। उन्होंने कहा कि बजट पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर और धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों और उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम बल्कि मायूस करने वाला ज्यादा है। देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन व कमजोर तबकों के उत्थान के प्रति सुधारवादी नीति और नीयत का अभाव है।

## विकसित राष्ट्र बनाने का मजबूत कदम है : मांडविया

केन्द्रीय खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के विकास पर केन्द्रित बजट के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। उन्होंने कहा गरीब युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के विकास पर केंद्रित बजट के लिये मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभार प्रकट करता हूं।

## रोजगार-मुद्रास्फीति पर ध्यान देना अच्छे संकेत

नई दिल्ली, एजेंसी

अर्थशास्त्रियों ने बजट को रोजगार सृजन, मुद्रास्फीति प्रबंधन और राजकोषीय विवेक पर केंद्रित बताते हुए इसे शुभ संकेत बताया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि सरकार ने रोजगार और कौशल विकास को पहली प्राथमिकता दी है।

कुमार ने कहा कि इससे पता चलता है कि सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और वह कुछ अर्थशास्त्रियों की तरह बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के झूठे दावों से प्रभावित नहीं हो रही है। एनआईपीएफपी के प्रोफेसर पिनाकी चक्रवर्ती ने कहा कि केंद्र सरकार के ऋण और घाटे को राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुरूप स्तर तक कम करने के लिए राजकोषीय विवेक के स्थिर मार्ग पर चलना जारी रखना होगा। बजट में आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की घोषणा की गई है। एनआईपीएफपी के प्रोफेसर एनआर भानुमूर्ति ने कहा कि बजट मोटे तौर पर अंतरिम बजट की निरंतरता है, जिसमें कुछ बेहतर राजकोषीय गुंजाइश के साथ नौकरियों पर ध्यान दिया गया है।

## विकसित भारत का लोक कल्याणकारी बजटः शर्मा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत का लोक कल्याणकारी बजट बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रस्तुत किये गए बजट को मैंने सुना। यह बजट विकसित भारत की परिकल्पना, अंत्योदय के प्रति दृढ़ संकल्प, एवं नए भारत को वैश्विक विकास का अग्रदूत बनाने का रोडमैप है। पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए इस लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख तथा सर्वसमावेशी बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद।

## दिल्ली को नहीं मिला एक भी रुपया : आतिशी

आतिशी ने कहा कि केंद्र को करों के रूप में 2.32 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करने के बावजूद केंद्रीय करों में दिल्ली को एक पैसा भी नहीं मिला। दिल्ली ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए बजटीय आवंटन की मांग की थी लेकिन उसे केंद्र से एक भी रुपया नहीं मिला है। वह केंद्र को आयकर के रूप में दो लाख करोड़ से अधिक और केंद्रीय जीएसटी के रूप में 25,000 करोड़ का भुगतान करती है। दिल्ली 20,000 करोड़ मांग रही थी जो कि केंद्रीय बजट का सिर्फ 0.4 प्रतिशत है।

## एमएसएमई सेक्टर को मिलेगी मजबूती



यह नए भारत का बजट है। सभी वर्गों और क्षेत्रों को साथ लेकर समर्थ और विकसित भारत के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने का दस्तावेजी प्रमाण है। मोदी सरकार 3.0 ने अपना पहला बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिहाज से डिजाइन किया है। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के साथ एमएसएमई सेक्टर को मजबूती से एड्रेस किया गया है। शेयर बाजार को इस बजट को समझने में एक-दो दिन का वक्त लग सकता है, उसकी रफ्तार और तेज होगी, इसमें कोई शक नहीं है। युवाओं के लिए कौशल विकास के साथ रोजगार का रोड मैप प्रदान किया जाना, यह बताता है कि सरकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कृत संकल्पित है। भारत आज युवाओं का देश है और स्किल डेवलपमेंट के बूते दुनिया में धाक जमा सकता है, ऐसे में सरकार के अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप की दिशा में आगे बढ़ने से युवाओं में भी आत्मविश्वास और जोश बढ़ेगा। पहली बार देश के कॉरपोरेट सेक्टर को इस जिम्मेदारी से जोड़ा जाना महत्वपूर्ण और परिदृश्य बदलने वाला कदम है। इसी तरह देश में निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों की बड़ी संख्या देखते हुए आयकर में मानक कटौती को 50 से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किए जाने और कर स्लैब में राहत प्रदान देने से 7 लाख 75 हजार तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, इससे लगभग 4 करोड़ लोगों को 17,500 रुपये की बचत होगी, जो बाजार का हिस्सा बनेगी। सरकार ने कृषि क्षेत्र को भी प्राथमिकता पर रखा है।

**-आकाश गोयनका**, प्रमुख उद्यमी और गोल्डी समूह के निदेशक

## इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में कर छूट सराहनीय

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सातवें बजट में 9 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रीत किया है। इसमें कृषि में उत्पादकता बढ़ाने को 1.52 लाख करोड़ निवेश की बात कही गई, किंतु कृषि वृद्धि दर 1.8% से 4% तक जाने का रास्ता कैसे तय होगा यह जिक्र नहीं किया। आर्थिक सर्वेक्षण यह कहता है कि 51% स्नातक रोजगार योग्य नहीं है तब रोजगार व कुशलता की प्राथमिकता सराहनीय है। अवसंरचना विकास में बिहार और आंध्र प्रदेश के एक्सप्रेस-वे ही महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ का आवंटन महत्वपूर्ण है किंतु ग्रामीण हाट को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में कर छूट सराहनीय है किंतु घर, रसोई, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर कुछ खास नहीं मिला। लघु उद्योगों का विकास व सहायता, रोजगार और कुशलता ऋण, सूर्य योजना, नए शोध केंद्रों का जिक्र आदि योजनाएं हैं। राजकोषीय घाटे का 4.9% का होना चिंता का विषय है। नौकरीपेशा और नवीन निवेशकों को न कर में छूट मिली, न बचत, न निवेश के लिए प्रोत्साहन। परिवहन और रेलवे पर संभवत: वित्त मंत्री ने अलग दस्तावेज तैयार किया है। बजट में महिला, युवा, बेरोजगार, कौशल आदि की बातें जरूर हैं लेकिन उनके आंकड़े और समय सीमा का होना भी जरूरी था। पूंजीगत व्यय का बढ़ना, युवाओं को इंटर्नशिप कराना, ऊर्जागत विकास, लघु उद्योगों को क्रेडिट गारंटी, औद्योगिक कॉरिडोर का विकास आदि महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं।

**- डॉ. विकास प्रधान**, अर्थशास्त्र विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीसलपुर (पीलीभीत)

## विकसित भारत बनाने को मजबूत कदम



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने विकसित भारत बनाने की रणनीति संसाधनों के माध्यम से मजबूत की है। इसमें उपेक्षित को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। बजट-2024 में युवा, महिला, कृषि, प्रशासनिक सुधार व क्षेत्रीय सशक्तिकरण को मजबूती देने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने युवाओं को शिक्षा, कौशल और विकास के साथ रोजगार देने पर बल दिया गया है। देश की टॉप 500 कंपनियां पांच वर्षों तक जिस तरह से युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगी, वो निश्चित तौर पर रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करेगा। इससे आर्थिक लाभ भी युवाओं को ही मिलेगा। महिलाओं के आर्थिक विकास व सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की धनराशि तय की गई है। यह नये ग्रोथ इंजन का काम करेगा, जो विकसित भारत की ओर अग्रसर होगा। इसमें कृषि के आधुनिकीकरण, उत्पादकता की वृद्धि तथा भूमि के रिकार्ड की डिजिटल व्यवस्था की बात की गई है। इसके तहत बदलते पर्यावरण के अनुकूल उच्च उत्पादकता वाले बीजों के वितरण तथा प्राकृतिक खेती को महत्व दिया गया है। छोटे व कुटीर उद्योग धंधों पर भी इस बजट में ध्यान केंद्रित किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार व आत्म निर्भरता का कार्य जारी है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को एक लाख करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। जलवायु परिवर्तन को सही करने के लिए बजट में प्रयास दिखाई पड़ते हैं।

**- प्रो. एमके अग्रवाल**, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय।

## आम लोगों को कोई राहत नहीं : चिदंबरम

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि महंगाई एवं बेरोजगारी को लेकर कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं तथा आम लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है। उनका कहना था कि यह दावा कि योजनाओं से 2.90 करोड़ लोगों को लाभ होगा, अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण है। चिदंबरम ने कहा कि महंगाई दूसरी बड़ी चुनौती है।

## बजट आमजन के इर्द-गिर्द केंद्रित : शिंदे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह बजट आम आदमी के इर्द-गिर्द केंद्रित है। बजट युवाओं, कामगारों, किसानों तथा महिलाओं पर केंद्रित है। इसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर भी जोर दिया गया है। यह भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने की एक शुरुआत है। बजट में महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये, किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये और बुनियादी ढांचा विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

# पूंजीगत लाभ पर कर की दर, होल्डिंग अवधि में बदलाव का प्रस्ताव

## सूचीबद्ध शेयर, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड और एक व्यावसायिक ट्रस्ट की इकाइयों पर एसटीसीजी को 20 प्रतिशत किया

नई दिल्ली, एजेंसी

सरकार ने पेश 2024-25 के बजट में प्रतिभूतियों एवं अचल संपत्तियों समेत विभिन्न परिसंपत्तियों से पूंजीगत लाभ पर कर की दर और उन्हें अपने पास रखने (होल्डिंग) की अवधि को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए पूंजीगत लाभ पर कर से संबंधित बदलावों की घोषणा की।

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर का पात्र होने के लिए सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को एक साल से अधिक समय तक जबकि गैर-सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों एवं सभी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों को कम-से-कम दो साल तक अपने पास रखना होगा। सूचीबद्ध शेयर, इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड और एक व्यावसायिक ट्रस्ट की इकाइयों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (एसटीसीजी) को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इन प्रतिभूतियों पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

निवेशकों को सालाना 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट दी जाएगी, जो वर्तमान में एक लाख रुपये है। हालांकि, सूचीबद्ध बॉण्ड एवं डिबेंचर के मामले में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इन पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं गैर-सूचीबद्ध बॉण्ड एवं डिबेंचर के मामले में एलटीसीजी को वर्तमान में 20 प्रतिशत की एकसमान दर के मुकाबले लागू होने वाली स्लैब दरों के आधार पर लगाया जाएगा। एसटीसीजी दर अपरिवर्तित बनी हुई है। अचल संपत्ति एवं सोने जैसी परिसंपत्तियों के मामले में एलटीसीजी को निवेश मूल्य पर मुद्रास्फीति के असर को हटाए बगैर 12.5 प्रतिशत की दर से लगाया जाने की बात कही गई है। इसकी मौजूदा दर 20 प्रतिशत है। हालांकि, एसटीसीजी दर में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है।

नांगिया एंडरसन एलएलपी में कर साझेदार संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि यह प्रस्ताव करदाताओं को खुश नहीं कर सकता है क्योंकि सरलीकरण की आड़ में यह प्रस्ताव कुछ मामलों में कर दरों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एकेएम ग्लोबल में कर साझेदार अमित माहेश्वरी ने कहा कि परिसंपत्ति के प्रकार पर ध्यान न देकर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर एकसमान 12.5 प्रतिशत कर की शुरुआत निष्पक्षता को बढ़ावा देती है और कर गणना को सरल बनाती है। माहेश्वरी ने कहा कि हालांकि अल्पकालिक लाभ पर 20 प्रतिशत कर लगना एक निराशा है, लेकिन यह दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है।



- दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
- बॉण्ड एवं डिबेंचर घटाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
- निवेशकों को सालाना 1.25 लाख तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट

# कर विवादों को कम करने के लिए विवाद से विश्वास-दो की तैयारी

## कानूनी मंचों पर कर अधिकारियों के लिए अपील दायर करने को मौद्रिक सीमा बढ़ाने की भी घोषणा

नई दिल्ली, एजेंसी

सरकार ने कर मामलों में विवादों को कम करने के लिए विवाद से विश्वास योजना-दो लाने का प्रस्ताव किया। साथ ही दोबारा आकलन की कार्रवाई शुरू करने की समयसीमा में कमी लाने और कानूनी मंचों पर कर अधिकारियों के लिए अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने की भी घोषणा की गयी।

बजट घोषणा के अनुसार, आकलन वर्ष समाप्ति के बाद तीन साल से लेकर पांच साल तक की अवधि वाले आयकर मामलों को फिर खोला जा सकेगा। लेकिन इसके लिए शर्त है कि मामला 50 लाख रुपये या उससे अधिक का हो। तलाशी के मामलों में भी तलाशी के वर्ष से पहले छह साल की समयसीमा का प्रस्ताव किया गया है। जबकि वर्तमान में यह 10 साल की समयसीमा है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इससे कर अनिश्चितता और विवाद कम होंगे। नांगिया एंडरसन एलएलपी के कार्यकारी निदेशक योगेश काले ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दोबारा से आकलन व्यवस्था में 2021 में महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया था। इससे सुप्रीम कोर्ट से लेकर विभिन्न अदालतों में मामले बढ़े। जो बदलाव हुए थे, उसमें एक यह था कि यदि आयकर मामले में गड़बड़ी 50 लाख रुपये से अधिक होने का संदेह है तो कर अधिकारी 10 साल पुराने मामले में भी दोबारा से आकलन शुरू कर सकते हैं।

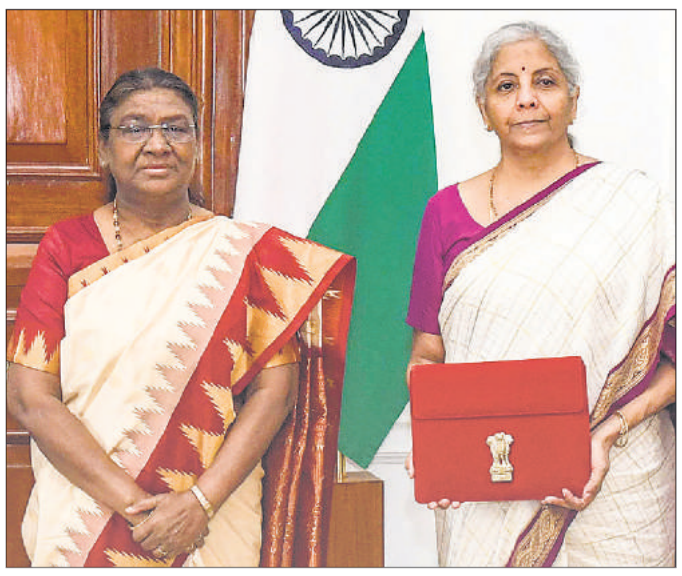

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि कोई कर अधिकारी किसी पांच साल से अधिक पुराने मामले में दोबारा से आकलन शुरू नहीं कर सकता है। इस संशोधन से करदाताओं के लिए अनिश्चितता की स्थिति दूर होगी। बजट में कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा को बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख, दो करोड़ और पांच करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव है। वर्तमान सीमा के तहत क्रमशः 50 लाख, एक करोड़ और दो करोड़ रुपये की कर मांग शामिल है। सरकार ने अपील में लंबित कुछ आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना- दो लाने का प्रस्ताव किया है।



नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने से पहले एक बैठक के दौरान केंद्रीय वित मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ● एजेंसी

- तीन से पांच साल तक की अवधि वाले 50 लाख से अधिक के आयकर मामलों को फिर खोला जा सकेगा

### 1.13 करोड़ मामलों का निदान 75,788 करोड़ का भुगतान

2020 में घोषित पहली विवाद से विश्वास योजना में, 1.13 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान किया गया है और कर विभाग को 75,788 करोड़ के कर का भुगतान मिला। सीतारमण ने कहा कि सरकार राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ करों को सरल बनाने, करदाताओं की सेवाओं में सुधार, कर को भरोसेमंद बनाने और विवादों को कम करने के अपने प्रयास जारी रखेगी। 2022-23 में कंपनी कर का 58% सरलीकृत कर व्यवस्था से आया।

### सरकार का स्टार्टअप में निवेश पर एंजल कर खत्म करने का प्रस्ताव

**नई दिल्ली।** स्टार्टअप कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल कर समाप्त करने की घोषणा की। एंजल कर का मतलब वह आयकर है जो सरकार गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई राशि पर लगाती है, यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है। अपने भाषण में उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियों तथा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संदर्भ में कुछ वित्तीय साधनों के लिए कर दरों में विभिन्न बदलावों की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि सबसे पहले, भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए मैं सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूं।

### परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने की घोषणा

**नई दिल्ली।** वित्त मंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी निवेश की खातिर खोले जाने की घोषणा की, क्योंकि सरकार का लक्ष्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को घटाकर शून्य करना है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करेगी। सरकार परमाणु ऊर्जा के लिए नयी प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास की खातिर निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करेगी। फरवरी में अंतरिम बजट में घोषित 1,000 अरब के अनुसंधान और विकास निधि को परमाणु क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

### खेती-किसानी के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में होगा सुधारः कौशल मिश्रा

**शाहजहांपुर :** प्रगतिशील किसान व मुख्यमंत्री से पुरस्कृत कौशल मिश्रा ने बजट की सराहना की है। उनका कहना है कि इससे खेती -किसानी के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। किसानों को भी तवज्जो दी गई है। हर वर्ग की तरह किसानों को भी इससे लाभ होगा। थाईलैंड, नेपाल, कजाकिस्तान जैसे देशों में भी गन्ने की विभिन्न प्रजातियों की उच्च कोटि की खेती करने के लिए सम्मानित हो चुके मिश्रा ने कहा है कि बजट में किसानों को जो सुविधाएं देने की बात कही गई है, उससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए 32 फसलों की 109 किस्मों को लाने, उच्च पैदावार वाली नौ फसलों को बढ़ावा देने, दलहन-तिलहन की खेती को मौसम से बचाने वाला बनाने का जिक्र किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खासा सुधार होगा।

मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए जा रहे बजट का सीधा प्रसारण देखते लोग। ● एजेंसी

# दूरसंचार परियोजनाओं के विस्तार के लिए मंत्रालय को मिले 1.28 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली, एजेंसी

सरकार ने दूरसंचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है। इसमें से अधिकांश राशि सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए निर्धारित की गई है।

कुल प्रस्तावित आवंटन में से एक लाख करोड़ से अधिक बीएसएनएल और एमटीएनएल से संबंधित खर्चों के लिए हैं, जिसमें बीएसएनएल में प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनर्गठन के लिए 82,916 करोड़ का निवेश शामिल है। बजट अनुमान में इस मांग के लिए कुल शुद्ध आवंटन 1,28,915.43 करोड़ (1,11,915.43 करोड़ और 17,000 करोड़ रुपये) है। 17,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत उपलब्ध शेष राशि से पूरा किया जाता है और इसका उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मुआवजा, भारतनेट और अनुसंधान एवं विकास जैसी योजनाओं के लिए किया जाएगा। बजट में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशन 17,510 करोड़ है, जिसमें बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारी भी ल हैं। सरकार ने एमटीएनएल बॉन्ड की मूल राशि के भुगतान के लिए 3,668.97 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।



- 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक बीएसएनएल और एमटीएनएल को मिले

# खुशी की बात : सोना-चांदी ने दमकाया चेहरा, सीमा शुल्क में कटौती

- सोने-चांदी पर सीमा शुल्क 15 से घटाकर किया 6 प्रतिशत
- प्लेटिनम व अन्य धातु पर सीमा शुल्क घटकर हुआ 6.4 प्रतिशत

नई दिल्ली, एजेंसी

रत्न एवं आभूषण उद्योग ने आम बजट में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क में कटौती करने के सरकार के कदम से सर्राफा करोबारियों ने बेहतर व्यापार की उम्मीद जताई है। इससे आदान (इनपुट) लागत कम होगी, मूल्य संवर्धन बढ़ेगा, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू विनिर्माण को लाभ मिलेगा।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि सोने और कीमती धातु के आभूषणों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए मैं सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर छह प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं। पहले सोने और चांदी पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत था। सोने और चांदी के 'डोर' पर शुल्क पहले के 14.35 प्रतिशत से घटाकर 5.35 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्लेटिनम, पैलेडियम, ऑस्मियम, रूथेनियम और इरीडियम पर सीमा शुल्क 15.4 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया।

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के चेयरमैन विपुल शाह के अनुसार, आयात शुल्क में कमी हमारे उद्योग के लिए एक बड़ा बढ़ावा है, जो कार्यशील पूंजी जारी करके उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य और विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा। शाह ने कहा कि विशेष अधिसूचित क्षेत्रों (एसएनजेड) में बिक्री के लिए कच्चे हीरों पर दो प्रतिशत समानीकरण शुल्क को समाप्त करने और सुरक्षित बंदरगाह नियम की शुरूआत भारत को वैश्विक हीरा व्यापार केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित करेगी। उ ये उपाय इस क्षेत्र के विकास को गति देंगे, छोटे पैमाने के हीरा तराशने वालों और पॉलिशरों के लिए लाखों नौकरियां पैदा करेंगे और वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के भारत के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

विश्व स्वर्ण परिषद के क्षेत्रीय सीईओ (भारत) सचिन जैन ने कहा कि स्वर्ण उद्योग के लिए, सोने पर मूल सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) में कमी से घरेलू आभूषण उद्योग की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।' उन्होंने कहा कि यह सोने पर कुल करों को प्रभावी रूप से जीएसटी सहित लगभग 18.5 प्रतिशत से घटाकर नौ प्रतिशत कर देगा। यह सही दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह सोने की तस्करी को हतोत्साहित करेगा। यह ईमानदार कारोबारियों को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर देगा।

### शुल्क में कमी से तस्करी में आएगी कमी

मालाबार समूह के चेयरमैन एम पी अहमद ने कहा कि उम्मीद है कि शुल्क में कमी से सोने की तस्करी में भारी कमी आएगी, जिससे अवैध व्यापार पर अंकुश लगेगा और कर राजस्व में वृद्धि होगी। इस कटौती से संगठित खुदरा आभूषण विक्रेताओं, उपभोक्ताओं और सरकार को लाभ होगा। अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) के चेयरमैन संयम मेहरा ने कहा कि सीमा शुल्क में कमी से घरेलू आभूषण निर्माताओं, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों को लाभ होगा, जिससे उन्हें धीरे-धीरे औपचारिक चैनल की ओर संक्रमण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के उपाध्यक्ष अक्ष कंबोज ने कहा कि हमारा मानना है कि यह फैसला आभूषण और सर्राफा उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करेगा, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा और नए अवसर पैदा करेगा। आयात शुल्क में कमी के साथ, पीएनजी ज्वैलर्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सौरभ गाडगिल को सोने की खपत में वृद्धि और सोने की कीमतों में नरमी की उम्मीद है, जो हाल ही में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है।

### दो लाख 78000 करोड़ में बनेंगे राजमार्गः गडकरी





**नई दिल्ली।** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए दो लाख 78000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग नितिन गडकरी ने मंत्रालय के लिए बजट प्रावधान को ढांचागत विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टिकोण का करिश्मा बताया और कहा कि बजट अगली पीढी के लिए महत्वपूर्ण सुधार लाने का रास्ता खोलता है। यह बजट ढांचागत क्षेत्र में प्रगति का मंच तैयार करता है और देश को विकास की नई राह दिखाता है। उन्होंने कहा कि यह बजट बुनियादी ढांचे, नवाचार, अनुसंधान और अगली पीढ़ी के सुधारों पर जोर देता है। साथ ही सभी क्षेत्रों में देश की महत्वपूर्ण प्रगति के लिए मंच तैयार करता है।

### मंत्रिपरिषद, सचिवालय, पीएमओ को 1,248.91 करोड़

**नई दिल्ली।** मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा किए जाने वाले व्यय तथा राजकीय अतिथियों के सेवा-सत्कार के लिए 1,248 .91 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। यह राशि 2023-24 के लिए आवंटित 1,803 .01 करोड़ रुपये से कम है। मंत्रिपरिषद के व्यय के लिए कुल 828 .36 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि 2023-24 में 1,289 .28 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे। मंत्रिपरिषद के लिए यह आवंटन कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतन, सेवा-सत्कार और अन्य भत्तों तथा वीवीआईपी की यात्रा पर होने वाले खर्च के लिए है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को 202 .10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह 2023-24 में 299 .30 करोड़ रुपये था। यह राशि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के प्रशासनिक व्यय और अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय को कुल 72 .11 करोड़ रुपये (2023-24 में 76 .20 करोड़ रुपये) दिए गए हैं। रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी) के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए कैबिनेट सचिवालय को 2023-24 में आवंटित किए गए 70 .28 करोड़ रुपये के मुकाबले 75 .24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रशासनिक व्यय के लिए 65 .30 करोड़ रुपये (2023-24 में 62 .65 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं। बजट में राजकीय अतिथियों के सेवा-सत्कार के लिए चार करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो 2023-24 में आवंटित राशि के बराबर है। बजट में पूर्व राज्यपालों के सचिवालय सहायता के भुगतान पर व्यय के लिए 1.80 करोड़ रुपये (2023-24 में 1.30 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं।

### सीबीआई को मिले 951 करोड़, पिछले साल से कम

**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषित वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में देश की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 951 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं, जिसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 1.79 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई है। एजेंसी को 2023-24 के संशोधित बजट अनुमान में अपने कामकाज के प्रबंधन के लिए 968 .86 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश बजट दस्तावेज के अनुसार, सरकार ने 2024-25 के लिए एजेंसी को 951 .46 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बजट दस्तावेज के अनुसार यह प्रावधान एजेंसी के संस्थापन संबंधी व्यय के लिए है, जिसे लोक सेवकों, निजी व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों की जांच और अभियोजन का काम सौंपा गया है। बजट दस्तावेज में कहा गया है कि सीबीआई के आवंटन में उसके प्रशिक्षण केंद्रों का आधुनिकीकरण, तकनीकी और फोरेंसिक सहायता इकाइयों की स्थापना, व्यापक आधुनिकीकरण और सीबीआई के लिए भूमि की खरीद/कार्यालय/आवास भवनों का निर्माण जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।




### बच्चों के लिए नई पेंशन योजना वात्सल्य



**नई दिल्ली।** सरकार ने बच्चों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) वात्सल्य की घोषणा की है जिसमें माता-पिता और अभिभावक को अंशदान करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश 'केन्द्रीय बजट 2024-25' में बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना 'वात्सल्य' की घोषणा की। इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे। वयस्कता की आयु होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। श्रीमती सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारियों ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकल सके और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाई रखी जाएगी।

### अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को दिए 574 करोड़

**नई दिल्ली।** केंद्रीय बजट में इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 3183 .24 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में 574 .31 करोड़ रुपये अधिक है। सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 20 फीसदी से अधिक की वृद्धि की है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में मंत्रालय के लिए 3097 .60 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया था, हालांकि संशोधित बजट में यह राशि 2608 .93 करोड़ रुपये हो गई थी। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 3183 .24 करोड़ रुपये को आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए इस बार 326 .16 करोड़ रुपये तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1145 .38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए सरकार ने बजट में कुल 1575 .72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं/परियोजनाओं के लिए कुल 2120 .72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' के लिए इस बार 910 .90 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है।

## वक्तव्य

### रोजगार और कौशल विकास पर फोकस : आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि बजट में शिक्षा, रोजगार व कौशल विकास पर जोर दिया गया है। आम बजट अमृत काल के लिहाज से बहुत ही अहम है क्योंकि यह देश के 140 करोड़ लोगों को सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक न्याय दिलाने वाला है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल ने कहा कि बजट में किसान, गरीब, युवा व महिला सभी के लिए कुछ न कुछ है। इसमें मध्यम वर्ग को न्याय, औद्योगीकरण को बढ़ावा, बेरोजगारों को रोजगार और गरीब आदिवासी व अल्पसंख्यकों को न्याय देने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि व सामाजिक क्षेत्र का विशेष ध्यान रखने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास व युवाओं के कौशल विकास पर बल देने से अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

### सबका साथ, सबका विकास वाला बजट: ब्रजेश पाठक

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आम बजट सबका साथ, सबका विकास करने वाला है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। युवाओं, महिलाओं व नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि पहली नौकरी में एक लाख रुपए सालाना से कम सैलेरी होने पर 15 हजार रुपए की मदद, शिक्षा ऋण में छूट से युवाओं का भविष्य संवरेगा। वहीं, पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए व 500 टॉप कंपनियों में पांच करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से काफी लाभ मिलेगा।

### गरीबों को मायूस करने वाला सरकार का बजट : रीता बहुगुणा

पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व सांसद प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला बजट है। वित्त मंत्री ने बजट में हवाई अड्डो से लेकर चिकित्सा सुविधाओं और खेल बुनियादी ढ़ांचे का ध्यान रखा है। बजट में युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, कृषि और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। पूर्वी राज्यों को देश की आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाने के लिए विशेष योजनाओं का भी ऐलान किया है। महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

### युवाओं को बैंकों से ऋण लेने में मिलेगी सुविधा : राकेश सचान

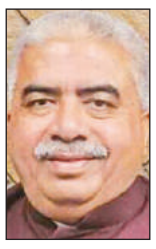

एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बजट को सर्वस्पर्शी और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एमएसएमई इकाइयों को विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए बजट में एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल पेश किया जाएगा, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर ऋण की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। यह नई प्रणाली बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सुविधा उपलब्ध कराएगी।

### बजट में केवल जुमलेबाजी और हवाई दावे : अजय राय

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आम बजट में हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ जुमलों और हवाई दावों के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंन कहा कि देश की सभी बड़ी समस्याओं फिर चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, या फिर महंगाई की बात हो किसी भी समस्या के निवारण का स्पष्ट रोड मैप नहीं है। पिछले बजट में जो वादे किय गये थे, जो योजनाएं घोषित हुई थी, उनकी कोई चर्चा न करते हुए फिर से नये वादे नई घोषणाएं की गई हैं, पर किसानों, बेरोजगारों व गरीबों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

# आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ेंगी महिलाएं, बनेंगी सशक्त

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की योजना लागू होने व इसके अलावा महिला केंद्रित स्किल्ड प्रोग्राम लागू करने और पॉलिसी के साथ हायर एजुकेशन घरेलू संस्थाओं के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाना सराहनीय है। – **डॉ अनीता मिश्रा**, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज शास्त्र,एमएल वर्मा पीजी कॉलेज

नए भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और देश व प्रदेश का ग्रोथ इंजन बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला यह लोक-कल्याणकारी बजट है। इसमें महिलाओं के विकास और सशक्त बनाने के लिए उपयोगी कदम उठाए गए हैं। – **रेनुका टंडन**, निदेशक, एमरन ग्रुप ऑफ कंपनी

इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान समेत समाज के सभी तबकों के समग्र विकास का संकल्प, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि और वंचित को वंचना से मुक्त कराने का रोडमैप है। महिलाओं का प्राथमिकता दी गई है। – **श्रुति सांडिल्य**, प्रबंध निदेशक तिर्वा फार्म्स

इस बजट में किसानों की समृद्धि के लिए 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपए कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। – **वंदिता अग्रवाल**, सीनियर वाईस चेयरपर्सन, फिक्की फ्लो लखनऊ चैप्टर

## खेलों को मिलेगा बढ़ावा

छात्रों को दिया जाने वाला मॉडल स्किल लोन निश्चित तौर पर हम जैसे खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होगा। कई बार पैसों के अभाव में खेलों की प्रेक्टिस पर असर पड़ता है। यह पहले होता तो मैं भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी होती। – **हामिद सलमानी**, राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, पुनर्वास विश्वविद्यालय

मॉडल स्किल लोन का लाभ हम जैसे तमाम छात्रों के लिए लाभकारी रहेगा। कई बार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान पैसों के अभाव में बाधा आ जाती है। ऐसे में योजना का लाभ लेकर दिव्यांग छात्र भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। – **सिराजुद्दीन**, दिव्यांग छात्र, पुनर्वास विश्वविद्यालय

# कानपुर के लिए सेमी हाईस्पीड ट्रेन भोपाल तक चलाई जाएगी वंदे भारत

## रेल बजट: ट्रैक मेंटीनेंस, यार्ड रिमॉडलिंग, सेफ्टी से जुड़े कई काम होंगे

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार** : लखनऊ से कानपुर के लिए सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे मेट्रो के जल्द ही पटरी पर उतरने की संभावना है। बजट में इसके लिए 240 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद रेलवे अधिकारियों ने लगा रखी है। इसी तरह से गोमतीनगर से भोपाल के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, कटरा व पुरी के लिए नई ट्रेन की सौगात यात्रियों को मिलने की उम्मीद भी रेलवे अधिकारियों को है।

मंगलवार को आम बजट में रेलवे के लिए कुल 2.62 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इसमें सेफ्टी व मेंटीनेंस के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उत्तर रेलवे व पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों को लखनऊ मंडल के लिए सेफ्टी, यात्री सुविधाओं व स्टेशनों के विकास के लिए खासा बजट मिलने की उम्मीद अधिकारियों को है। लेकिन लखनऊ मंडल को कितनी धनराशि आवंटित की गई है, इसकी जानकारी पिंक बुक जारी होने पर मिल सकेगी। पिंक बुक में मदवार आवंटित धनराशि की जानकारी होगी। वहीं अधिकारियों को यह उम्मीद है कि लखनऊ से कानपुर के बीच सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे मेट्रो चलाने का खाका तैयार कर लिया गया है। इसके लिए रूट के स्टेशनों की इंटरलॉकिंग, ट्रैक मेंटीनेंस आदि पहले ही हो चुका है। रूट पर ट्रैक स्पीड भी बढ़ाई जा रही है।

इसके बाद कानपुर के लिए वंदे मेट्रो चलेगी, जिसकी स्पीड 130 से 160 किमी प्रति घंटे के बीच होगी। इससे कानपुर की दूरी महज 45 मिनट में पूरी कर ली जाएगी। इससे यात्रियों को खासी राहत मिलेगी। गोमती नगर से भोपाल के लिए नई वंदे भारत शुरू करने की भी तैयारी रेलवे कर रहा है। पुरी व कटरा के लिए ट्रेनों को शुरू करने का प्लान पहले से ही पाइपलाइन में है।

**अगले हफ्ते रिलीज होगी उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे की पिंक बुक**

### सेफ्टी, सिक्योरिटी होगी अत्याधुनिक

लखनऊ मंडल में ट्रेनों के हादसों को रोकने के लिए सेफ्टी व यात्रियों की ट्रेनों में सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी पर खासा खर्च होगा। इसे अत्याधुनिक बनाने के लिए सौ करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं।

### चारबाग स्टेशन होगा अपग्रेड

चारबाग रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है। सेकेंड एंट्री बनाई जा रही है। एयर कॉन्कोर्स का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। अपग्रेडेशन के लिए 450 करोड़ रुपये मिल चुके हैं और इस मद में धनराशि मिलने की उम्मीद रेलवे अधिकारियों को है। अमृत भारत स्टेशनों के विकास को भी गति मिलेगी।

### फोरलेन आउटर बनेगा

चारबाग से दिलकुशा और आलमनगर की ओर फोरलेन आउटर बनाए जाने की तैयारी है। दिलकुशा आउटर के लिए काम शुरू किया जा चुका है। उम्मीद है कि इस मद में अच्छी-खासी धनराशि मिलेगी। फोरलेन आउटर बन जाने से ट्रेनों की लेटलतीफी काम हो जाएगी और ट्रेनों को आउटर पर रोकने से यात्रियों को होने वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी।

# कैंसर के मरीजों को राहत की गारंटी

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार** : बजट में कैंसर की तीन प्रमुख दवाएं ट्रास्टुजुमैब डेरेक्सटेकन, ओसिमेर्टिनिव और डुर्बालुमैव को कस्टम ड्यूटी से मुक्त करने की घोषणा की गई हैं। इससे कैंसर के मरीजों को राहत मिलेगी। इस घोषणा की चिकित्सकों ने सराहना की है।

चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवाशीष शुक्ला ने कहा देश में कैंसर का बोझ हर साल बढ़ रहा है। बजट घोषणा में कैंसर दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला सराहनीय है। केजीएमयू के प्रवक्ता व रेडियो थेरेपी विभाग के प्रोफेसर डॉ. सुधीर सिंह ने कहा कस्टम ड्यूटी हटने से मरीजों को दवाओं की कीमत कम देनी होगी। इसके अलावा कई मेडिकल उपकरणों पर छूट भी मिलेगी। इससे मरीजों को भी फायदा होगा।

डॉ. देवाशीष शुक्ला

डॉ. सुधीर सिंह

**कई मेडिकल उपकरणों पर छूट भी मिलेगी, इससे मरीजों को भी फायदा होगा**

### दवाएं और उनकी कीमत

**ट्रास्टुजुमैब डेरेक्सटेकन**

यह दवा सभी प्रकार के पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में काम आती है। इसे हरसेप्टिन नाम से भी जाना जाता है। यह दवा आमतौर पर कैंसर के मरीज को 3 हफ्ते में एक बार लेनी होती है। इसकी एक डोज में 3 वायल लगते हैं, इसकी कीमत अनुमानित 4 लाख रुपये तक आती है।

**ओसिमेर्टिनिव**

यह दवा नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में टार्गेटेड थेरेपी के रूप में इस्तेमाल होती है। यह दवा ईजीएफआर इनहेबिटर्स पीढ़ियों के प्रति रेजिस्टेंट हो चुके कैंसर पर बेहतरीन काम करती है। एक महीने की खुराकों की कीमत डेढ़ लाख रुपये तक है।

**डुर्बालुमैव**

यह एक इम्यूनोथेरेपी दवा है जो पीडी-एल1 प्रोटीन को ब्लॉक करके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने में मदद करती है। इसे नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और ब्लैडर कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा भी मरीज को 3 हफ्ते यानि करीब 21 दिन में एक बार लेनी होती है। । इसकी एक खुराक की कीमत ढाई लाख रुपये के आसपास है।

### फार्मा उद्योग में कर्मचारी कर रहे थे 8वें वेतन आयोग का इंतजार

**अमृत विचार, लखनऊ** : बजट में कैंसर की तीन दवाओं को कस्टम मुक्त किया जाना और फार्मा उद्योग में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 1200 से बढ़ाकर 2143 किया जाना स्वागत योग्य है, लेकिन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की घोषणा न होने से निराशा है। कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, वहीं 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय की घोषणा का भी इंतजार था। फार्मेसिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि स्थाई रोजगार सृजन न होने से तकनीकी योग्यता धारक लोगों को अल्प वेतन और भविष्य की असुरक्षा के बीच कार्य करना पड़ रहा है। फेडरेशन अध्यक्ष ने कहा कि बजट में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की घोषणा तो की गई है लेकिन इन पुराने अस्पतालों में जनता को निशुल्क औषधियां, निशुल्क इलाज और सुविधाओं को लेकर कोई नई योजना नहीं दी गई है।

# रिकार्ड भी बनाया, राष्ट्र की रफ्तार भी बढ़ाई : एबीवीपी

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार:** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अपनी राय साझा की गई।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष जयव्रत राय ने कहा कि वित्तमंत्री द्वारा दिया गया बजट का फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक का इंकम टैक्स फ्री हो गया है। वैभव जोशी ने बताया कि इस बार के बजट में युवाओं, एमएसएमई, कृषि, महिला एवं कर्मचारियों को विशेष ध्यान में रखा गया है। देश के किसानों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया है, चाहे वो योजनाएं हो या फिर नई तकनीकी सम्बंधित परियोजना। तान्या तिवारी कहती हैं कि बजट से रोजगार के अवसर एवं उपलब्धता बढ़ेगी। पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देगी। देश की सर्वोच्च 500 कंपनियों में 5 करोड़ प्रशिक्षित युवाओं को इन्टर्नशिप एवं मुद्रा लोन के तहत ऋण राशि का लाभ भी मिलेगा। विकास तिवारी ने बताया कि बजट में सामाजिक एवं आर्थिक समावेश एवं विकास के लिए महिलाओं, युवाओं, किसानों और असंगठित मजदूरों वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है।

जयव्रत राय

वैभव जोशी

तान्या तिवारी

विकास तिवारी

**प्रतिक्रिया** टैक्स स्लैब में नहीं होगा ज्यादा फायदा

# ठगा महसूस कर रहे शिक्षक और कर्मचारी

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार** : सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों को केन्द्रीय बजट नहीं भाया। वे ठगा हुआ महसूस कर रहे है। बजट में वर्षों से पुराने टैक्स सिस्टम में कोई राहत नहीं मिली है। साथ ही पुराने टैक्स स्लैब में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हज़ार ही रहेगा।

वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी एवं महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने कहा कि परिषद के लम्बे संघर्ष एवं वित्त सचिव स्तर की कई बार बातचीत के बाद भी पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में निर्णय सरकार ने नहीं लिया गया।

बजट में भी शिक्षको-कर्मचारियों और शिक्षकों को बहुत उम्मीद थी कि पुरानी पेंशन बहाली की बात होगी, 8वें वेतन आयोग की बात होगी, कोरोना काल में जब्त किए गए मंहगाई भत्ते की बात होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। – **रीना त्रिपाठी, शिक्षिका व अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ**

सरकार ने गरीबों के सशक्तिकरण, मुफ्त राशन और युवा बेरोजगार को एक करोड़ रोजगार की बात की है लेकिन कर्मचारियों को टैक्स स्लैब में फायदा कम मिला है। सरकार को इस बारे भी सोचना चाहिए था। – **सुलोचना मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष, महिला शिक्षक संघ**

नये बजट में होम लोन,लाइफ इंश्योरेंस जैसी स्कीम लेने वाले शिक्षक-कर्मचारी की आशाओं को झटका लगा है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की घोषणा की है ये सराहनीय है। – **महेश मिश्रा, लखनऊ मंडल अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ**

शिक्षक-कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे है। जो शिक्षक-कर्मचारी किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करते हैं,उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से बढ़ाकर 75 हजार किया गया है। – **वीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ-लखनऊ**

कर्मचारियों के लिए कुछ खास नहीं है। शिक्षकों/कर्मचारियों की आशाओं पर पानी फेरा गया है। इनकम टैक्स में बहुत थोड़ा सा लाभ दिया गया है। इससे क्या हो जाएगा – **विनय कुमार सिंह, प्रान्तीय अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन**

**8वां वेतन आयोग ओपीएस बहाली की उम्मीद भी टूटी**

संयुक्त संघर्ष संचालन समिति एस-4 के पदाधिकरियों ने बजट को निराशाजनक बताया है। पदाधिकारियों ने कहा कि इस बजट में उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी। अब तो ओल्ड पेंशन स्कीम की भी उम्मीद टूट चुकी है। समिति के अध्यक्ष अजय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह, संयोजक सत्य प्रकाश और महासचिव आरके निगम ने केंद्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारी समाज के लिए ये बजट निराशाजनक है। ओपीएस, 8 वें वेतन आयोग, राष्ट्रीय वेतन नीति, रिक्त पदों पर भर्तियां, संविदा-आउटसोर्सिंग बजट से सब गायब हैं। 10 वर्षों के बाद आयकर ढांचे में एक बात की बढ़ोत्तरी व छूट में मात्र 25 हजार की वृद्धि नाकाफी है।

## व्यापारी नेता बोले

केन्द्र सरकार का यह बेहतरीन बजट है। आयकर की दरों में थोड़ा बदलाव कर 12 लाख तक आय वाले छोटे व्यापारियों को राहत देने का कार्य किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव सभी वर्गों को आयकर में राहत देगा। सोने और चांदी में कस्टम डयूटी घटाने से सोने और चांदी के गहने सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल फोन एवं चार्जर पर सीमा शुल्क घटने के अलावा कैंसर की दवाएं सस्ती होने और मुफ्त राशन आगे भी जारी रखने का फैसला सराहनीय है। – **बनवारी लाल कंछल**, पूर्व सांसद एवं प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल



मोबाइल, चार्जर और स्पेयर पार्ट्स पर कस्टम शुल्क घटने से यह चीजें सस्ती होंगी। मिडिल क्लास के लिए बीस हजार के मोबाइल पर जीएसटी कम की जाती तो जनता का ज्यादा फायदा होता। ऑनलाइन पॉलिसी पर इस बार भी सरकार ने खुदरा व्यापारियों को राहत नहीं दी। व्यापारी काफी त्रस्त है। ऑनलाइन कंपनियों की मनमानी रोकी जाए। इसके लिए दस प्रतिशत न केवल सेस लगना चाहिए बल्कि स्पष्ट पॉलिसी का भी आगाज होना चाहिए।– **नीरज जौहर**, प्रदेश अध्यक्ष, यूपी मोबाइल एसोसिएशन



मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। इससे छोटे बड़े सभी व्यापारियों को कारोबार करने में सहूलियत मिलेगी। बजट में टीडीएस टाइम से जमा न करने पर अब ज्यादा सख्ती नहीं की जाएगी। यह एक अच्छी पहल है। युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए बजट में काफी कुछ है। इनकम टैक्स में छूट का दायरा व्यापारी वर्ग की उम्मीदों से काफी कम है। एमएसएमई 43बी एच वाले नियम की समयावधि पर भी सोचा नहीं गया। –**अशोक मोतियानी**, अध्यक्ष, कपड़ा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल लखनऊ



बजट मध्यम वर्ग के लिए नई आशा लेकर आया है। आयकर में छूट और कैंसर की दवा, ऑक्सीजन, मोबाइल चार्जर, सोना-चांदी सस्ती होने का लाभ आमजन को मिलेगा। मुद्रा लोन 20 लाख किए जाने का लाभ छोटे उद्योगों और व्यापारियों को मिल सकता है। इससे लोग नए कारोबार की तरफ बढ़ेंगे। छोटे उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का विस्तार किया गया है। किसानों, महिलाओं, शिक्षा, कृषि और उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने वाला बजट है। –**संदीप बंसल**, अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल



बजट व्यापारियों और देश की जनता को उत्साहित करने वाला है। व्यापारी कई वर्षों से आयकर स्लैब में बदलाव की मांग कर रहे थे, जिसे वित्त मंत्री ने पूरा किया है। इससे आयकरदाता बढ़ेंगे। जनता की क्रय करने की क्षमता बढ़ेगी। इसका लाभ उद्योग एवं व्यापार दोनों को मिलेगा। एंजल टैक्स को समाप्त करने से युवाओं को लाभ होगा तथा स्टार्टअप में निवेश के अवसर बढ़ेंगे। मोबाइल समेत कई चीजों पर राहत देने की कोशिश हुई है। यह अच्छा प्रयास है। –**संजय गुप्ता**, प्रदेश अध्यक्ष, उप्र आदर्श व्यापार मंडल



व्यापारियों के लिए बजट उम्मीद से बेहतर है। जीएसटी का सरलीकरण करने के लिए टैक्स का एक स्लैब होने की उम्मीद थी। ई-कॉमर्स कंपनियों को बजट में छूट दी गयी है जबकि इसकी जरूरत व्यापारियों को थी। ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी से रिटेल व्यापारी परेशान है। खर्च ज्यादा है बिक्री घटी है। देश के रिटेल कारोबार को बचाना है तो ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सरकार को पॉलिसी बनाने की जरूरत है। लेकिन सरकार ने इस दिशा में नहीं सोचा। –**मो. अफजल**, प्रदेश कोषाध्यक्ष, उप्र आदर्श व्यापार मंडल



पिछले बजट में सरकार ने इंफ्रास्टक्चर और इस बार एमएसएमई पर जोर दिया है। 20 लाख तक लोन बिना सिक्योरिटी व्यापारियों को मिलेगा, जिससे व्यापार बढ़ेगा। बजट में युवाओं और किसानों के लिए भी कई निर्णय लिये गए हैं। सोने चांदी पर आयात शुल्क घटाया है, जिसका फायदा जनता और व्यापारियों को मिलेगा। कई मुद्दों को संगठन की ओर से उठाया गया था। इसमें अभी राहत की दरकार है। –**अविनाश त्रिपाठी**, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल



बजट आमजन को राहत देने वाला है। लेकिन कपड़ा समेत कई चीजों पर सरकार का ध्यान नहीं गया है। एमएसएमई में पंजीकृत व्यापारियों की समयावधि बढ़ाए जाने की मांग थी। इस पर भी बात नहीं बनीं। कपड़ों पर राहत की उम्मीद थी। सोने में कस्टम डयूटी घटाई गई है जो महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली है। –**प्रभू जालान**, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लखनऊ व्यापार मंडल



आमजन के लिए ठीक है। जहां मोबाइल, चार्जर पर कस्टम डयूटी घटने से लोगों को लाभ मिलेगा। मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा लोग इसी तकनीकी यंत्र का उपयोग करते हैं। यार्न में तेजी को लेकर कपड़ा और चिकन वस्त्रों पर ध्यान नहीं दिया गया। इस ओर देखा जाना जरूरी है।–**सुरेश छाबलानी**, अध्यक्ष लखनऊ महानगर अभा उद्योग व्यापार मंडल



बजट ठीक है। सभी को साथ लेकर चलने की बात बजट में है। हालांकि कई बार मांग के बाद भी कपड़ा उद्योग और यार्न में तेजी की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। एमएसएमई में पंजीकृत व्यापारियों के लिए समयावधि बढ़ाने को भी कहा गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। –**अनिल बजाज**,



यह एक ईमानदार सरकार का ईमानदारी वाला बजट है। प्रोग्रेसिव सरकार का प्रोग्रेसिव बजट है। गरीब, किसान, युवा, मातृ शक्ति को समर्पित बजट देश को समग्र विकास की ओर निश्चय ही तेजी से आगे ले जाएगा। –**सुधीर हलवासिया**, संरक्षक, लखनऊ व्यापार मण्डल



सब कुछ ऑनलाइन है। इससे ईज ऑफ डूइंगि बिजनेस होगा। धरातल पर ऐसा है नहीं। बजट में व्यापारियों के लिए बहुत कुछ नहीं है। दवा की दुकान करते हैं तो ड्रग लाइसेन्स लेना है और अगर आप फ्रूड सप्लीमेंट भी उसमें बेचते है दवा के साथ फूड डिपार्टमेन्ट में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसे में एक ही दस्तावेजों से दोनो लाइसेन्स जारी होने चाहिए। **अनिल बिरमानी**, चेयरमैन लखनऊ व्यापार मंडल

**उद्यमियों चार्टेड एकाउंटेंट ने जताई उम्मीद**

# कौशल में निखार से खुलेंगे रोजगार के द्वार, बढ़ेंगे उद्योग

**कार्यालय संवाददाता, लखनऊ**

**अमृत विचार :** केंद्रीय बजट-2024 लघु उद्योगों को बढ़ावा देगा और रोजगार के द्वार खोलेगा। इकाइयों में कौशल के प्रशिक्षण से निखार आएगा तो कृषि क्षेत्र को भी पंख लगेंगे। इससे उद्यमियों के साथ किसान और महिलाएं समृद्ध होंगी। ये बातें मंगलवार को पेश हुए बजट पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) में पदाधिकारियों व सदस्यों ने कहीं।

मीटिंग हॉल में शहर के उद्यमी, चार्टेड एकाउंटेंट, सीआईआई के सदस्य व पदाधिकारियों ने एलईडी पर केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट देखा। बजट में किस क्षेत्र को क्या मिला इसको लेकर चर्चा हुई। ज्यादातर ने इसे सराहा, जबकि न के बराबर लोगों ने बजट मामूली बताया। कहा, यह अब तक का सबसे अच्छा बजट है। इसमें लघु उद्योग, कृषि, रोजगार, प्रशिक्षण और महिलाओं का ध्यान रखा गया है।

वहीं, इकाइयों में 60 फीसद अनुभवी कर्मियों व श्रमिकों की कमी है। जो सरकार युवाओं को कौशल विकास के तहत उन ट्रेड का प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण केंद्र बनाएगी। प्रशिक्षण पाए कर्मियों व श्रमिकों के काम से निखार आएगा और कमी पूरी होगी। सरकार ने कृषि क्षेत्र पर भी फोकस किया है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, आलू आदि फसलों से हटकर बायो एग्री यूनिट लगाकर काम होगा। इसके रिसर्च सेंटर बनेंगे और भी बदलाव सरकार करेगी। इसके लिए बजट की कमी नहीं रहेगी। महिलाएं भी लघु उद्योग लगाकर आत्मनिर्भर बनेंगी। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन से काफी बदलाव आएगा।

बजट पर चर्चा करते भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के पदाधिकारी। अमृत विचार

सैलरी व टैक्स को लेकर बजट मामूली है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। 25 हजार रुपये से ऊपर टैक्स भरने वालों को फायदा होगा। – **मुमताज अली खां**, पूर्व एचआर हेड, टाटा मोटर्स



बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं व एमएसएमई को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कैपिटल मार्केट के लिए बजट सही नहीं है। – **स्मिता अग्रवाल**, चेयरपर्सन, सीआईआई



बजट अच्छा है। खासकर एमएसएमई के लिए। इससे उद्योग में उपलब्धियां हासिल होंगी। केंद्र की आगे बढ़ने की सोच अच्छी है। – **वासुदेव चावला**, सीएमडी, महेश नमकीन प्रा.लि



सरकार ने स्किल पर फोकस किया है। जो उद्योगों के ट्रेड से जुड़ा प्रशिक्षण देगी। इससे इकाइयों में अनुभवी श्रमिकों की कमी पूरी होगी और गुणवत्ता आएगी। बायो एग्री यूनिट से कृषि का क्षेत्रफल बढ़ेगा। – **राघव कृष्ण**, चेयरमैन यंग इंडिया व चार्टेड एकाउंटेंट

**ऋण से बढ़ेंगे छोटे कारोबार**

एमएसएमई के लिए जो बजट आया, उससे कई योजनाएं आएंगी और जरूरतमंद आसानी से छोटा ऋण लेकर उद्योग लगा सकेंगे। इससे रोजगार बढ़ेगा।

# ज्वेलरी इंडस्ट्री की चमक सोने जैसी बढ़ाने वाला निर्णय : इब्जा

**कार्यालय संवाददाता, लखनऊ**

**अमृत विचार :** निश्चित तौर पर सोने की इंडस्ट्री के लिए बजट बहुत अच्छा है। न केवल कारोबार की चमक सोने जैसी होगी बल्कि आमजन के लिए भी राहत देने वाली है। एसोसिएशन की ओर से वर्षों से उठाई जा रही इस मांग को सरकार ने माना है।

इसके लिए सरकार का संगठन की ओर से आभार। ज्वैलरी इंडस्ट्री के हित के लिए कस्टम ड्यूटी घटाने की मांग बार-बार उठाई जा रही थी। कई बार सरकार से वार्ता और पत्राचार हुआ। सरकार के समक्ष 12 सूत्रीय डिमांड रखी गई थी। 15 प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी घटकर 6 फीसद रह गई है। लगभग 9 प्रतिशत भाव गिरेगा। इससे जो लोग सोने से दूर हो रहे थे अब उनका रुझान फिर से पीली धातु की ओर होगा। इससे सोना खरीद बढ़ेगी साथ ही तस्करी पर भी फर्क पड़ेगा। यह इंडस्ट्री और आमजन के लिए सरकार का उपहार है। **अनुराग रस्तोगी,** स्टेट हेड इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (इब्जा)



केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से अनेकों बार पत्राचार किया गया। इससे तस्करी रुकेगी। ज्वेलरी उद्योग को गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने संगठन की इस मांग को 2024 के बजट में शामिल करने सर्राफा को बड़ी राहत दी है। इससे स्वर्ण कारोबार की ओर आमजन फिर से लौटेगा। साथ ही ईडी और डीआरआई एजेंसियों के दंश से व्यापारियों को खासी राहत मिलेगी। –**आदीश कुमार जैन सर्राफ**, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सराफा एसोसिएशन चौक लखनऊ



सोने चांदी पर ड्यूटी कम किए जाने की मांग थी। सहालग वाले परिवार में 5 से 15 लाख तक की ज्वैलरी की खरीदी होती है। ड्यूटी घटाने से कारोबार में चमक आएगी। ड्यूटी कम होने कारण से स्मगलिंग पर भी रोक लगेगी। –**विनोद महेश्वरी**, संयोजक, आल इण्डिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन

# उम्मीदों के पथ पर कृषि और कारोबार प्रदेश में बनेंगे 2000 नए ग्रामीण मार्ग

**कार्यालय संवाददाता,लखनऊ**

**अमृत विचारः** बजट में प्रदेश के हाइवे और सड़कों के लिए 40 हजार करोड़ की राशि मिल सकती है। इससे प्रदेश में करीब दो हजार नए ग्रामीण मार्ग बनेंगे। नई सड़कें बनने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। साथ ही कृषि और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

एनएच के मुख्य अभियंता अरविंद कुमार जैन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 11737 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में यूपी में हाईवे के विकास के लिए केंद्र से 25 हजार करोड़ रुपये मिले थे। साथ ही राज्य सरकार की सहमति पर 50 से अधिक राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया। केंद्रीय बजट में पिछले साल के मुकाबले 15 हजार करोड़ ज्यादा बजट मिलने से नए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2023-24 में इस मद में करीब 60 करोड़ रुपये मिले थे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का चौथा चरण शुरू करने का एलान किया है। योजना के लिए पात्र ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इस दायरे में प्रदेश की दो हजार नई सड़कें आएंगी। यूपी में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों और एक किमी या अधिक लंबी सड़कों को नाबार्ड की सहायता से बनाया जा रहा है। एक किमी से कम लंबी सड़कों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत बनाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पीएमजीएसवाई के चौथे चरण से प्रदेश में ग्रामीण सड़कों का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

## मानवता को मिलेगा जहरमुक्त अनाज

मोदी सरकार के 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं, शिक्षा, कौशल और रोजगार पर बल दिया है। सबसे बड़ा कदम कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने का किया है। 1 वर्ष में एक करोड़ किसानों को इस दायरे में लाया जाएगा और आगे भी प्रत्येक वर्ष इस संख्या में वृद्धि की जाएगी। इसके अतिरिक्त उनके उत्पादों के प्रमाणीकरण एवं ब्रांडिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। चूंकि प्राकृतिक कृषि में किसानों की उत्पादन लागत न्यूनतम होती है, यह कदम निश्चित ही उनकी आय को दोगुनी करने में मदद करेगा और साथ ही मानवता को जहर मुक्त अनाज उपलब्ध हो सकेगा। दलहन और तिलहन में आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए उत्पादन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर बल दिया गया है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि को 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये किया गया है परंतु वित्त मंत्री से इसे कम से कम दोगुना करने की उम्मीद थी। –**प्रो. भारती पांडेय**, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, जय नारायण मिश्रा पी.जी. कॉलेज



## विकास को मजबूती से किया प्रोत्साहित

बजट देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाला है। इसमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चार मुख्य पहलुओं पर बल दिया गया है। बजट में रोजगार, कौशल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए उनके विकास को मजबूती से प्रोत्साहित किया गया है। पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने की घोषणा नई ऊर्जा और रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है, जिससे नए कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। पीएम पैकेज में तीन योजनाओं को शामिल किया गया है। जो सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए प्रवेशकों के लिए है, यह राशि 15,000 तक की 3 किश्तों में दी जाएगी। विनिर्माण में रोजगार सृजन के लिए बी योजना में प्रोत्साहन से 30 लाख युवाओं को लाभ होने की उम्मीद है। योजना सी में सरकार सभी नई नियुक्तियों के लिए 2 वर्षों के लिए 3,000 तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति करेगी। रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा ने युवाओं के लिए बड़ी राहत प्रदान की है। – **डॉ. अनामिका चौधरी,** विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय



## व्यापारी नेता बोले

कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाए जाने का स्वागत है। व्यापारियों के लिए बजट पूरी तरह से निराशानक है। सिर्फ आंकड़ों की चाशनी में लपेटा गया है। इसमें सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का ही ख्याल रखा गया है। यूपी समेत देश के अन्य प्रांतों को स्थान नहीं मिला है। मुद्रा लोन की सीमा 20 लाख की, मगर यह उसे ही मिलेगा जो अपना दस लाख जमा कर चुका है तो क्या फायदा? एक व्यापारी को चलता व्यापार बढ़ाने के लिए पूंजी जरूरी है। –**राजेंद्र अग्रवाल**, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल



व्यापार मंदा पड़ा है। महंगाई ने पहले से ही आमजन की कमर तोड़ रखी है। यूपी को इस बार बिल्कुल भूल गई सरकार। इस बजट में शायद सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर ज्यादा चिंतित दिखी। व्यापारी के लिए राहत के नाम पर आंकड़े हैं। जीएसटी आज भी व्यापारियों के लिए पहेली बनी हुई है। बस मोबाइल और सोना को लेकर जरूर राहत देने की कोशिश हुई है। व्यापारियों के लिए बजट में कुछ नहीं है। –**जितेंद्र सिंह चौहान**, प्रदेश अध्यक्ष स्टेशनरी



व्यापारी समाज के लिए एक निराशाजनक बजट है। इसमें चुनावी गठबंधन का असर साफ दिख रहा है। बिहार, आंध्र प्रदेश और कुछ हद तक ओडिशा एवं असम के लिए है। व्यापारियों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स में आय की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए थी। लोकल ट्रेडर्स को संरक्षित करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। ई कॉमर्स पॉलिसी पर भी ध्यान नहीं दिया गया। सात वर्ष से जीएसटी को लेकर सरकार के प्रयोग जारी हैं। ना तो ट्रिब्यूनल बन पाया न रुका अफसरों का उत्पीड़न।– **अमरनाथ मिश्र**, अध्यक्ष लखनऊ व्यापार मंडल



टेक्सटाइल पर कस्टम छूट का फायदा जनता को नहीं मिलेगा। आम बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए कुछ नहीं है। आंकड़ों की बाजीगरी है। पूर्व में जिलाधिकारी और जीएसटी कमिश्नर के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के लिए तमाम सुझाव दिए गए। एक पर भी विचार नहीं हुआ। जीएसटी की विसंगतियों पर भी ध्यान नहीं दिया गया। 7 साल में जीएसटी ट्रिब्यूनल तक नहीं बन पाई। –**पवन मनोचा**, वरिष्ठ महामंत्री लखनऊ व्यापार मंडल



बजट में महंगाई को कम करने पर ध्यान नहीं दिया गया है। सोना चांदी पर आयात शुल्क कम करने की जगह सब्जी और राशन सस्ता होना चाहिए। बिजली, डीजल, पेट्रोल सब महंगा है। निम्न और मध्यम वर्ग के लिए बजट में कुछ नहीं है। महंगाई है इस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। मोबाइल और चार्जर पर राहत दी गई है। लेकिन यह आइटम आमजन एक बार खरीदता है और महीनों उसका इस्तेमाल करता है। –**एकता पांडे**, फर्नीचर व्यापारी



व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है। कैंसर की दवा सस्ती की गई है। मध्यम वर्ग के लिए स्लैब में अंतर लाया गया है। जो पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर है। व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है। निराशाजनक है। मोबाइल में एक्साइज डयूटी घटने से आमजन को लाभ मिलेगा। यूपी को कुछ नहीं मिला। 60 नंबर दिए जा सकते हैं। कई मांगों और सुझावों पर इस बार भी विचार नहीं हुआ। कई मांगे लंबित है जिन पर सरकार ने विचार नहीं किया।–**देवेंद्र गुप्ता**, अध्यक्ष भूतनाथ व्यापार मंडल



बजट काफी हद तक सही है। लेकिन, आयकर के स्लैब में रियायत की आवश्यकता है। 25 लाख तक केवल 5 फीसदी ही आयकर होना चाहिए क्योंकि जब प्रतिशत है तो 100 पर 5 तो 25 लाख में भी उसी अनुपात में टैक्स बनेगा। जितना कम टैक्स होगा उतनी अधिक रेवेन्यू आएगा। ये फंडा सरकार समझ जाए तो काफी लाभ में रहेगी और व्यापार के अलावा कारोबारियों का हित होगा। –**दीपक सिंघल**, अध्यक्ष, लखनऊ सीमेंट एसोसिएशन एवं व्यापारी

**फोकस**

# महिलाओं की भागीदारी दिखाएगी रंग

**कार्यालय संवाददाता,लखनऊ**

**अमृत विचारः** भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने के सरकार के प्रयास श्रम गहन उत्पादन, इसकी कौशल पहल, औपचारिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की दिशा में दिखाई देते हैं।

गोमती नगर निवासी दिनेश कुमार सिंह ने मार्च 2022 में मुद्रा लोन लिया था। अब वह एक सफल व्यवसायी है। उनका कहना है कि व्यापार आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लोन की राशि को 20 लाख रुपए करना सराहनीय है। मुद्रा लोन छोटे उद्यमियों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा हैं।

चौक निवासी भारती लाल ने बताया कि उन्होंने मुद्रा लोन लेकर व्यवसाय की शुरूआत की थी। वह व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाह रहे थे जिसके लिए और धन की आवश्यकता थी। अब जब मुद्रा लोन की राशि बढ़ गई है तो वह अधिक राशि का लोन लेकर व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे।





गोमती नगर स्थित आईआईए भवन के सभागार में बजट पर चर्चा करते लोग। अमृत विचार



बजट में नई कर व्यवस्था कायम रहेगी। पुरानी कर व्यवस्था धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक बचत और मध्यम वर्ग का प्रोत्साहन पर जोर नदारद है। मानक कटौती में वृद्धि से सेवा वर्ग को लाभ होता है। व्यक्तिगत और एचयूएफ के मामले में कर की अधिकतम दर 30 प्रतिशत को घटाकर कॉर्पोरेट कर 25 प्रतिशत के अनुरूप किया जाना चाहिए। –**सीए जयंत पाण्डेय**

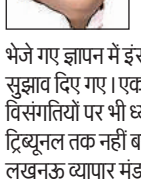

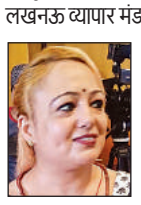



अगर हमें 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य पूरा करना है तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास परिवारों के हाथ में पैसा होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर छठ की सीमा को 125000 तक किया गया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निर्धारित किया गया, जो की अब तक सबसे ज्यादा एलोकेशन है। –**सीए आशीष कुमार पाठक**, पूर्व चेयरमैन आईसीए



इस बजट के साथ सरकार का लक्ष्य कर कानूनों को सरल बनाना और नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं को प्रोत्साहित करना है। सरकार का लक्ष्य विवाद से विश्वास योजना शुरू करके मुकदमेबाजी को कम करना भी है। हालांकि सरकार ने शेयर बाजार लेनदेन पर कर बढ़ाकर राजस्व में वृद्धि की है। क्योंकि अधिक करदाताओं ने शेयर बाजार में निवेश करना शुरू कर दिया है। –**सीए सार्थक जैन**

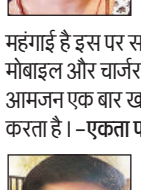

बजट में दो मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया है। पहला युवाओं को मज़बूत बनाना। दूसरा बुनियादी ढांचे के विकास के ज़रिए एक विकसित भारत बनाना। बजट में युवाओं के लिए रोज़गार के तीन नए कार्यक्रम बताए गए हैं जो बेरोज़गारी की समस्या दूर करने में मदद करेंगे। साथ ही स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के लिए एंजेल टैक्स खत्म करने से उन्हें काफी फायदा होगा। –**विनम्र गर्ग** इन्वेस्टवेज़ फिनसर्व, सीनियर एसोसिएट

पहली बार काम करने वालों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के साथ आयकर स्लैब में बदलाव से खर्च योग्य आय में वृद्धि करके, विशेष रूप से छोटी टिकट वस्तुओं के लिए खपत को बढ़ावा मिलने की संभावना है। बजट का नीति मिश्रण, जिसमें निरंतर पूंजीगत व्यय, रोजगार सृजन, विनिर्माण, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्थन शामिल है। –अभीक बरुआ, मुख्य अर्थशास्त्री, एचडीएफसी बैंक

छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा लोन योजना को 10 से 20 लाख रुपए बढाया जाना है। इससे उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। ऋण जमानुपात सुधरेगा और बैंको के लिए लोन पोर्टफोलियो बढ़ाये जाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। –मनीष पाठक एलडीएम, लखनऊ



आयकरदाताओं को इस बजट से बहुत अधिक आशाएं थीं, लेकिन उन्हे बहुत कम लाभ इस बजट में प्रदान किए गए हैं। वेतन आय पर जो स्टैन्डर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपए का मिलता था, उसे बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। शेयर बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन पर छूट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन पाने वालों को मिलने वाली छूट की सीमा को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दिया गया है। इन पर मिलने वाली छूट में और अधिक वृद्धि की उम्मीद करदाताओं को थी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है जो करदाताओं के हित में नही है। –**सीए अनुराग पाण्डेय**,वाइस चेयरमैन एवं ट्रेजरार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया,लखनऊ शाखा

अमृत विचार
एक सम्पूर्ण अखबार
अपने आसपास की घटना, आयोजन की सूचना और फोटो हमें भेजें। इसे अखबार में प्रकाशित किया जाएगा।
इमेल
lkocityreporter@amritvichar.com
व्हाट्सएप
8112979390

**मौसम**

बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने की संभावना है।

| 38.5⁰ | 39.3⁰ |
|---|---|
| अधिकतम तापमान | न्यूनतम तापमान |

**शहर में आज**

- गोमती नगर विजयंत खंड स्टेडियम में आइटा टेनिस चैंपियनशिप के मैच- 9:00 बजे।
- इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा नारायण प्लाजा में मेडनॉल डायबिटिक केयर की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर- 10:00 बजे।
- नरही प्राथमिक विद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी डॉ. दरबारी लाल अस्थाना का जन्मोत्सव कार्यक्रम- 11:00 बजे।
- केजीएमयू के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रुमेटोलॉजी विभाग में विश्व स्जोग्रेन दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम- 11:00 बजे।
- चौक स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग के मुकाबले- 3:00 बजे।

# नौबस्ता में उल्टी-दस्त के 40 और मरीज मिले

## 25 मरीज बुखार के, स्वास्थ्य विभाग ने जांच कर दीं दवाएं

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार :** फैजुल्लागंज के नौबस्ता में मरीज मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। मंगलवार को मोहल्ले में उल्टी-दस्त के 40 और मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन मरीजों की जांच कर दवाएं दीं। शिविर में 80 से अधिक मरीज दवा लेने के लिए पहुंचे। करीब 25 लोग बुखार से भी पीड़ित मिले।

नौबस्ता में दूषित पानी पीने से बीमारियां फैल गई हैं। मोहल्ले में करीब 150 लोग बीमार हैं। जानकारी मिलने पर सोमवार को स्वास्थ्य शिविर लगाकर कर मरीजों की जांच कर दवाएं दी गईं थीं। मंगलवार को भी शिविर लगाया गया। एडी मंडल डॉ. जीपी गुप्ता और अलीगंज सीएचसी की टीम ने मोहल्ले का निरीक्षण किया। डॉक्टरों के अनुसार डायरिया के हल्के लक्षण वाले मरीज सामने आ रहे हैं। मंगलवार को शिविर में करीब 80 मरीज आए। इसमें 40 को दस्त व उल्टी की समस्या थी। कोई भी मरीज गंभीर नहीं था। डायरिया को लेकर लोगों में दहशत हैं। लोग टंकी का पानी पीने से घबरा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर-घर जाकर क्लोरीन की गोलियां बांटीं हैं। एक गोली को 20 लीटर पानी में घोलकर पीने की सलाह दी है।

### बलरामपुर व रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में पानी का संकट

**अमृत विचार, लखनऊ :** बलरामपुर और रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल की बोरिंगें खराब होने से पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। वार्डों से लेकर शौचालयों तक पानी की आपूर्ति ठप होने से मरीज और तीमारदार परेशान हैं। रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में वैकल्पिक व्यवस्था के लिए लगाए गए टैंकर नाकाफी साबित हो रहे हैं।

राजाजीपुरम स्थित 100 बेड वाले रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में हर समय 40-50 मरीज भर्ती रहते हैं। तीन दिन पहले अस्पताल की बोरिंग खराब हो गई थी। शौचालय में भी पानी की आपूर्ति ठप है। मरीज व तीमारदार पानी लिए परेशान हैं। भर्ती मरीजों के तीमारदार पीने के लिए पानी घर से ला रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जलकल के टैंकर लगाए गए हैं लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मंगलवार को भी बोरिंग ठीक नहीं हो पाई। सीएमएस डॉ. श्याम व्यास ने बताया बोरिंग मरम्मत का काम चल रहा है।

उधर, मंगलवार सुबह बलरामपुर अस्पताल की पुरानी बोरिंग भी खराब हो गई। इससे पानी की आपूर्ति बंद हो गई। इमरजेंसी समेत सभी वार्डों और शौचालय में पानी की आपूर्ति ठप हो गई। जानकारी पर अधिकारियों ने बोरिंग ठीक कराने के निर्देश दिए। आनन-फानन मरम्मत का काम शुरू हुआ, लेकिन देर शाम तक बोरिंग ठीक नहीं हो पाई थी। अस्पताल प्रशासन का कहना है बोरिंग ठीक करने का काम चल रहा है।

### तीन जोन में सफाई का टेंडर निरस्त

**अमृत विचार, लखनऊ :** तीन जोन में सफाई के लिए निकाले गए टेंडर को नगर निगम ने खींचतान के बीच निरस्त कर दिया है। रिटेंडर कराने के बाद कंपनियों को शामिल होने के लिए 14 दिन का समय देगा। बताया जा रहा है कि लखनऊ की फर्म को सफाई का काम देने पर पेंच फंस गया। जोन तीन, पांच और आठ के 33 वार्डों में साफ-सफाई के लिए नगर निगम ने टेंडर निकाला गया था। इसमें लखनऊ की लॉयन सिक्योरिटी, बेगलुरु की स्वच्छता कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र की कंपनी बीवीजी का अंतिम चयन हुआ था। बताया जा रहा है कि पार्षद लखनऊ की फर्म लॉयन सिक्योरिटी के पक्ष में हैं लेकिन अधिकारी लोकल कंपनी को काम नहीं देना चाहते हैं। वर्षों से सफाई का काम कर रही फर्म में 3,000 सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग लगे हैं। इनकी हाजिरी में गड़बड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने सफाई के लिए बड़ी कंपनी लाने का निर्णय लिया था।

## सार-संक्षेप

### एक-दो दिन में मिटाए जाएंगे लाल निशान

**अमृत विचार, लखनऊ :** कुकरैल रिवर फ्रंट बनाने के लिए अबरार नगर, पंत नगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर व खुर्रम नगर में मकानों पर लगाए गए लाल निशान की रिपोर्ट सिंचाई विभाग ने मंडलायुक्त को भेज दी है। इस आधार पर जांच शुरू हो गई है। वहीं, सिंचाई विभाग एक-दो दिन में मकानों से लाल निशान मिटाएगा। मामले की जांच कर रहीं मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब को दी गई रिपोर्ट में सिंचाई विभाग ने क्रॉस लगाने की बात स्वीकार की है। प्रक्रिया किसके आदेश पर, क्यों और किस आधार पर की गई रिपोर्ट में ये भी बताया है। मंगलवार को एलडीए से स्थानीय लोगों को फोन पर बताया कि एक दो दिन में निशान मिटा दिए जाएंगे।

### गरीब रथ में बढ़ाए जाएंगे वातानुकूलित तृतीय श्रेणी कोच

**अमृत विचार, लखनऊ :** ट्रेन नंबर 12537 व 12536 लखनऊ जंक्शन रायपुर और 12593 व 12594 लखनऊ जंक्शन भोपाल गरीब रथ एक्सप्रेस में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के अस्थाई रूप से चार अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। लखनऊ जंक्शन से 29 और रायपुर से 30 जुलाई से कोच लगेंगे। वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 14 कोच लगेंगे। लखनऊ जंक्शन से 3 अगस्त के स्थान पर 27 जुलाई से तथा भोपाल से 4 अगस्त के स्थान पर 28 जुलाई से वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के चार अतिरिक्त कोच लगेंगे। वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 14 कोच लगेंगे।

### उद्यान अधिकारी को नजूल पार्कों की जिम्मेदारी

**अमृत विचार, लखनऊ :** लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को अधीक्षण अभियंता व उद्यान अधिकारी के कार्यों का विभाजन किया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से स्थानांतरित होकर आए उद्यान अधिकारी शशि कुमार भारती को नजूल पार्कों की जिम्मेदारी दी है। वह नजूल पार्कों के औद्यानीकरण से सम्बंधित सभी कार्य करेंगे। वह पत्रावलियां अधीक्षण अभियंता के माध्यम से उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा आगरा विकास प्राधिकरण से स्थानांतरित होकर अधीक्षण अभियंता अवनीन्द्र कुमार सिंह को अभियंत्रण खंड के कार्यों की जिम्मेदारी दी है। वह अभियंत्रण खंड की सभी पत्रावलियां मुख्य अभियंता को प्रस्तुत करेंगे।

### उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए टीमें गठित

**अमृत विचार, लखनऊ :** राजधानी में उर्वरक की कालाबाजारी और ओवररेटिंग रोकने के लिए जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने आठ टीमें गठित कर दी हैं। विकासखंड वार नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि उर्वरक विक्रेताओं द्वारा किसानों को उनकी कृषि जोत फसल के अनुसार आधार कार्ड पर उर्वरक का वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि विक्रेता स्टॉक पंजिका, विक्रय पंजिका तथा रसीद अनिवार्य रूप से रखें। जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह ने बताया कि किसान किसान कालाबाजारी, ओवररेटिंग और जमाखोरी की शिकायत उनके सीयूजी नंबर 7839882167 पर कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर 9198938099 पर भी शिकायत की जा सकती है।

### कोई भी लाभार्थी नहीं छूटा, सचिव प्रमाण दें

**अमृत विचार, लखनऊ :** गांवों में चल रहे विशेष ग्रामसभा अभियान में व्यक्तिगत शौचालय के लिए बढ़े परिवारों का चयन करके सचिव फोटो उपलब्ध कराएं। इस अभियान से कोई भी लाभार्थी नहीं छूटा यह भी प्रमाण देंगे। मंगलवार को 75 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभा अभियान चलाया गया। इस दौरान पंचायती राज विभाग ने शौचालय आवंटित करने के लिए बढ़े परिवारों का चयन किया। सदस्यों से मौके पर जानकारी करके 575 ऑनलाइन आवेदन कराए। इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशू शेखर ठाकुर ने सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करके समीक्षा की। बताया 26 जुलाई तक अभियान चलेगा। कुल 14815 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य मिला है। दो दिन में 1132 लाभार्थी चयनित किए हैं। एक हजार से अधिक के ऑनलाइन आवेदन कराए हैं। संबंधित सचिव इस आयोजन की फोटो रोजाना शेयर करेंगे और कोई भी लाभार्थी नहीं छूटा इसका प्रमाण पत्र देंगे।

# रोडवेज के कर्मचारियों ने वर्कशॉप पर किया प्रदर्शन

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

- 22 सूत्री मांगों का ज्ञापन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को सौंपा

**अमृत विचार :** रोडवेज कर्मचारियों ने मंगलवार को अमौसी रोडवेज वर्कशॉप में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद 22 सूत्री मांगों का ज्ञापन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और सीनियर फोरमैन को सौंपा। हैदरगढ़ उपनगरीय डिपो के शाखा अध्यक्ष ने नोटिस मांग पत्र चारबाग डिपो एआरएम को दिया।

भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ प्रांत के आह्वान हुए धरने का नेतृत्व प्रदेश प्रभारी मोहम्मद नसीम ने किया। इसके बाद चारबाग डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जितेंद्र प्रसाद व सीनियर फोरमैन कुंवर राजकमल को मांग पत्र सौंपा गया। हैदरगढ़ उपनगरीय डिपो के शाखा अध्यक्ष सहदेव सिंह ने अगुवाई में कर्मचारियों ने जन जागरण आंदोलन को लेकर नोटिस मांग पत्र चारबाग डिपो के एआरएम को दिया।

संगठन के शाखा अध्यक्ष अब्दुल करीम, शाखा मंत्री राजेश कुमार शुक्ला, कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल कुद्दूस, उपाध्यक्ष मनोज कुमार कश्यप, प्रांतीय प्रतिनिधि राजमणि, मनप्रीत सिंह, फिरोज खान, साहिबे आलम, दीपक शर्मा, मनीष शुक्ला, गणेश दत्त पांडेय, अमरनाथ तिवारी, अबरार अहमद, फारुख हुसैन, रुसैद अब्बास, कंचन शर्मा, कमलेश यादव, ओम प्रकाश यादव व योगेंद्र यादव, आउटसोर्सिंग के गोलू, वसीम, सुरेश कुमार, अनिल कुमार और सनी शामिल रहे। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने नोटिस आंदोलन पत्र को शासन तक भेजने का आश्वासन दिया।

# 29 को विभूति खंड में लगेगा कर्मचारी भविष्य निधि का शिविर

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार:** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से निजी, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण करने के लिए 29 जुलाई को निधि आपके निकट 2.0 को जिला आउटरीच कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ परिक्षेत्र में आने वाले लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, हरदोई एवं रायबरेली जिलों में छह टीमें निधि आपके निकट 2.0 का आयोजन करेंगी। उन क्षेत्रों में निवास करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों, पेंशनरों, नियोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। मैसर्स एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड एप्को हाउस बी-9 विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ, मैसर्स सेकसरिया बिसवां शुगर फैक्ट्री लिमिटेड बीसवां सीतापुर, मैसर्स बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड लखीमपुर खीरी, मैसर्स एसएलएमजी बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड कुर्सी रोड बाराबंकी, मैसर्स ग्रीनप्लाई संडीला प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नं. एच 2संडीला,हरदोई और डीसी मनरेगा विकास भवन रायबरेली में शिविर लगाएंगे।

**बैठक** महापौर सुषमा खर्कवाल ने की जोन चार और पांच के कामकाज व गृहकर की समीक्षा

# गृहकर वसूली में नहीं लगाया जाएगा निजी कर्मचारी

कार्यालय संवाददाता लखनऊ

नगर निगम मुख्यालय के राजकुमार हॉल में समीक्षा करतीं महापौर।

- आशा आश्रम नाले की सफाई न होने पर ठेकेदार को नोटिस
- सम्पत्तियों के सर्वे की सूची क्षेत्रीय पार्षद को भी उपलब्ध कराएं

**अमृत विचार :** गृहकर वसूली में अब निजी कर्मचारी नहीं लगाया जाएगा। जोन पांच की समीक्षा में अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर महापौर ने ये आदेश मंगलवार को अधिकारियों को दिया। आशा आश्रम नाले की सफाई न करवाने पर ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जोन चार की समीक्षा के दौरान सम्पत्तियों के सर्वे की सूची क्षेत्रीय पार्षद को भी उपलब्ध कराने के लिए कहा।

महापौर सुषमा खर्कवाल ने जोनल कार्यालय में जोन पांच की समीक्षा की। इसमें गृहकर अवैध वसूली की शिकायत पर उन्होंने गृहकर वसूली में अब निजी कर्मचारी नहीं लगाया जाएगा। निजी कर्मचारी न भवन स्वामी के घर जाएगा और न ही जोनल कार्यालय बुलाया जाएगा। महापौर ने गृहकर निर्धारण व टैक्स सम्बंधी प्रकरण का जीआईएस समाधान दिवस में निस्तारण करने के निर्देश दिए। बिना खसरा, खतौनी व बिना रजिस्ट्री वाली संपत्तियों और कब्जे वाली नजूल की जमीनों को चिन्हित कर सूची तैयार कराएं। अपर आयुक्त ललित कुमार मौके पर जाकर सरोजनी नगर द्वितीय वार्ड में आशा आश्रम नाले की सफाई करवाने और ठेकेदार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिए। गुरुगोविंद सिंह वार्ड के आदर्श नगर और पटेल नगर में सर्वे करके व्यावसायिक सम्पत्तियां चिन्हित करने के लिए भी कहा।

लालबाग स्थित राजकुमार हॉल में जोन चार की समीक्षा बैठक में पार्षदों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। क्षेत्र की आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों का सर्वे कर एक सूची क्षेत्रीय पार्षद को भी उपलब्ध कराने और टैक्स वसूली के आदेश दिए। टैक्स वसूली की वार्ड वार फाइल बनाने के लिए भी कहा।

बिना शिलापट भुगतान करने पर भुगतान करने पर सम्बंधित अधिकारी पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया। पार्षदों ने सुएज इंडिया कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। महापौर अधिकारियों को जल्द से जल्द शिकायतों का निस्तारण करने के लिए कहा।

# रेलवे स्टेशनों पर क्यूआर डिवाइस लगाने का कार्य तेज

**अमृत विचार, लखनऊ :** पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्टेशनों पर क्रिस सीआरआईएस के जरिये क्यूआर डिवाइस लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

जिससे यात्रियों को यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध हो सके। लखनऊ मंडल पर डिजिटल भुगतान यूपीआई के लिए 268 क्यूआर डिवाइसों को क्रय किया गया है, जिन्हें इंस्टॉल किया जा रहा है। लखनऊ जंक्शन स्टेशन पर दो, ऐशबाग पर एक, डालीगंज पर एक एवं गोमती नगर पर एक यूनिट सहित चार स्टेशनों पर पांच यूनिट क्यूआर डिवाइस इंस्टॉल किया जा चुका है।


# नगर पंचायत जहाँगीरगंज, अम्बेडकरनगर

पत्रांकः मेमो / न0पं0 जहाँ0 / विज्ञापन / 2024–25 दिनांक : 23–07–2024.

## नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ समावेशी विकास का संकल्प

## संचारी रोग नियन्त्रण अभियान

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ जहाँगीरगंज

1. बुखार होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर जायें ।
2. सिर, हाथ–पांव एवं पेट पर सामान्य पट्टी रखें ।
3. बुखार के समय पानी एवं तरल पदार्थों जैसे नारियल पानी, शिकंजी, ताजा फलों का रस इत्यादि अधिक सेवन करें ।
4. हल्के सूती वस्त्र पहनें तथा कमरें को ठण्डा रखें
5. झोलाछाप चिकित्सकों से बचें।
6. बिना चिकित्सक की सलाह के अनावश्यक औषधियों का सेवन न करें ।

**अपील**

1. नगर पंचायत को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें ताकि स्वच्छता की रैंकिंग में नगर पंचायत जहाँगीरगंज को नं0 – 1 पर लाया जा सके ।
2. समस्त करों का भुगतान समय से करें ।
3. स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग करें एवं नगर को स्वच्छ साफ – सुथरा रखें ।
4. खुले में शौच न करें व्यक्तिगत शौचालय एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करें ।
5. नगर के समावेशी विकास में सत्त सहयोग करे ।
6. सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें ।

(विनय कुमार द्विवेदी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत जहॉगीरगंज, अम्बेडकरनगर

(सुनीता)
अध्यक्ष
नगर पंचायत जहॉगीरगंज, अम्बेडकरनगर



स्वच्छ सुलतानपुर! सुन्दर सुलतानपुर!

# कार्यालय नगर पालिका परिषद सुलतानपुर

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

## नागरिकों से अपील

1. नगर पालिका परिषद सुलतानपुर प्रत्येक वर्ष की भांति भारत सरकार द्वारा कराये जा रहे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में प्रतिभाग कर रही है। नगर पालिका परिषद सुलतानपुर समस्त जनमानस से अपील करती है कि नगर को स्वच्छ रखकर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सहयोग प्रदान करे।
2. स्वच्छता ऐप का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें तथा अपने नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में नम्बर 1 बनाएं।
3. खुले में शौच न करें, व्यक्तिगत/सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय का ही प्रयोग करें।
4. गीले व सूखे कूडे को अलग–अलग डस्टबिन में रखें तथा पालिका के सफाई कर्मचारियों के मांगने दें।
5. घर से निकलने वाले गीले कूड़े से होम कम्पोस्टिंग के माध्यम से निस्तारित करें।
6. कूड़ा सड़क, गली, नाले, नालियों तथा सार्वजनिक स्थानों पर न फेंकें डस्टबिन में एकत्रित कर नगर पालिका के स्वच्छता कर्मियों को दें, कूड़े में आग न लगायें।
7. सिंगल यूज प्लास्टिक एवं थर्माकोल से निर्मित सामग्री पूर्णतया प्रतिबन्धित है इसका प्रयोग न करें।
8. मच्छरजनित बीमारियों से बचाव हेतु अपने आस–पास सफाई रखें तथा गन्दे पानी को न इकट्ठा होने दें। पूरी आस्तीन के कपड़ों का प्रयोग करें।
9. कूलर, पुराने टायर, टूटी बाल्टी आदि में बरसात का पानी न रूकने दें।
10. सभी नागरिक अपशिष्ट प्रबन्धन अपनाकर अपने वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।
11. सभी नागरिक अपने आस–पास कम से कम एक वृक्षारोपण करें। स्वच्छता बनाये रखें और स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण को बढावा दें।
12. जल ही जीवन है इसे बर्बाद न करें व दूषित न करें, नलों व समर्सिबल पम्पों को खुला न छोड़ें।
13. पालिका द्वारा लाल डिग्गी वार्ड में पन्त स्टेडियम के पास निर्मित आर.आर.आर. सेन्टर पर पुरानी वस्तुएं (पुनर्उपयोग हेतु) देकर जरूरतमन्दों की मदद करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सुलतानपुर

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, सुलतानपुर

पत्रांकः 236/न0पा0परि0सुल0/2024–25 दिनांकः 23 जुलाई, 2024

पितृपैतामहं राज्यं प्राप्तवान् स्वेन कर्मणा।
वायुरभ्रमिवासाद्य भ्रंशयत्यनये स्थित: ॥

अन्याय के मार्ग पर चलने वाला राजा विरासत में मिले राज्य को उसी प्रकार से नष्ट कर देता है जैसे तेज हवा बादलों को छिन्न-भिन्न कर देती है।

## संपादकीय

# समावेशी बजट

मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पूर्ण बजट पेश हुआ। बजट में सरकार की ओर से सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की गई। बजट में युवा, किसान, उद्यमी, महिलाओं व नौकरी पेशा लोगों का ध्यान रखा गया है। साथ ही व्यापार तथा विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। नौकरी पेशा लोगों को पहले की तरह ही 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 7 लाख की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स देने का प्रावधान रखा गया है। पहले यह छूट 3 लाख से 6 लाख की आय पर थी। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए लोन गारंटी योजना का प्रावधान किया है,जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी। संकट से गुजर रहे एमएसएमई की कर्ज जरूरत सरकार समर्थित कोष से पूरी की जाएगी। साथ ही सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडीएस मंच पर अनिवार्य रूप से जुड़ने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी। सरकार के इस प्रावधान से निश्चित ही एमएसएमई क्षेत्र के उद्योग को बढ़ाने करने में मदद मिलेगी।

बजट में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स हटाने का प्रावधान किया गया है। एंजल कर को हटाने से स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे उनके लिए अधिक अनुकूल माहौल बनेगा। एंजेल टैक्स को देश में साल 2012 में लागू किया गया था। तब से इसको हटाने की मांग की जा रही थी। यह टैक्स उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता था, जो एंजेल निवेशकों से फंडिंग हासिल करते थे। बजट में इसके अतिरिक्त महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। ग्रामीण विकास को ध्यान रखते हुए बजट में ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं सरकार के हर व्यक्ति को छत देने के इरादे की झलक भी बजट में दिखी। बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही बजट में छात्रों के लिए शिक्षा ऋण व रोजगार शुरू करने के लिए सरल ऋण प्रक्रिया अपनाए जाने पर भी जोर दिया गया है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना कि चाहिए बजट के द्वारा सरकार ने सभी वर्गों को कुछ न कुछ दिया है।

# आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापक वित्तीय रोडमैप

रजत मेहरोत्रा
वित्तीय सलाहकार

बजट में शिक्षा में लिंग अंतर को पाटने और अधिक महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से एसटीईएम क्षेत्रों में महिला छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और अनुदान बढ़ाया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2024 का भारतीय बजट एक आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत के लिए बनाया गया एक व्यापक वित्तीय रोडमैप है। यह बजट आत्मनिर्भर रक्षा, आत्मनिर्भर कृषि, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) विकास, निर्यात वृद्धि, ग्रामीण उपभोग वृद्धि, युवा रोजगार क्षमता और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर देता है।

आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं को बढ़ानाः रक्षा बजट आवंटन में वृद्धि 2024 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह आवंटन भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बजट रक्षा क्षेत्र के भीतर 'मेक इन इंडिया' पहल को मजबूत करता है, जिसका लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू रक्षा निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन, कर छूट और सब्सिडी प्रदान करना। बजट नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने, रक्षा अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित करता है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) जैसे संगठनों के लिए धन में वृद्धि। रक्षा उत्पादों का निर्यात करने वाली कंपनियों के लिए कर छूट और सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना।

एमएसएमई विकासः बजट में एमएसएमई के लिए वित्त तक पहुंच में सुधार के लिए कई उपाय पेश किए गए हैं, ऋणदाताओं के लिए जोखिम को कम करने और एमएसएमई के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी योजनाओं को बढ़ाना। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। एमएसएमई को उनकी पूंजी की लागत कम करने और उनके विकास और विस्तार का समर्थन करने के लिए सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करना। एमएसएमई को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार

> मनरेगा के लिए फंडिंग को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना और ग्रामीण गरीबों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत सुनिश्चित करना है।

करने में मदद करने के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। डिजिटल परिवर्तनः ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने सहित एमएसएमई के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम। बजट में एमएसएमई की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उपाय पेश किए गए हैं, जिनमें निर्यात-संबंधी लागत को कम करने और अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एमएसएमई को सब्सिडी प्रदान करना।

निर्यात वृद्धि : बजट में व्यापार बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बंदरगाहों की क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए उनका आधुनिकीकरण करना, टर्नअराउंड समय को कम करना और व्यापार रसद में सुधार करना। माल की सुचारू आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और लॉजिस्टिक बाधाओं को कम करने के लिए सड़क, रेलवे और हवाई अड्डों सहित परिवहन नेटवर्क का विकास करना। निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले आयातित इनपुट पर सीमा शुल्क वापस करने के लिए शुल्क वापसी योजनाओं को बढ़ाना। वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से बजट में 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एमएसएमई और अन्य निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने में सहायता करना, उनकी विश्वसनीयता और विपणन क्षमता को बढ़ाना। ग्रामीण उपभोग विकास : बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं किसानों के लिए उत्पादन लागत कम करने के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करना। बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आरआईडीएफ को 40,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें कनेक्टिविटी और बाजारों तक पहुंच में सुधार के लिए ग्रामीण सड़कों का निर्माण और उन्नयन है। कृषि के लिए विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने और फसल की पैदावार में सुधार करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को वित्त पोषित करना।

बजट में मनरेगा के लिए फंडिंग को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना और ग्रामीण गरीबों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत सुनिश्चित करना है। युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, बजट में कौशल भारत मिशन के विस्तार पर जोर दिया गया है, स्टार्टअप्स को विकास के शुरुआती चरणों में मदद करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सीड फंडिंग बढ़ाना। उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को संसाधन, सलाह और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करने के लिए और अधिक इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित करना।

महिला सशक्तिकरणः बजट में महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए कई उपाय पेश किए गए हैं। 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला उद्यमियों के लिए ऋण तक आसान पहुंच को शामिल किया गया। बजट में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए 30,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करना। बजट में शिक्षा में लिंग अंतर को पाटने और अधिक महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से एसटीईएम क्षेत्रों में महिला छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और अनुदान बढ़ाया गया है। बजट में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई पहलों के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिलाओं के लिए हेल्पलाइन और सहायता केंद्र स्थापित करना, उन्हें तत्काल सहायता और सहायता प्रदान करना।

कृषि क्षेत्रः कृषि सब्सिडी के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। किसानों पर लागत का बोझ कम करने और फसल उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक सब्सिडी का आवंटन बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। कीट-संबंधी मुद्दों के समाधान और फसल की पैदावार की सुरक्षा के लिए कीटनाशक सब्सिडी के लिए धन बढ़ाया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तंत्र किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए बजट में एमएसपी तंत्र को मजबूत करने के उपायों की रूपरेखा दी गई है। किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान करने और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए गेहूं, चावल और दालों जैसी प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी में 5-10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

बजट में एक गारंटी योजना शुरू करने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार की कीमतें गारंटी स्तर से नीचे आने पर भी किसानों को एमएसपी मिले। फसल की किस्मों, कीट नियंत्रण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों में अनुसंधान का समर्थन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जैसे संस्थानों के लिए धन में वृद्धि। बदलते मौसम के मिजाज के अनुकूल होने और स्थिर कृषि उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए जलवायु-लचीला फसल किस्मों के अनुसंधान और विकास में निवेश करना। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। फंडिंग को नई नहरों, जलाशयों और पाइप लाइनों के निर्माण सहित सिंचाई कवरेज का विस्तार करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 40,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और किसानों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करने के लिए कृषि बाजारों और भंडारण सुविधाओं का विकास। कहा जा सकता है कि बजट से सभी वर्गों को लाभ होगा।

## प्रसंगवश

# बजट से बैसाखियों की मजबूती

वर्ष का पूर्ण आम बजट आ गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दो नारे याद आ गए। पहलाः "सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास"। दूसराः"न खाएंगे न खाने देंगे"। ये नारे हमें अकारण नहीं याद आए हैं।

बजट देखकर प्रतिक्रिया स्वरूप ये स्मरण हो आए। बताते चलें कि वर्तमान में केन्द्र में पदस्थ मोदी सरकार का अपने दल का बहुमत नहीं है। वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नाइडू की तेलगू देशम पार्टी की बैसाखियों पर टिकी है। बजट में इन राज्यों को दिल खोलकर वित्तीय पैकेज दिए गए। बिहार को 26 हजार करोड़ तो अकेले सड़क निर्माण हेतु ही दिए। कुछ और भी। कुल मिलाकर 58900 करोड़ की सौगात दी गई। नाइडू को विभिन्न मदों में पचास हजार करोड़ की मदद का ऐलान हुआ है। अब सवाल यह है कि कहीं तो मणिपुर जैसा राज्य है, जहां हिंसा और अभद्रता का तांडव चल रहा है और पीएम ने कोई सुधि नहीं ली। वहां झांकने तक नहीं गए और जिन राज्यों के मुखिया मोदी की सरकार संभाले हैं, उन्हें सब कुछ। क्या देश चलाने का यही सिद्धांत होना चाहिए कि जिससे तात्कालिक स्वार्थ सिद्ध होता हो वही अपना। तब तो नारा यह होना चाहिए,"जो हमारा खास,बस उसका विकास"। अब हम दूसरे नारे पर आते हैं। खाने कमाने से संबंधित। नीतीश का शासन बिहार में लंबे समय से है।

रघोत्तम शुक्ला
सेवानिवृत्त पीसीएस

पिछले दिनों जिस तरह धड़ाधड़ पुल टूटे बहे, उससे नीतीश के सुशासन की कलई खुल गई। केवल कुछ इंजीनियर निलंबित हुए। क्या इन घटिया पुलों के निर्माण में की गई कमाई अकेले इंजीनियर हजम कर सके होंगे? नहीं। हिस्सा ऊपर तक गया होगा, लेकिन फंदा पतली गर्दन में आसानी से पड़ता है। उन्हें तो अल्पांश ही मिलता है। कहावत है "खाए बांदर। मरैं कूकुर"। अब फिर से भारी रकमें मिल रही हैं। कार्यों की जैसी गुणवत्ता होगी,आगे चलकर मालूम हो जाएगा। हां प्रसन्न नीतीश मोदी सरकार के बैसाखी लगाए रहेंगे। रही चन्द्रबाबू नाइडू की बात, तो वे तो घोटालों में जेल में रह चुके हैं। जो भी हो बजट से मोदी ने अपनी बैसाखियां मजबूत कर लीं।

# आस्था और सामाजिक सद्भाव

प्रसिद्ध सावन मास आरंभ हो चुका है। इसके साथ शुरू हो चुकी है, शिव भक्तों की कठिन कांवड़ यात्र,जिसमें कई दिनों की हजारों लोग पैदल यात्रा कर हरिद्वार या अन्य गंगा घाटों से गंगाजल लाकर महादेव का अभिषेक करने की परंपरा है। यूपी सरकार के आदेश के बाद कि कांवड़ियों के मार्ग में जितनी भी दुकाने, ठेले और होटल इत्यादि हैं उनमें कारोबारी का नाम व पहचान अंकित करना आवश्यक है, राजनीतिक हलचलों के साथ सोशल मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव की भांति आदेश के समर्थन व विरोध में लामबंदी भी शुरू हो गई है। यूपी सरकार के पश्चात उत्तराखंड सरकार ने भी इसी प्रकार का आदेश जारी कर दिया था।

हालांकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है। आदेश के पक्ष में सरकार व प्रशासन के अपने तर्क हो सकते हैं,परंतु आदेश के पश्चात जो सब्जियों पर थूकने, खाद्य सामग्री पर मूत्र विसर्जन के वीडियो व संदेश वायरल हो रहे हैं,वे दोनों ही समुदायों में पारस्परिक नफरत और अविश्वास का बीज बोने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही गंगा जमुना तहजीब को भी ध्वस्त करने में धीमे जहर का कार्य कर रही है। हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया के इस दौर में सच और झूठ का प्रोपेगेंडा विभिन्न समूहों द्वारा निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। सरकार व प्रशासन को चाहिए कि ऐसे वीडियो और संदेशों की सत्यता की जांच करवाए और दोषी व्यक्ति चाहे किसी भी समुदाय के हों,उन्हें उचित दंड दिया जाए,क्योंकि मुट्ठी भर लोगों के उन्माद की कीमत सांप्रदायिक सौहार्द नहीं हो सकती। साथ ही खान-पान की शुचिता

बीना नयाल
लेखिका, अल्मोड़ा

> देश व हमारी तरक्की का आधार सांप्रदायिक सद्भाव तथा शांति है। हम विलेज अर्थव्यवस्था से बहुत आगे निकलकर ग्लोबल अर्थव्यवस्था की रेस में है।

व पवित्रता हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। खान-पान की रोजमर्रा की वस्तुओं के उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग तथा भंडारण की प्रक्रिया में विभिन्न रसायनों के रूप में धीमे जहर का पहले से ही प्रयोग हो रहा है,जिसका परिणाम गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आ रहे हैं। अब उन्हें इस प्रकार नफरत रूपी जहर से विकृत करना शारीरिक व मानसिक रूप से तकलीफदेह तो है ही,सामाजिक समरसता पर भी आघात करने वाला घृणित कार्य है। इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ दोनों समुदायों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

हमारी तरक्की का आधार सांप्रदायिक सद्भाव तथा शांति है। हम विलेज अर्थव्यवस्था से बहुत आगे निकलकर ग्लोबल अर्थव्यवस्था की रेस में हैं। यदि इसी प्रकार नफरती जहर फैलता रहा तो शायद अपनी-अपनी जाति और धर्म की प्रधानता पर आधारित आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की और पलायन करना होगा। रही बात कांवड़ यात्रा की तो यह गहन आस्था और आत्मिक संयम का प्रतीक है। इसमें खान-पान के साथ जीवनशैली में शुद्धता तथा पवित्रता का ध्यान कांवड़िया ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार रखता है। आप आस्था को चाहे अंधविश्वास का नाम दें, लेकिन यह यात्रा सनातनी परंपरा का अहम हिस्सा है। इस यात्रा के दौरान संभव है कि हिंदुओं के होटलों के जिन बर्तनों में एक समय लहसुन प्याज का भोजन बनाया जाता है, थोड़ी देर पश्चात उन्हीं बर्तनों में शाकाहार के नाम पर कांवड़ियों का भी भोजन बनाया जाए। उपवास के दिनों में ऐसे भोजन के मामले में मैं स्वयं मुक्तभोगी हूं,जहां होटल के सामने बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा होता है व्रत का खाना,लेकिन कहीं न कहीं प्याज का उपयोग पहले से खाना पकाने के लिए हुआ होता है। अतः आवश्यक है इस यात्रा मार्ग में अधिक से अधिक शिविर लगाया जाएं।

यद्यपि ऐसे शिविर हमेशा से लगाए जाते हैं,जहां खान-पान की पूरी सुविधा और शुचिता के साथ कांवड़ियों के स्वास्थ्य और आराम की भी सुविधा का ध्यान रखा जाता है। अब ऐसे शिविर कम से कम दूरी में लगाने चाहिए, जिससे कांवड़ियों को भोजनालय या अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ज्यादा सोचना और भटकना न पड़े। आम लोगों को भी तन मन धन से सेवा का अवसर मिले। जब गुरुद्वारे में सिख लोग रोज लंगर लगा सकते हैं तो उचित दूरी पर शिविर भी अधिकाधिक मात्रा में लगाए जा सकते हैं,क्योंकि कई बार जबरन नियमों को थोप कर सामाजिक अविश्वास उत्पन्न करने से बेहतर है, मध्यम मार्ग निकालना,जिससे न भावनाएं भड़के,न विश्वास आहत हो और सात्विकता के साथ सांप्रदायिक सौहार्द भी बरकरार रहे। वैसे भी सावन का पवित्र माह सृजन का प्रतीक है न की विध्वंस का।

## सोशल फोरम

# धैर्य और समर्पण का महीना

जब बादल इकट्ठे होकर जमीन को नहलाने लगें। जमीन हरी घास सी तौलिया बांध मंद-मंद मुस्काए। बीज अखुए फोड़कर सलाम करने खड़े हो जाएं। नदियां भर पेट पानी पीकर इतराएं। तालाब शरारती बच्चों की तरह जगह-जगह खिलकर फैले हों। मिट्टी मक्खन बनकर फूली हो। हरी-हरी काई,मखमल की तरह जमीन पर टंकी हो। हवा जब खुद में नमी का वजन लेकर बदन को ताजगी दे जाए। तब जर्रा-जर्रा मुस्कुरा के कहता है,यही तो सावन का स्वाद है। जो दिल सावन में न झूमे, जिसे सावन की नरमी तरावट न दे, जिसमें सावन का भोलापन मासूमियत न भरे, जिसका दिल बड़ा और बराबरी की गवाही न दे,वह भला फुहारों के बीच नाचते सावन को समझा ही कब। सावन तो हर एक को बराबर आनंद देने का उत्सव है।

धरती पर मौजूद हर हृदय, जिसमें प्रेम है, उसमें ही तो सावन की आहट होगी। हे सावन मेरे दिल को ढक लो ताकि इसमें मोहब्बत के सिवा कुछ न रह जाए। मेरे दिल को ऐसा कर दे,जो संसार भर का जहर पी तो सके मगर दूसरों पर उगल न सके। मुझे खुद में समाकर मेरा वजूद मिटा दो मेरे सावन। पार्वती जी ने सबसे खूबसूरत महीनों में से एक सावन में तप करके दुनिया का सबसे शक्तिशाली, मासूम और समर्पित प्रेम शिव हासिल किया था, इसलिए मेरे लिए यह माह प्रेम को पाने का महीना है।

यह महीना धैर्य और समर्पण का महीना है। खुद के अंदर से सुई की नोक बराबर भी नफरत को खत्म करने का महीना है और सबसे बड़ी बात पिछले पूरे चक्र में की गई गलतियों के प्रायश्चित का महीना है,जब दिल प्रायश्चित के बाद साफ हो जाए, तब उसमें पहला पांव शिव रखते हैं और जिस हृदय में शिव पांव रख दें,वहां और कुछ रह ही क्यों जाएगा सिवाए शिव शिव के। सावन मंद-मंद मुझे खुद में घोल दे रहा है। अगर सावन गुजरता रहे और इसकी आहटें दिल में मचलती रहें, तब भी किसी हृदय में नफरत रह जाए, तो पृथ्वी पर उससे अभागा भला कौन सा हृदय होगा। यह तो खुद को मिटकर प्रकृति के साथ झूमने का वक्त है। मेरे शिव के पैतियाने बैठकर,हरी चादर ओढ़े भारत भूमि को निहारते रहने कह वक्त है। **-फेसबुक वॉल से**

हफीज किदवई
लेखक

# समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास जरूरी

बद्री प्रसाद सिंह
सेवानिवृत्त आईजी पुलिस, उप्र.

> सावन के कांवड़ मेले में ही रास्ते में सैकड़ों लंगर चला देते तो कांवड़ियों की भोजन समस्या समाप्त हो जाती और हिंदू-मुस्लिम होटलों का विवाद न होता। हिंदू धर्म में वर्ण तथा जाति व्यवस्था नासूर बनी हुई है, जिसके कारण बहुत से पिछड़े व दलित समाज के लोग ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध धर्म में दीक्षित हो रहे हैं। यदि घूम-घूम कर ये संत इस व्यवस्था की आलोचना कर सभी हिंदुओं को बराबरी का संदेश देते,तो इस कुप्रथा का अंत हो गया होता। कुंभ मेलों मे संतों का स्नान जुलूस "शोभा यात्रा" निकालने में आगे पीछे चलने में ही विवाद होता रहता है,जबकि संतों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग द्वेष आदि दुर्गुणों से मुक्त होना चाहिए।

प्रयाग विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र से एमए करने तथा भारतीय संस्कृति का अध्ययन करके धर्म और दर्शन के ज्ञान में कुछ वृद्धि की। तीर्थराज प्रयाग तथा देश की सांस्कृतिक एवं धार्मिक राजधानी काशी में नियुक्ति के समय कुछ विद्वत जनों का स्नेह मिला। पुलिस अधीक्षक पौड़ी की नियुक्ति काल में मैं अधिकतर लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश एवं हरिद्वार के बहुत से संत-महात्माओं के प्रवचनों को सुनने तथा उनसे वार्ता कर जिज्ञासा दूर करने का अवसर मिला, यद्यपि उन वार्ताओं में निराशा अधिक मिलती।

वर्ष 2010 में मुरादाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक था। एक दिन प्रातः घर के फोन ड्यूटी ने बताया कि शंकराचार्य जी आवास के फाटक पर खड़े हैं और सुरक्षा न मिलने से रुष्ट हैं। मैंने शंकराचार्य के विषय में पूछा तो वह नहीं बता सका, उनके सहायक ने फोन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शंकराचार्य जी हरिद्वार जा रहे हैं रास्ते के सभी जिलों में उन्हें सुरक्षा हेतु एस्कॉर्ट गाड़ी मिली, लेकिन यहां नहीं मिली जबकि डीजीपी कार्यालय ने वायरलेस से इसका आदेश दे दिया था। मैं तुरंत उनकी सुरक्षा हेतु एस्कॉर्ट लगा दूं और आकर उनसे माफी मांगू। मैं सोकर उठा ही था। मैंने दिखवाया तो पता चला ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। मैंने उनके सहायक को आदेश न मिलने की बात बताकर पूछा कि वह कहां के शंकराचार्य हैं तो वह बोले कि काशी के हैं। मैंने कहा कि देश में कुल चार पीठ ही हैं, जहां शंकराचार्य जी होते हैं, उनमें काशी नहीं है। तब वह मुझे बरगलाना चाहा तो मैंने धमकाया कि फर्जी शंकराचार्य बनने पर जेल भेज दूंगा तब वह गलती मान गए। बात से पता चला सहायक जी मेरे गांव के पड़ोस के रहने वाले सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी थे। उनके आग्रह पर मैंने जनपद की सीमा तक एस्कॉर्ट लगा दी। उन्होंने मुझे बुलाकर शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने को कहा जिसे मैंने विनम्रता से मनाकर दिया।

देश में न जाने कितने स्वयंभू शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, विश्वगुरु, महामंडलेश्वर आदि हिंदुओं को बरगला रहे हैं और शिष्यों को धन का मोह त्याग ने का उपदेश देकर अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं। आशाराम, राम रहीम तो कुछ ऐसे संत हैं, जिनको न्यायालय ने दंडित किया। देश में बहुत से ऐसे संत हैं जिन पर आरोप नहीं लगे या आरोप दबा दिए गए। बड़े नेताओं, अधिकारियों से संपर्क बढ़ाकर अकूत संपदा के स्वामी होने के बाद भी ऐसे धर्माचार्य जनहित या हिन्दू हित में शिक्षा, अस्पताल, अनाथालय, लंगर आदि चलाने में कोई रुचि नहीं लेते। यही नहीं, हिंदू धर्म में सदियों से व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में भी रुचि नहीं लेते।

सावन के कांवड़ मेले में ही रास्ते में सैकड़ों लंगर चला देते तो कांवड़ियों की भोजन समस्या समाप्त हो जाती और हिंदू-मुस्लिम होटलों का विवाद न होता। हिंदू धर्म में वर्ण तथा जाति व्यवस्था नासूर बनी हुई है, जिसके कारण बहुत से पिछड़े व दलित समाज के लोग ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध धर्म में दीक्षित हो रहे हैं। यदि घूम-घूम कर ये संत इस व्यवस्था की आलोचना कर सभी हिंदुओं को बराबरी का संदेश देते, तो इस कुप्रथा का अंत हो गया होता। कुंभ मेलों मे संतों का स्नान जुलूस "शोभा यात्रा" निकालने में आगे पीछे चलने में ही विवाद होता रहता है, जबकि संतों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग द्वेष आदि दुर्गुणों से मुक्त होना चाहिए। देश में बहुत से विद्वान, अनासक्त संत हैं, उन्हें आकर हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने हेतु ठोस प्रयास करना चाहिए।

हिंदू धर्म में प्रतिदिन नए पंथ, संप्रदाय बनते रहे हैं, उनके आचार्यों में शास्त्रार्थ होते रहते थे और पराजित संत जीते हुए का पंथ स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता था। आदि शंकराचार्य का मीमांसक मंडन मिश्र से हुए शास्त्रार्थ में मंडन पराजित होकर शंकराचार्य के शिष्य बन गए थे। धर्मांधता हिंदुओं का गुण कभी नहीं रहा। हम समझ लें कि "धुआं भरा हो जिन आंखों में नफरत का,उनसे कोई ख्वाब न देखा जाएगा।" सैकड़ों वर्षों देश पर मुस्लिम और ईसाई के द्वारा राज करने के बाद भी हिंदू धर्म न केवल बचा है, अपितु पल्लवित-पुष्पित हो रहा है। हमारे संत विश्व में हो रहे नव जागरण, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक उन्नति को दृष्टि में रखकर हिंदुओं को जागृत करें, जिससे देश और समाज प्रगति कर सके।

# जरूरतों को सीमित करना आवश्यक

दुनिया में बढ़ रहा है मिनिमलिज्म यानी कम सामानों में बेहतर जिंदगी कैसे जिए,अगर आप अपने जीवन को सरल और सहज बनाने की सोच रहे हैं तो जरूरतों को सीमित करना होगा। यह तनाव कम करने और बचत करने का बेहतर तरीका होगा। इसका अर्थ है जीवन जीने के लिए कम से कम वस्तुएं खरीदना और उनका उपभोग सही तरीके से करना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का उदाहरण है,जिन्होंने अपना जीवन बहुत साधारण तरीके से जिया बहुत कम कपड़ों में गुजारा किया। अति सूक्ष्मवाद को अपनाया और अपना सारा पैसा दान कर दिया।

संजीव मेहरोत्रा
बरेली

मिनिमलिज्म की शुरुआत आप अपने विचारों में परिवर्तन कर उपयोग में न आने वाली चीजों को दानकर अलमारी में भरे हुए अनावश्यक कपड़ों, जूतों, चप्पलों आदि को दूसरों को देकर कर सकते हैं। सभी इंसानों को और अधिक की चाह होती है, अधिक कपड़े, नए नए गजेट, ज्यादा घूमना, ज्यादा शॉपिंग, ज्यादा पार्टियां और न जाने क्या क्या, इसके लिए हम ज्यादा कमाना चाहते हैं और ज्यादा खर्च करना भी, लेकिन इससे अगर खुशी मिलती तो ऐसा करने वाले सब खुश दिखाई देते।

रिसर्चगेट की एक स्टडी में बताया गया है कि मिनिमनिज्म एक लोकप्रिय जीवनशैली है। इसे अपना कर लोग अपनी खुशी से कम संपत्ति और सीमित संसाधन के साथ जी सकते हैं। ऐसे लोगों में जागरूकता सहनशीलता व सकारात्मक सोच पैदा होती है और मानसिक शांति मिलती है। मिनिमलिज्म का मंत्र है, 'कम ही ज्यादा' है। मिनिमलिज्म का मतलब है कि आप अपनी जरूरत की चीजें ही खरीदें, बजाय इसके कि आप जो चाहें वो खरीद लें। कोई भी सामान लेने पहले एक बार जरूर सोचे।

# एलडीए के तत्कालीन सचिव समेत चार को सजा और जुर्माना

विधि संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार** : वर्ष 1987 से लेकर 1999 के दौरान एलडीए की जानकीपुरम योजना में भूखंडों के आवंटन में हेराफेरी एवं सरकार को राजस्व क्षति पहुंचाने के एक मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एलडीए के तत्कालीन संयुक्त सचिव सहित चार आरोपियों को कारावास एवं भारी जुर्माने की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने इस मामले में एलडीए के पूर्व संयुक्त सचिव आरएन सिंह को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 35 हजार रुपये जुर्माना जबकि लिपिक राज नारायण द्विवेदी को 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 60 हजार रुपये जुर्माना तथा बाहरी व्यक्ति महेंद्र सिंह सेंगर व दिवाकर सिंह को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 15000-15000 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई के अनुसार प्लाट आवंटन में बड़े पैमाने पर की गई धोखाधड़ी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 21 फरवरी 2006 के आदेश के तहत सीबीआई ने 28 फरवरी 2006 को संयुक्त सचिव आरएन सिंह सहित सात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। जिसमें आरोप था कि वर्ष 1987 से 1999 के बीच एलडीए की जानकीपुरम योजना के अंतर्गत 123 भूखंडों को संयुक्त सचिव एवं उपसचिव स्तर के विभिन्न अधिकारियों द्वारा एलडीए के तत्कालीन प्रधान लिपिकों एवं अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से उन लोगों को भूखंड आवंटित कर दिया जिनका पंजीकरण फॉर्म तक नहीं भरा गया था।

इसके अलावा भूखंड वितरण के लिए अपेक्षित रकम भी जमा नहीं की गई थी। विवेचना के उपरांत सीबीआई ने सात आरोपियों विरुद्ध 26 फरवरी 2010 को विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जहां पर सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मृत्यु होने के कारण उनका मामला समाप्त कर दिया गया तथा एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया।

### 1.57 करोड़ का घोटाला, 16 अधिकारी-कर्मचारी मिले थे दोषी, तीन से हुई थी वसूली

**अमृत विचार , लखनऊ :** 29 साल से चल रहे भूखंड घोटाले में 16 अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाए गए थे। सभी पर 1,57,63,497 रुपये की रिकवरी निकली थी जबकि एलडीए ने रकम तीन से जमा कराई थी।कैसरबाग कोतवाली में पूर्व संयुक्त सचिव समेत 16 अधिकारियों व कर्मचारियों पर भूखंडों में फर्जीवाड़ा की तहरीर दी गई थी। दर्शाया था कि भूखंडों की रकम जमा न करके 10 फीसद नामांतरण शुल्क लेकर आवंटित किए गए। पार्क की जगह तक बेच दी।

जांच में संयुक्त सचिव आरएन सिंह पर 1,73,010 रुपये, मिश्री लाल पासवान पर 1,80,330 रुपये व श्रीपाल वर्मा पर 1,20,860 रुपये, अनुसचिव राम प्रकाश सिंह पर 94,01,647, संपत्ति अधिकारी रामप्यारे सिंह 23,73,623, अधिशासी अभियंता केके पांडेय 4,74,210, सहायक अभियंता डीपी सिंह 4,56,010 व डीवी माथुर 18,200, अवर अभियंता जे वाधवानी 2,14,197, ओपी पांडेय 1,33,768, एके जौहरी 42,254 व पंकज कुमार 31,446, ड्राफ्टमैन पूरन सिंह नागर 3,27,210, योजना सहायक आरएन द्विवेदी 2,60,014 व जेपी शुक्ला 38,697, अनुभाग अधिकारी श्याम किशोर गुप्ता 3,44,957 रुपये वसूल किये जाने थे। वसूली अनुसचिव राम प्रकाश सिंह, योजना सहायक जेपी शुक्ला एवं ड्राफ्टमैन पूरन सिंह नागर से की गई। जिस समय तहरीर दी गई उस समय पूर्व संयुक्त सचिव आरएन सिंह, सहायक संपत्ति अधिकारी बाबू राम, लिपिक श्याम किशोर गुप्ता, इरशाद हुसैन, यूएस द्विवेदी रिटायर हो चुके थे। पूर्व अनुसचिव राम प्रकाश सिंह, सहायक संपत्ति अधिकारी राम प्यारे सिंह, लिपिक राजनरायन द्विवेदी, सुरेश वर्मा, गोपाल सिंह निलंबित किए गए थे।

# पॉक्सो के तहत दोषी को सुनाई 10 वर्ष के कारावास की सजा

विधि संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार :** शादी का झांसा देकर नाबालिक से यौन संबंध बनाने एवं बाद में शादी से इनकार करने के आरोपी को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने 10 वर्ष के कठोर करावास एवं 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक सुखेन्द्र प्रताप सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता द्वारा 23 जनवरी 2017 को काकोरी थाने में दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया कि आरोपी धीरेंद्र ने उससे प्रेम संबंध बनाकर यौन शोषण किया। 21 जनवरी को शादी की बात करने पर उसने इनकार किया और गालियां एवं जानमाल की धमकी देकर मारपीट भी की। मामले की सुनवाई के दौरान विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को बतौर गवाह पेश किया गया। स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 5 मई 2000 पाई गई। अदालत ने कहा है कि घटना के समय पीड़िता नाबालिक थी तथा आरोपी ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका।

## एक नजर

### युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान

**अमृत विचार, लखनऊ :** मानकनगर क्षेत्र में युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक, मेंहदी खेड़ा निवासी अमित ने बताया भाई पिंटू यादव (44) काफी दिनों से मानसिक बीमार था। उसका इलाज नूर मंजिल अस्पताल से चल रहा था। सोमवार को उसने जहरीला पदार्थ खालिया। हालत बिगड़ने पर लोकबंधु अस्पताल ले गए। जहां से लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। वहां मौत हो गयी। पिंटू पांच भाइयों में तीसरे नंबर पर व अविवाहित था।

### पेट्रोल पंप पर मारपीट, रिपोर्ट

**अमृत विचार, लखनऊ :** पीजीआई क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, हसनगंज निवासी राघवेन्द्र सिंह ने प्रार्थना-पत्र दिया। बताया उनका भतीजा पार्थ सिंह दोस्त युवराज के साथ शनिवार शाम बाइक से कल्ली पश्चिम स्थित पंप पर बाइक में तेल भरवा रहा था। इस दौरान कुछ बाइक सवार युवक बहस करने लगे। विरोध पर एक युवक ने रॉड से पार्थ का सिर फोड़ दिया और युवराज की भी पिटाई कर दी। पार्थ ट्रामा में भर्ती है।

### पति पर प्रताड़ना व धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज

**अमृत विचार, लखनऊ :** पीजीआई कोतवाली में पत्नी ने पति के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक तेलीबाग निवासी महिला की दूसरी शादी आलमबाग निवासी युवक से हुई थी। रिश्ते के वक्त युवक को ऑटो पार्ट्स का डीलर बताया गया था। शादी के कुछ वक्त बाद महिला को पता चला कि पति को सुनाई नहीं देता है और शारीरिक रूप से भी कमजोर है। महिला ने झूठ बोल कर शादी करने पर विरोध किया। तो ससुराल में मारपीट कर दहेज की मांग की गई।

### शराब पिलाने से मना करने पर सिर फोड़ा

**अमृत विचार, लखनऊ :** मदेयगंज क्षेत्र में शराब पीने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, दीनदयाल नगर निवासी शुभम वर्मा सोमवार रात शराब की दुकान के बाहर खड़ा था। तभी बाइक सवार तीन युवक पहुंचे यहां शराब पिलाने को लेकर विवाद हो गया। शुभम का आरोप है कि उसके मना करने पर तीनों ने रॉड से हमला कर सिर फोड़ दिया। शुभम को घर वाले अस्पताल ले गये। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

### बाइकों की भिड़ंत में दो युवक घायल

**अमृत विचार, माल :** माल कस्बा के वीरांगना ऊदा देवी इंटर कॉलेज मोड़ पर मंगलवार को दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक चालक हरदोई जनपद के संडीला निवासी नवनीत कुमार और भानपुर निवासी अभिषेक घायल हो गये। ग्रामीणों ने दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से नवनीत को ट्रॉमा रेफर कर दिया गया।

# बिजली गुल होने पर उपकेंद्र में घुसकर अवर अभियंता, एसएसओ को पीटा

## कार्यालय के दस्तावेज भी फाड़ने की कोशिश, एसएसओ व कर्मचारी घायल

कार्यालय संवाददाता,लखनऊ

**अवर अभियंता ने पांच नामजद व 20 अज्ञात पर दर्ज कराई रिपोर्ट**

**अमृत विचार:** बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सोमवार रात बीकेटी क्षेत्र के सुंदर बिहार सैदपुर जागीर उपकेंद्र पर हंगामा कर एसएसओ और अवर अभियंता की पिटाई कर दी। हमले में एसएसओ और कर्मचारी घायल हो गए। बीकेटी के अवर अभियंता ने पांच नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर जानकीपुरम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

जानकीपुरम थाने में दिए प्रार्थनापत्र में अवर अभियंता ने बताया कि आसिफ, महेश वर्मा, भारत सिह और जय सिह 15 से 20 अज्ञात लोगों के साथ उपकेंद्र आए थे। बार-बार बिजली काटने का आरोप लगाकर एसएसओ प्रभात कुमार, कृष्णकुमार दुबे और राम कुमार के साथ अभद्रता व गाली गलौज की। कर्मियों ने गोहना फीडर में ओवरलोडिंग से फाल्ट होने की जानकारी देने दी।

बताया कि फाल्ट सही कर आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। आरोप है कि जानकारी देने के बावजूद ये लोग एसएसओ को मारने की नीयत से कंट्रोल रूम में घुस आए। वीडियो बनाने पर एसएसओ प्रभात कुमार का गला पकड कर मारने की कोशिश करने लगे। बचाव करने आए अवर अभियंता की आंखों में अज्ञात वस्तु से हमला कर मारपीट की। सुन्दर विहार सैदुपर की तरफ आने पर गोली मारने की धमकी दी। दोबारा एक दो लोगों ने कार्यालय में घुसकर रजिस्टर और सरकारी दस्तावेज नष्ट करने का प्रयास किया। जानकीपुरम थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

### 132 केवी उपकेंद्र नवी कोट नंदना पर लिया जाएगा शटडाउन

अमृत विचार,लखनऊ : 132 केवी नवी कोट नंदना पर 33 केवी विकास नगर साइड आइसोलेटर क्लैम्प वाई फेज को बदलने के लिए बुधवार सुबह 7 से 8 बजे तक शटडाउन लिया जायेगा। इससे नवी कोट नंदना से संचालित उपकेंद्रों की आपूर्ति अन्य विकल्पों से की जाएगी। 33 केवी विकास नगर, कपूरथला की सप्लाई 132 केवी खुर्रमनगर उपकेंद्र,अहबरनपुर दो की अबारनपुर प्रथम से की जाएगी। पुरनिया की सप्लाई बाधित रहेगी।

### मुंशीपुलिया और जानकीपुरम में आज रहेगी बिजली गुल

अमृत विचार, लखनऊ : शहर के मुंशीपुलिया विद्युत उपकेंद्र सेक्टर 14 आरएलबी स्कूल के पास मरम्मत कार्य के चलते क्षेत्र की बिजली आपूर्ति सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। विकास नगर और कपूरथला फीडर पर कार्य किए जाने के चलते प्रियदर्शिनी कॉलोनी, केशवनगर, नायकनगर, मौहिबल्लापुर, अजीजनगर, शेरवानीनगर और मडियांव इलाके की आपूर्ति सुबह 7 से रात 8 बजे और सुल्तानपुर,वृद्धा आश्रम के पास, सुल्तानपुर गांव,सेक्टर आई और जानकीपुरम के अलीशा नगर की आपूर्ति सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बाधित रहेगी।

अकबरनगर के विस्थापितों की समस्याएं सुनतीं मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब। अमृत विचार

# बसंतकुंज में बनाया गया वेंडिंग जोन

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार:** अकबरनगर से विस्थापितों को रोजगार देने के लिए बसंतकुंज में वेंडिंग जोन बना दिया गया है। यहां दुकानें लगाने वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित भी किया जाएगा। इसके अलावा विस्थापित परिवारों के बच्चों को प्रशासन शिक्षा दिलाएगा। उनको हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी।

मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने मंगलवार को बसंतकुंज में शिविर लगाकर विस्थापितों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों को चिकित्सा, शिक्षा के अलावा ट्रांसपोर्ट, खाद्यान प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाएगा। सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी बनेगी।

उन्होंने आशा, एएनएम के लिए सब सेंटर बनाने बनाने और प्राथमिकता पर टीकाकरण कराने के निर्देश भी दिए। जिला पूर्ति अधिकारी से कहाकि, कोटेदार का चयन कर राशन की दुकान भी बसंतकुंज योजना में खोली जाए। पात्रों के तत्काल राशन कार्ड बनवाए करा ली जाए, जिससे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि साफ सफाई के लिए मैन पावर की व्यवस्था कर दी गई है। वेंडिंग जोन तय कर दिया गया है।

वहां विस्थापितों को आजीविका चलाने के लिए दुकानें लगवाई जाएंगी। जोन वालों को लाभान्वित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विस्थापित परिवारों के 120 बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में दाखिला कराया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार आदि मौजूद रहे।

### मुख्यमंत्री आवास योजना में सीतापुर की ग्रेडिंग खराब

**अमृत विचार, लखनऊ :** मुख्यमंत्री आवास योजना में सीतापुर की ग्रेडिंग खराब मिलने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने लक्ष्य के सापेक्ष धीमी और खराब प्रगति वाले जिलों को सुधार करने की हिदायत दी। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। मंडलायुक्त ने आरएस विभाग को सड़क और भवन निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कायाकल्प योजना, मध्याह्न भोजन, कन्या विवाह योजना, स्वरोजगार योजना, कृषक दुर्घटना, किसान सम्मान निधि, कुसुम योजना, ऊर्जा, कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा के दौरान ग्रेडिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। सड़कों के मरम्मत का काम प्राथमिकता पर कराने को कहा। मंडलायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम ऋण स्वीकृत किया जाए ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें। पीएम स्वनिधि योजना में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष समयावधि के तहत प्राप्त आवेदनों को शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जाए। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा के रूटों पर साफ-सफाई कराते रहें साथ ही ध्यान रखें कि जल भराव न हो। नालियों की साफ-सफाई के बाद एंटीलार्वा और स्प्रे का छिड़काव कराएं। जर्जर और निष्प्रयोज विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन न किया जाए। उन्होंने कहा कि कायाकल्प योजना के तहत दिव्यांग शौचालयों की क्रियाशीलता जांच ली जाए। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन रणविजय यादव, संयुक्त विकास आयुक्त केके सिंह मौजूद रहे।

# पेपर लीक कांड के सभी 23 आरोपियों पर गैंगस्टर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

**अमृत विचार :** प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र आउट कराने वाले गिरोह के सरगना राजीव नयन मिश्र सहित 23 आरोपियों पर कौशाम्बी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। सभी के खिलाफ मंझनपुर, कोखराज और प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज हैं। आरओ/एआरओ की परीक्षा के पर्चा आउट और परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूले के मामले में एसटीएफ ने गैंग के तीन सदस्यों आयुष पांडेय, पुनीत सिंह और नवीन सिंह को मंझनपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मंझनपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

जांच में सरगना राजीव नयन मिश्र सहित 20 अन्य के नाम सामने आए। सरगना समेत 19 सदस्य एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुके हैं। इसी मामले में एक एफआईआर प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुई थी। अब कौशांबी पुलिस ने सरगना सहित सभी 23 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट तहत कार्रवाई की है। एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पेपर लीक गैंग पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के बाद कौशाम्बी पुलिस अब सभी सदस्यों की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही है। बताया कि गिरोह के सदस्यों के पास अपराध से अर्जित जो भी संपत्ति होगी, उसे जल्द ही कुर्क किया जाएगा। पेपर लीक कांड के चार सदस्य अभी फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। आरोपी अर्पित दिलीप यशवंत, अमित सिंह, डॉ. शरद, कमलेश कुमार और अभिषेक शुक्ला कौशाम्बी की जेल में हैं। सरगना राजीव नयन मेरठ जेल में निरुद्ध है। उसे एसटीएफ ने पकड़ा था।

## एटीएम कार्ड बदल 27 हजार उड़ाए

**अमृत विचार, लखनऊ:** मड़ियांव क्षेत्र में टप्पेबाजों ने युवती का एटीएम कार्ड बदल कर करीब 27 हजार रुपये निकाल लिये।

इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा के मुताबिक, सेक्टर क्यू निवासी अंजली पुत्री चेतराम ने दिये प्रार्थना-पत्र में बताया 17 जुलाई की रात करीब 8.55 बजे अलीगंज स्थित पीएनबी के एटीएम से रुपये निकालने गई थी। जहां मदद के बहाने दो टप्पेबाजों ने उसका एटीएम कार्ड बदल दिया। इसकी जानकारी घर पहुंचने पर मोबाइल में मैसेज देखने पर हुई। आरोपियों ने चार बार में उसके खाते से रुपये निकाल लिये। एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से टप्पेबाजों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।

## महिला का शव फंदे से लटका मिला

**अमृत विचार, लखन0ऊ:** बीबीडी थाना क्षेत्र में महिला का शव फंदे से लटका मिला। भाई ने हत्या कर शव फंदे से लटकाने की आशंका जताई है। उसने पति समेत अन्य द्वारा बिना वजह बहन को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक, क्षेत्र के दुधरा निवासी पूजा (28) पत्नी अनिल कुमार का शव फंदे से लटका मिला। भाई उमेश के मुताबिक पूजा की शादी पांच वर्ष पहले की थी। बहन ने कई बार बिना वजह पति द्वारा प्रताड़ित करने की बात बताई। उसे हर बार में समझा बुझा कर शांत कर दिया जाता था। भाई ने पूजा की संदिग्ध हालात में मौत होने की बात कही है।

# चार बार किया ऑपरेशन, नहीं मिला आराम

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार :** मवैया निवासी मरीज के बेटे ने सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के सर्जन डॉक्टर राजेश मेहता पर ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाकर उपमुख्यमंत्री से शिकायत की है। सीएमओ की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की जांच में पता चला कि मरीज की हड्डियां कमजोर होने के कारण ऑपरेशन नहीं हो सकता था। कूल्हा प्रत्यारोपण ही विकल्प था, लेकिन डॉ. राजेश ने बड़े चिकित्सा संस्थान रेफर करने के बजाय लापरवाही करते हुए ऑपरेशन कर दिया। शासन को भेजी रिपोर्ट में सीएमओ ने डॉक्टर को प्रथमदृष्टया डॉ. दोषी माना है।

आलमबाग के मवैया निवासी सुरजीत सिंह ने उपमुख्यमंत्री को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि मां अमरजीत कौर के बाएं कूल्हे की हड्डी में दर्द था। वर्ष 2022 में सरदारी खेड़ा आलमबाग स्थित सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में डॉ. राजेश मेहता को दिखाया था। डॉ. राजेश ने कैल्शियम की कमी बता कर दवाइयां और हर छह महीने में इंजेक्शन लगवाने का सुझाव दिया। जिसकी कीमत 25 हजार रुपये थी। इंजेक्शन से आराम न मिलने पर डॉ. राजेश ने 4 जनवरी 2023 को ऑपरेशन किया, लेकिन आराम नहीं मिला।

आरोप है कि डॉ. राजेश ने चार बार ऑपरेशन कर करीब सात लाख रुपये वसूल लिए। आरोप है कि चारों ऑपरेशन सफल न होने पर डॉक्टर ने कूल्हे में डाला गया गुल्ला व अन्य सामान बाहर निकाल दिया। दर्द से आराम न मिलने पर दूसरे डॉक्टर के परामर्श पर एक्स-रे कराया। जिसमें पता चला कि कूल्हे के स्टेप्लर वाले पिन और प्लास्टर का सामान जख्म के अंदर छोड़ने से दर्द हो रहा है। लापरवाही के कारण मरीज उठने-चलने में असमर्थ है और हर माह इलाज पर करीब 30 हजार रुपये खर्च हो रहे हैं। सीएमओ डॉ. मनोज अग्रवाल ने कहा कि जांच में ऑपरेशन के दौरान डॉ. राजेश की लापरवाही की पुष्टि हुई है।

गिरने से कूल्हा फैक्चर हो गया था, मेरे पास आठ माह से इलाज चल रहा था। मरीज का बीपी-शुगर कंट्रोल नहीं था और उम्र भी बहुत अधिक थी। ऐसी स्थिति में पूरा हिप रिप्लसमेंट संभव नहीं था। इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई है। आरोप बेबुनियाद हैं।

**-डॉ. राजेश मेहता, सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर**

### रंजिश में मजदूर की पिटाई कर किया लहूलुहान

**अमृत विचार, मोहनलालगंज :** पुरानी रंजिश को लेकर मजदूर को दबंगों ने पिटाई कर लहूलुहान कर दिया। भरसवा गांव निवासी विकास ने बताया बीते सोमवार की शाम को अपने साथी शिवा निवासी डाढा सिकंदरपुर के साथ निगोहां के भट्ही सिर्स गांव से मजदूरी कर बाइक से निकलकर मदाखेड़ा मंदिर पर स्थित पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहे थे। तभी रंजिश को लेकर दिलीप और मोहित निवासी पिपरीखेड़ा समेत पांच साथियों के साथ उसे व साथी को पीटा। डंडे से सिर फोड़कर लहूलूहान कर दिया। इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया दो नामजद समेत पांच अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर घायलों को मेडिकल के लिए सीएचसी भेजा है।

### घर से नकदी व जेवरात लेकर किशोरी प्रेमी के साथ फरार

**अमृत विचार , मोहनलालगंज :** कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की घर से लाखों की नकदी सहित जेवरात लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गयी। पीड़ित मां की तहरीर पर तीन आरोपियो के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी गयी है। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया उसकी 17वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर बीते रविवार की देर रात मनोज कुमार निवासी शेखपुर जनपद उन्नाव भगा ले गया।

### जलकुंभी निकालने गए युवक का शव तालाब में मिला

**अमृत विचार, लखनऊ :** पारा क्षेत्र में मंगलवार को तालाब में युवक का शव उतराता मिला। पुलिस के मुताबिक, क्षेत्र के काकोरी मौंदा निवासी अनिल साहू (35) पड़ोस के भरोसा गांव गया था। उसके अलावा साथी रामबाबू, सूरज व शिवरी निवासी दरोगा भी थे। सभी को योगेंद्र लाल ने तालाब से जल कुंभी निकालने के लिये बुलाया था। गहराई अधिक होने के कारण अनिल डूब गया था। मंगलवार सुबह ग्रामीण तालाब की तरफ पहुंचे तो अनिल का शव उतराता मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि परिजन द्वारा प्रार्थना-पत्र मिलने पर कार्रवाई की जायेगी।

**बजट पर चर्चा** | उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का ऋण सामान्य वर्ग के लिए लाभकारी

# कहीं उत्साह, कहीं अव्यवस्थाओं को दर्शाती तस्वीर

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार :** केंद्रीय बजट आने के बाद छात्रों और शिक्षकों के बीच मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई, कुछ ने इसे उम्मीदों का बजट बताया। कई ऐसे भी रहे, जो योजनाओं को धरातल पर न उतरने की बात कहते दिखे।

उत्कर्ष अग्रवाल कहते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण की वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए लाभकारी रहेगी। ई-वाउचर के माध्यम से मिलने वाला लाभ कई औपचारिकताओं के झंझट को खत्म करेगा। ब्याज में की जाने वाली कमी भी समस्याओं को कम करेगी।

उत्कर्ष अग्रवाल

समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने कहा कि युवाओं और छात्रों के लिए रोजगार के द्वार खुलने का दावा महज दिखावा है। बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार परीक्षा कराने में ही पूरी तरह से विफल साबित हुई तो रोजगार कहां से उपलब्ध कराएगी। नौकरियों से जुड़े आवेदन करीब-करीब बंद होते दिख रहे हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर हैं।

हब और स्पोक मॉडल में 1,000 आईटीआई को अपग्रेड करने की योजना दूरगामी परिणाम लाएगी। बड़ी संख्या में युवा कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़ेंगे। केंद्र प्रायोजित योजना आने वाले समय में युवाओं को ऋण की सुविधा के साथ कौशल भी प्रदान करेगी। इससे युवा तेजी से आत्मनिर्भर बनेंगे। **- डॉ. रुचिता सुजय चौधरी, भाषा विश्वविद्यालय**

मल्टीनेशनल कंपनियों में युवाओं को पांच वर्ष इंटर्नशिप की सुविधा देना छात्रों के आर्थिक स्तर को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। ट्रेनिंग के दौरान होने वाले खर्च को कम्पनी सीएसआर फंड से वहन करना भविष्य की सार्थकता को मजबूती देगा। ऐसे में युवाओं को रोजगार के साधन मिलेंगे। **-डॉ. शशांक शेखर, डॉ. राममनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय**

हर वर्ष 25 हजार छात्रों को मदद देने का केंद्र सरकार का एलान हवा-हवाई साबित होगा। जब राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं तो परिणाम कहां से बेहतर होंगे। यूजी पाठ्यक्रमों में सीयूईटी यूजी परीक्षा परिणाम न घोषित होने से सीटें नहीं भर सकी हैं। **-सुधांशु शर्मा, अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय**

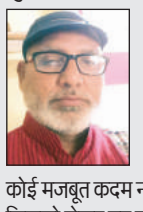

युवा, महिला और श्रमिक वर्ग से जुड़े लोगों को पिछले 10 वर्षों से बजट में कुछ खास नहीं मिल रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और घरेलू बजट पर ऐसा कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया, जिसको लेकर यह कहा जाए कि केंद्र सरकार ने आमजन को कोई राहत दी है। बजट तीनों वर्गों को धोखा देने वाला है। **- डॉ. बृज बिहारी, प्रदेश महासचिव, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट**

## तीन आईटीआई के बहुरेंगे दिन

**अमृत विचार, लखनऊ :** केंद्र सरकार ने आम बजट में आईटीआई को अपग्रेड करने की घोषणा की है। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित लखनऊ, गोरखपुर और प्रतापगढ़ आईटीआई के दिन बहुरने की संभावना है।

इन आईटीआई ते विभिन्न ट्रेडो में छात्र-छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनमें लगभग 500 छात्र-छात्राएं हैं। सबसे अधिक 300 छात्र-छात्राएं लखनऊ आईटीआई में हैं। उम्मीद है कि उक्त तीनों आईटीआई को भी बजट मिलेगा। वर्षों पुराने भवन ठीक होने के साथ ही मशीनें भी अपग्रेड होंगी। साथ ही नए ट्रेड भी संचालित किए जा सकते हैं। समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि आईटीआई को अपग्रेड करने के लिए प्रस्ताव बनाया जाएगा और उसके अनुसार शासन से बजट मांगा जाएगा।

# एपी सेन गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने देखा बजट

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**बजट की खास बातों पर छात्राओं ने प्रतिक्रिया की साझा**

**अमृत विचार :** एपीसेन मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में छात्राओं को बजट का लाइव प्रसारण दिखाया गया। आम बजट की खास बातों पर छात्राओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कीं।

विभागाध्यक्ष डॉ. मोनिका ने बताया कि अमृत काल का यह बजट निश्चित रूप से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में एक मजबूत आधारशिला तैयार करेगा। बजट में 2.6 लाख करोड़ ग्रामीण महिलाओं एवं 3 लाख करोड़ लड़कियों के विकास पर जोर दिया गया। छात्रा प्रज्ञा सिंह ने कहा कि सरकार को बेरोजगारी कम करने की दिशा में और अधिक सार्थक प्रयास करना चाहिए। छात्रा अलका दुबे, हुदा ने बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपये का अलॉटमेंट शिक्षा, रोजगार व कौशल विकास पर आवंटन करने को लेकर प्रसन्नता जताई। वहीं खुशबू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनांनिकी लाभांश को प्राप्त करने के लिए कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सरकार को बहुत ध्यान देना होगा। कुमुद का कहना है कि आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात को स्वीकार किया गया है कि इंडस्ट्री की स्किल्ड वर्कर की डिमांड और वर्तमान शिक्षा प्रणाली के द्वारा तैयार स्किल्ड लेबरफोर्स में बहुत अंतर है। हर दो में से एक स्किल्ड युवा इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, और यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है।

## हादसों में घायल दो चालकों ने ट्रॉमा सेंटर में तोड़ा दम

**अमृत विचार, लखनऊ :** अलग-अलग थाना क्षेत्र में हादसों में घायल बाइक चालकों को गंभीर हालत में केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। सोमवार देर रात उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गोसाईंगंज पुलिस के मुताबिक, बाराबंकी स्थित लोनी कटरा मकनपुर निवासी नंदकिशोर (35) दिल्ली में मजदूरी करता था। पिता तिलक राम का कहना है कि बेटा कुछ दिन पहले घर आया था। सोमवार को बाइक से अपनी मौसी से मिलने गोसाईगंज के भमरोली जा रहा था। उधर, हजरतगंज कोतवाली अंतर्गत भेडी कोठी निवासी मो. शब्बीर (50) निज चालक थे। भाई मो. शाहिद ने बताया कि गुरुवार रात में बाइक से घर वापस आ रहे थे। कैसरबाग क्षेत्र में लालबाग में सामने से आये दूसरे बाइक चालक से भिड़त हो गई थी।

## सार-संक्षेप

### दरोगा से हाथापाई, महिला सिपाही की वर्दी फाड़ी

**अमृत विचार, लखनऊ :** कैंट कोतवाली क्षेत्र में सैन्यकर्मी द्वारा दरोगा से हाथापाई व महिला सिपाही की वर्दी फाड़ने का मामला सामने आया है। कैंट इलाके निवासी महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम में मगंलवार दोपहर को कॉल कर सूचना दी कि पति उसकी पिटाई कर रहे है। सूचना पर पीआरवी पर तैनात हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, संतोष और संदीप चौधरी मौके पर पहुंचे। पत्नी की पिटाई कर रहे रंजीत कुमार को सिपाहियों ने रोकने का प्रयास किया। लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। रंजीत ने सिपाहियों से गाली-गलौज और हाथापाई करते हुए एक सिपाही का कॉलर पकड़ लिया। मामला बढ़ता देखकर पीआरवी टीम ने कैंट थाना प्रभारी को कॉल कर अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की। कैंट कोतवाली से दरोगा दीपक कुमार टीम के साथ पहुंचे तो उनके साथ एक महिला सिपाही भी थी। आरोपी रंजीत ने दरोगा दीपक कुमार के समझाने पर उससे हाथापाई करने लगा। साथ ही महिला सिपाही की वर्दी फाड़ दी। एसआई दीपक कुमार के मुताबिक, घटना के वक्त आरोपी भी सेना की वर्दी में था। ऐसे में सेना पुलिस को सूचना देने के बाद गिरफ्तार किया गया।

### मौलाना के वेश में लूट करने वाला गिरफ्तार

**अमृत विचार, लखनऊ :** तालकटोरा क्षेत्र में मौलाना के वेश में घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को मिठाई में नशीला पदार्थ मिला कर खिलाने के बाद गहने व रुपये लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी इसी तरह के मामले में जेल की सजा काट चुका है। इंस्पेक्टर तालकटोरा कुलदीप दुबे के मुताबिक, जानकीपुरम के सेक्टर-एफ निवासी ऊषा के पोते को डायरिया की चपेट में आने पर निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 14 जुलाई की शाम वह पोते को डिस्चार्ज करा कर घर लाईं थी। अस्पताल में उनकी मुलाकात फुरकान से हुई थी। जिसने बच्चे पर ऊपरी साया होने का झांसा दिया था। ऊषा के घर पहुंचने के बाद फुरकान झाड़ फूंक के बहाने ऊषा, उनके बेटे अर्जुन, बहू रूबी और पोते को नशीली मिठाई खिला दी। आरोपी घर से गहने व रुपये समेट कर भाग निकला। होश में आने पर ऊषा ने पूरी घटना पुलिस को बताई। मंगलवार को ठाकुरगंज हुसैनाबाद निवासी फुरकान उर्फ रेहान को मंजू टण्डन ढाल के पास से गिरफ्तार किया गया। उसने जुर्म कुबूल किया। इंस्पेक्टर ने बताया आरोपी ने घर से लूटे गहने सआदतगंज चौपटिया निवासी सर्राफ एजाज को बेचे थे। सर्राफ को गिरफ्तार कर लूट के गहने बरामद किये हैं। आरोपी रेहान 2016 में बाराबंकी में लूट के मामले में जेल भेजा गया था।

### आग लगने पर नहीं दिया हर्जाना, फोरम से मिली राहत

**अमृत विचार, लखनऊ :** नोएडा सिटी में मेसर्स कृशांग आटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के प्रथम तल पर आग लगने के बाद रिलायंस बीमा कंपनी को हर्जाना न देना भारी पड़ गया। राज्य उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को क्षति के मद में 13,85,515 रुपये मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से निर्णय की तिथि से एक माह की अवधि में देने के आदेश दिए। साथ ही क्षतिपूर्ति मद में एक लाख और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये देने के आदेश दिए। बता दें कि 16 नवंबर 2018 को परिवादी के परिसर के प्रथम तल पर शार्ट सर्किट से आग लग गई थी। घटना की सूचना अगले दिन इंश्योरेंस कंपनी को दी गई। इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर ने 21 और 24 नवंबर 2018 को परिसर का निरीक्षण किया। इंश्योरेंस कंपनी ने फारेंसिक रिपोर्ट के लिए एक लैब को नियुक्त किया। लैब की ओर से रिपोर्ट नहीं दी गई। साथ ही हर्जाना भी नहीं दिया गया था।

### लापता मैकेनिक का गोमती में मिला शव, हत्या की आशंका

**अमृत विचार, मलिहाबाद :** तीन दिन से घर से लापता एसी मैकेनिक का शव चौक क्षेत्र में गोमती नदी में मंगलवार को मिला। युवक मलिहाबाद का रहने वाला है। परिजन ने अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर शव नदी में फेंके जाने की आशंका जताई है। पुलिस के मुताबिक, घुसौली निवासी सुमित कुमार उर्फ दीपक (24) टेढ़ी पुलिया के पास एसी का काम करता था। 17 जुलाई को सुमित घर से बिना बताया चला गया था। देर शाम परिजनों ने सुमित के मोबाइल पर संपर्क किया, लेकिन स्विच ऑफ था। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मंगलवार दोपहर चौक क्षेत्र में सुमित का शव गोमती नदी में मिला। इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय ने बताया कि शरीर पर चोट के निशान नहीं हैं। मां शांति देवी ने बेटे की हत्या कर शव नदी में फेंकने की आशंका जताई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट होने पर कार्रवाई की जायेगी।



सुमित कुमार

### अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार

**अमृत विचार, लखनऊ :** उप्र. एटीएस ने जौनपुर में इंटरनेशनल गेटवे को बाईपास कर मिडिल ईस्ट के देशों से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से लोकल कॉल्स में परिवर्तित करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एटीएस द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध टेलीफोन एक्सचेंज संचालक अभियुक्त अशरफ अली, जौनपुर को अवैध सिमबॉक्स एवं उसके सहवर्ती उपकरणों के साथ (डीओटी प्रतिनिधि के समक्ष) गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अशरफ अली ने बताया कि मुंबई में उसकी मुलाकात भिवंडी मुंबई निवासी जहांगीर से हुई, जिसने सऊदी अरब में रहने वाले मो. अली द्वारा सिमबॉक्स के सम्बन्धित उपकरण उपलब्ध कराये एवं एनीडेस्क सॉफ्टवेयर के माध्यम से कॉनफिगर किया गया, और इंटरनेशनल गेटवे को बाईपास कर अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से लोकल कॉल्स में परिवर्तित कर देते थे।

### 500 अवैध सिम विदेश भेजने वाला गिरफ्तार

**अमृत विचार, लखनऊ :** एसटीएफ ने मंगलवार को फर्जी आईडी पर सिम लेकर उन्हें एक्टिवेट कर भारत के बाहर विभिन्न देशों में सप्लाई करने वाले गैंग के एक सक्रिय सदस्य राहुल सिन्हा निवासी प. बंगाल को नेपाल से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी को 10 हजार प्री एक्टिवेटेड अवैध सिम विदेशों में भेजने का लक्ष्य मिला था, जिसमें से 500 सिम वह भेज भी चुका था। एसटीएफ से मिली जानकारी के अनुसार राहुल सिन्हा की 2022 में सुनील खडका निवासी सोलुखुम्ब, नेपाल से मुलाकात हुई थी। सुनील खडका कम्बोडिया में कॉल सेन्टर से धोखाधड़ी से पैसा ट्रान्सफर कराता था। इस धोखाधड़ी के लिए सिम कार्ड की जरूरत पड़ती थी। इस उद्देश्य के लिए राहुल सिन्हा का काम भारत से 10 हजार सिम सुनील खडका को थाइलैण्ड भेजने का था, जिसमें लगभग 500 सिम वह भेज चुका है।

### रवनीत सिंह बिट्टू ने वित्त मंत्री का जताया आभार

**अमृत विचार, नई दिल्ली/चंडीगढ़ :** केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री सिंह रवनीत बिट्टू ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की सराहना की और कहा कि यह बजट भारत में कृषि और लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए वरदान साबित होगा। एक बयान में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें देश में 24 एमएसएमई क्लस्टर स्थापित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा वित्त मंत्री के समक्ष बजट पूर्व बैठक के दौरान उठाया था। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा एमएसएमई के लिए बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के नई मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए टर्म लोन की सुविधा शुरू की गई है। इसी तरह मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित सभी केंद्रीय योजनाओं में पंजाब को उसका उचित हिस्सा मिलेगा। जिससे पंजाब में औद्योगिक और कृषि दोनों को बढ़ावा भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर बजट केंद्रित करना है।

# रिश्वत लेते लेखाकार गिरफ्तार

## वेतन जारी करने के लिए मांगे थे 12 हजार रुपये

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार :** बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात लेखाकार अजमत अकरम को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ धर दबोचा। अजमत ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन जारी करने के लिए 12 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी। टीम ने सोमवार को विकास भवन स्थित बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में छापा मारकर कार्रवाई की। इस दौरान कर्मचारियों ने हंगामा किया और टीम को कार्रवाई करने से रोकने का प्रयास भी किया।

शाजियाबाद थाना क्षेत्र के खतीबपुर निवासी सुरेश सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी में लिखित शिकायत की थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसकी पत्नी की प्राथमिक विद्यालय डिहवां, लखमनपुर क्षेत्र मनिहारी में प्रधानाध्यापिका के पद पर नियुक्त थी, जिनकी मृत्यु हो गई है। उनकी जगह पर मृतक आश्रित के रूप में सुरेश नियुक्ति 10 जनवरी 2024 को कंपोजिट विद्यालय डिहवां लखमनपुर क्षेत्र मनिहारी में परिचारक के पद पर हुई। लेकिन, अभी तक वेतन जारी नहीं किया जा रहा है।

आरोप है कि वेतन का प्रकरण वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा विभाग) के यहां लंबित है। जिसे लेखाकार अजमत अकरम देख रहे हैं। लेखाकार वेतन जारी करने/कराने के नाम पर 12 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहे थे। लेखाकार ने कहा था कि जब तक रुपये नहीं दोगे वेतन निर्गत नहीं होगा। इस पर पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी ने अपने स्तर से जांच कराई। इसमें आरोपों को सही पाया गया। इसके बाद विजिलेंस वाराणसी की ट्रैप टीम सोमवार सुबह करीब 11.30 बजे विकास भवन पहुंची। यहां से लेखाकार अजमत अकरम को 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे अपने साथ लेकर वाराणसी चली गई।



विजिलेंस टीम की गिरफ्त में लेखाकार अजमत (लाल घेरे में)। अमृत विचार

> गाजीपुर के बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात लेखाकार अजमत अकरम को 12 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया है। वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से वेतन जारी करने के नाम पर यह रुपये मांग रहे थे। लेखाकार के विरुद्ध थाना उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, सेक्टर वाराणसी में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
>
> -विजय मल सिंह यादव, डिप्टी एसपी, विजिलेंस, वाराणसी

### कर्मचारियों व विजिलेंस टीम में नोकझोंक, हाथापाई

विजिलेंस विभाग की टीम ने छापा मारकर अजमत को पकड़ लिया। इसकी जानकारी होते ही विकास भवन में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग के कर्मचारी नाराज हो गए। उन्होंने टीम को घेर लिया। इस दौरान नोकझोंक और हाथापाई भी हुई। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि कार्यालय में अजमत को जब पकड़ा गया तो उसके पास से रुपये नहीं मिले थे। इसके बाद कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मामले की मजिस्ट्रीयल जांच कराने की मांग की।

# होश आते ही महिला बोली, पति ने मारपीट कर जहर पिला दिया

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार :** गाजीपुर क्षेत्र में पति द्वारा पत्नी को ऑल आउट का लिक्विड पिला कर जान से मारने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पड़ोसियों ने गंभीर हालत में महिला को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला को कुछ सेकंड के लिए होश आया तो बोली, पति ने मुझसे मारापीट कर जहर पिला दिया। चर्चा है कि पति का दूसरी युवती से प्रेम-प्रसंग है। जिसको लेकर दंपति में विवाद होता रहता है।

घटना को लेकर कानपुर निवासी पीड़ित पिता नौशाद ने बताया कि बेटी निशी फातिमा (33) की शादी 2010 में लवकुश नगर की नई बस्ती निवासी चालक राशु अली से की थी। उसके एक बेटा जैन (9) और बेटी गाजी (12) है। बताया कि सोमवार रात लगभग 11 बजे बेटी के पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर बताया कि फातिका की हालात गंभीर है। पिता लोहिया अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि बेटी को ऑल आउट का लिक्विड पिलाया गया है। इस बीच राशु बहाना बनाकर मौके से भाग निकला। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़ित पिता के प्रार्थना-पत्र पर राशु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जांच कर कार्रवाई की जायेगी।

### 10 दिन पहले भी हुआ था विवाद

पिता नौशाद का कहना है कि 10 दिन पहले भी बेटी और दामाद के बीच जमकर विवाद हुआ था। बेटी जब भी पति को दूसरी महिला से दूर रहने की बात कहती वह मारपीट शुरू कर देता था। नौशाद ने बताया कि दो बार अपने सामने ही दूसरी लड़की का नंबर राशु के मोबाइल से डिलीट कराया था।

## 12वीं की छात्रा का फंदे से लटका मिला शव

**अमृत विचार, लखनऊ :** ठाकुरगंज क्षेत्र में 12वीं की छात्रा का कमरे में फंदे से शव लटका मिला। भाई ने बहन के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से मामले की जांच की मांग की है।

पुलिस के मुताबिक, क्षेत्र के बरी कला निवासी मोहिनी (20) जिया मऊ स्थित कॉलेज में 12वीं की छात्रा थी। भाई विपिन ने बताया कि माता-पिता की मौत के बाद छोटी बहन मोहिनी की देखरेख वह और भाई अनूप करता था। सोमवार शाम काम करके घर पहुंचा। तो बहन दुपट्टे के फंदे से पंखे के से लटकी मिली। भाई अनूप ने बताया बहन के पास से मोबाइल मिला है। जिसमें सारी कॉल डिलीट की गई हैं। एक युवक का नंबर मिला है। जिससे आखरी बार उसकी बात हुई थी। इंस्पेक्टर श्रीकांत राय के मुताबिक, मोबाइल कब्जे में लिया है कॉल डिटेल खंगाली जा रही है।

## पूर्व मुख्य सचिव के बैंक खाते में वापस कराई 383 डॉलर की रकम

**अमृत विचार, लखनऊ :** प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन के खाते से कटी रकम 383 डॉलर (लगभग 32 हजार रुपये) को साइबर सेल ने कुछ ही दिन में वापस करवा दिया। साइबर सेल टीम के सक्रिय होने से बैंक ने समय रहते ट्रांसफर प्रक्रिया रोक दी थी। इसके चलते साइबर जालसाजों के खाते में डॉलर नहीं पहुंच सके। पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि साइबर जालसाज ने 8 जुलाई को फोन कर क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख रुपये बकाया होने की बात कहते हुए मोबाइल में नौ नंबर दबाने को कहा था। ऐसा करते ही उनके क्रेडिट कार्ड से 383 डॉलर कट गए थे।

# दो दरोगा और एक सिपाही निलंबित, एसीपी को सौंपी जांच

संवाददाता, सरोजनीनगर

**अमृत विचार :** बंथरा गांव में बिजली ठीक कराने को लेकर हुए विवाद में युवक की पीटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में लापरवाही बरतने और वारदात वाली रात को कार्रवाई न करने वाले दो दरोगा और एक सिपाही को मंगलवार देर शाम को निलंबित कर दिया गया। इसकी जांच एसीपी कृष्णानगर विनय द्विवेदी को सौंपी गई है। उधर, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छह पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। हालांकि दो दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है।

एडीसीपी दक्षिणी शशांक सिंह के मुताबिक, मृतक ऋतिक के पिता इंदु ने आरोप लगाया कि वारदात के बाद बंथरा थाने गए थे। वहां तहरीर दी, तो मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे कहा कि जाओ पहले इलाज कराओ सुबह देखा जाएगा। पुलिस ने ना तो कार्रवाई की और न ही घायल का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। वहीं, गांव जाकर घटना स्थल का निरीक्षण करना भी जरूरी नहीं समझा। इस आरोप की शुरूआती जांच में थाने में तैनात दरोगा सुभाष यादव, सुशील यादव और सिपाही यत्येंद्र सिंह की लापरवाही पाई गई। इस आधार पर तीनों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इनके खिलाफ विभागीय जांच एसीपी कृष्णानगर विनय कुमार द्विवेदी को सौंपी गई। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इंस्पेक्टर की भी भूमिका की भी जांच की जा रही है।

बता दें कि बंथरा गांव निवासी इंदु कुमार पांडेय का बेटा ऋतिक उर्फ हितेश (20) की रविवार रात को घर में घुसे दबंगों ने लाठी-डंडों से पीट दिया था। उसकी इलाज के दौरान सोमवार सुबह मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को देर शाम को सुपुर्द किया गया। रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं थी। मंगलवार को अंतिम संस्कार उन्नाव के शुक्लागंज स्थित गंगा घाट पर किया गया। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस के अलावा एक प्लाटून पीएसी भी तैनात की गई है।

### आरोपियों की तलाश में छह टीमें दे रही दबिश

एसीपी कृष्णानगर विनय द्विवेदी ने बताया कि इंदु की तहरीर पर अवनीश, हिमांशु सिंह, प्रियांशू, प्रत्यूश, सनी सिंह और 10 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश में थाने, सर्विलांस सेल, क्राइम टीम समेत कुल छह टीमें दबिश दे रहीं हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

### कैब चालक को पीटने वाला ट्रैफिक दरोगा निलंबित

**अमृत विचार, लखनऊ :** कमता तिराहे पर कैब खड़ी करने पर चालक को ट्रैफिक दरोगा ने डंडों से पीट दिया। इसका वीडियो सोमवार देर रात को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अधिकारियों के संज्ञान में मामला आते ही दरोगा को निलंबित कर दिया गया। कमता तिराहे पर सोमवार दोपहर को चालक ने कैब रोकी। इसके बाद पानी लेने जाने लगा। इसी बीच जाम लगता देख वहां तैनात टीएसआई राजेंद्र कुमार ने चालक की डंडे से पिटाई शुरू कर दी। एडीसीपी यातायात अजय कुमार ने बताया कि चालक की पिटाई करने वाले टीएसआई राजेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच एसीपी इंद्रपाल को सौंपी गई है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

**मामला** परिजन ने शिक्षक के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी

# सही उत्तर न देने पर छात्र का सिर फोड़ा

संवाददाता, मलिहाबाद

**अमृत विचार :** मलिहाबाद के गोशालालपुर गांव स्थित राजकीय हाईस्कूल में 7वीं के दो छात्रों ने सवाल के सहीं उत्तर नहीं दिए। इस पर नाराज शिक्षक ने उन्हें जमकर पीटा। इस दौरान दोनों को डेस्क की तरफ धकेल दिया। जिस कारण एक छात्र का सिर फूट गया। पीड़ित छात्र ने परिजनों को जानकारी दी। परिजन छात्र को लेकर मलिहाबाद थाने पहुंचे। जहां पुलिस ने छात्र को उपचार के लिए भेजकर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

मलिहाबाद के पुरवा गांव निवासी राजेंद्र कुमार ने बताया कि उनका बेटा प्रिंस (16) और गांव के ही आकाश का छोटा भाई गौरव गोशालालपुर स्थित राजकीय हाईस्कूल में 10वीं के छात्र हैं। सोमवार को दिन में 12 बजे स्कूल में मध्यान्ह भोजन के बाद की कक्षा में प्रिंस और गौरव पढ़ने गए। स्कूल में तैनात शिक्षक मो. सलीम आशिके रसूल ने एक सवाल किया। दोनों सवाल का सहीं जवाब नहीं दे सके। इस पर नाराज शिक्षक ने दोनों छात्रों की पिटाई शुरू कर दी और दोनों के सिर दरवाजे पर कई बार दे मारा। आरोप है कि इसके बाद भी संतोष नहीं हुआ तो दोनों लात-घूंसों से वार किया। फिर दोनों को डेस्क पर ढ़केल दिया। इसके कारण प्रिंस का सिर फट गया।

पिता राजेंद्र ने बताया कि प्रिंस और गौरव के शरीर में कई स्थान काले निशान बन गए है। प्रिंस के सिर में चार टांके लगे हैं। आरोप है कि मो. सलीम ने धमकी दी कि इसके बारे में घर पर बताए तो जान से मार देगा। प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह ने बताया कि राजेंद्र कुमार की तहरीर पर शिक्षक मो. सलीम के खिलाफ पिटाई करने, जान से मारने की धमकी, जानबूझकर अपमानित करने, एससीएसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है।



पीड़ित छात्र

# 55 दिनों से तीन थानों के चक्कर लगा रहे मेडिकल स्टोर संचालक

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

▸▸ लूट की रिपोर्ट दर्ज न होने पर आईजीआरएस पर की शिकायत

**अमृत विचार :** लूट का मुकदमा दर्ज कराने के लिए मेडिकल स्टोर संचालक देव कुमार तिवारी पिछले 55 दिनों से भटक रहे है। मुकदमा दर्ज करने के बजाए पुलिस उनको तीन थानों पीजीआई, कैंट और हुसैनगंज के चक्कर लगवा रही है। परेशान देव कुमार ने आईजीआरएस पर शिकायत की।

पंचम खेड़ा निवासी पीड़ित देव कुमार ने बताया कि 4 जून को रात 10 बजे चारबाग जाने किए ऑटो पर बैठे। चारबाग रेलवे ओवरब्रिज के नीचे साथ बैठे दो युवकों ने चाकू लगा दी। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। बैग, मोबाइल, चेन छीन लिया। बैग में 32 हजार रुपये रखे थे। फिर मारपीट कर चलते ऑटो से फेंक दिया। बीते 55 दिनों से तहरीर लेकर पीजीआई, कैंट व हुसैनगंज थाने के चक्कर काट रहे है लेकिन कहीं भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इंस्पेक्टर हुसैनगंज राजकुमार ने बताया कि देव कुमार घटनास्थल के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। कभी कैंट बता रहे हैं तो कभी चारबाग ओवरब्रिज के पास। मामले की जांच की जा रही है।


## कार्यालय नगर पंचायत पयागपुर, बहराइच

पत्रांक: 196/ प्रेस विज्ञप्तिं/प्लास्टिक प्रतिबंध/2024 दिनांक-24.07. 2024

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार राजपत्र संख्या 178 नई दिल्ली शुक्रवार 18 मार्च 2016 अपशिष्ट प्लास्टिक अधिनियम 2016 तथा भारत सरकार का राजपत्र संख्या 459 नई दिल्ली 12 अगस्त 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक प्रबन्धन (संसोधन) नियम 2021 द्वारा एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई 2018 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड भारत सरकार के पत्रांक NOB17011/7/UPC-II-PWM (SUP)/2022 Dated 30-06-2022 एवं राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन '(नगरीय) लखनऊ उ0प्र0 के पत्र संख्या पी0एम0यू0/6142/524/2020-21 दिनांक 20 जुलाई 2022 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पालिका परिषद बहराइच के सीमान्तर्गत प्रतिबन्धित प्लास्टिक एवं थर्माकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।

1. 75 माईक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग और वस्तु 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबन्धित है तथा 120 माईक्रोन से कम मोटाई के समस्त प्रकार की एकल उपयोग प्लास्टिक 31 दिसम्बर 2022 से पूर्णता प्रतिबन्धित है।

2. 01 जुलाई 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबन्धित है-

(1). पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण वितरण बिक्री और उपयोग को पूर्णतः निषेध किया गया है।

(2). प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झण्डे, कैडी स्टिक, आईस्क्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावट सामग्री।

(3) जो कम्पोस्टिक योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटे कप, गिलास, कोटे, स्ट्रों, ट्रें जैसे कटलरी मिठाई के डिब्बे के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर ट्रे का भी 01 जुलाई 2022 से प्रयोग प्रतिबन्धित है।

इन सामग्रियों का विनिर्माण, आयात भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग करना प्रतिबन्धित है पायें जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध अधिसूचना के निर्धारित नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

**अधिशाषी अधिकारी**
नगर पंयायत पयागपुर , बहराइच।

**(नामित)अध्यक्ष**
नगर पंयायत पयागपुर , बहराइच।

## कार्यालय नगर पालिका परिषद, बहराइच

पत्रांक: 195/ प्रेस विज्ञप्तिं/प्लास्टिक प्रतिबंध/2024 दिनांक-24.07. 2024

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार राजपत्र संख्या 178 नई दिल्ली शुक्रवार 18 मार्च 2016 अपशिष्ट प्लास्टिक अधिनियम 2016 तथा भारत सरकार का राजपत्र संख्या 459 नई दिल्ली 12 अगस्त 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक प्रबन्धन (संसोधन) नियम 2021 द्वारा एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई 2018 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड भारत सरकार के पत्रांक NOB17011/7/UPC-II-PWM (SUP)/2022 Dated 30-06-2022 एवं राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन '(नगरीय) लखनऊ उ0प्र0 के पत्र संख्या पी0एम0यू0/6142/524/2020-21 दिनांक 20 जुलाई 2022 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पालिका परिषद बहराइच के सीमान्तर्गत प्रतिबन्धित प्लास्टिक एवं थर्माकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।

1. 75 माईक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग और वस्तु 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबन्धित है तथा 120 माईक्रोन से कम मोटाई के समस्त प्रकार की एकल उपयोग प्लास्टिक 31 दिसम्बर 2022 से पूर्णता प्रतिबन्धित है।

2. 01 जुलाई 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबन्धित है-

(1). पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण वितरण बिक्री और उपयोग को पूर्णतः निषेध किया गया है।

(2). प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झण्डे, कैडी स्टिक, आईस्क्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावट सामग्री।

(3) जो कम्पोस्टिक योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटे कप, गिलास, कोटे, स्ट्रों, ट्रें जैसे कटलरी मिठाई के डिब्बे के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर ट्रे का भी 01 जुलाई 2022 से प्रयोग प्रतिबन्धित है।

इन सामग्रियों का विनिर्माण, आयात भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग करना प्रतिबन्धित है पायें जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध अधिसूचना के निर्धारित नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

**अधिशाषी अधिकारी**
नगर पालिका परिषद , बहराइच।

**अध्यक्ष**
नगर पालिका परिषद , बहराइच।

## कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बहराइच

संख्यारू 463/ जि0आ0अ0/वि0वि0/2024-25/बहराइच/दिनांक जुलाई, 23, 2024

चेतावनी

जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि अवैध अड्डों से बिकने वाली अवैध मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि अवैध अड्डों से मिलने वाली मदिरा जहरीली हो सकती है तथा मिथाईल अल्कोहल भी हो सकता है. जो एक तीव्र जहर है तथा इसके सेवन से आंखों की रोशनी जाने के साथ व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।

सस्ते के चक्कर में जान न गवायें, जहरीली शराब पीने से बचें। उत्तर प्रदेश में वैध शराब पाउच में नहीं बिकती है, इसलिए अपना एवं अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकृत शराब की दुकान से ही बार कोडयुक्त एवं सीलबन्द मदिरा ही खरीदें। पाउच वाली शराब किसी भी हालत में न खरीदें, क्योंकि यह पूर्णतया नकली एवं जानलेवा है।

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के संशोधित धारा-60 (क) के अनुसार अवैध मदिरा के सेवन से जनहानि होने की दशा में कारोबारीयो विरुद्ध मृत्युदण्ड / आजीवन कारावास का प्राविधान है। यदि किसी अवैध शराब के कारोबारी द्वारा ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप किसी व्यक्ति की विकलांगता, मृत्यु होती है तो आजीवन कारावास, मृत्यु की सजा तथा दस लाख रूपये जुर्माना भी हो सकता है।

यदि किसी व्यक्ति को अवैध मदिरा की बिक्री की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल जनहित में निम्न दूरभाष नं0/मोबाइल नं0 पर सूचना देने का कष्ट करें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जायेगा।

नववर्ष के अवसर पर रेस्टोरेन्ट एवं होटलों में पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें बिना लाइसेंस के मदिरा परोसे जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इन आयोजनों के लिए विभागीय पोर्टल www.upeexciseportal.in पर आनलाइन आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त करके ही करें।

**मो0नं0 का विवरण :-**

आबकारी निरीक्षक, सदर, बहराइच, मो0- 9454466250, आबकारी निरीक्षक, नानपारा, बहराइच मो0- 9454466251, आबकारी निरीक्षक, महसी, बहराइच मो0- 8585906474, आबकारी निरीक्षक, कैसरगंज, बहराइच मो0- 9795732838, आबकारी निरीक्षक, पयागपुर, बहराइच मो0नं0- 9721172567 आबकारी निरीक्षक, मिहींपुरवा, बहराइच मो0नं0- 7651874146

**(सुधांशु सिंह)**
जिला आबकारी अधिकारी,
बहराइच।

**(मोनिका रानी)**
जिलाधिकारी,
बहराइच।

## एक नजर

### दो पालियों में होंगी पीजी प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षाएं

**अमृत विचार, लखनऊ :** लखनऊ विश्वविद्यालय 25 जुलाई से परास्नातक एवं परास्नातक प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा (सत्र-2024-2025) आयोजित कराने जा रहा है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन दो पालियों में होगा। लखनऊ विवि के प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि परास्नातक एवं परास्नातक प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 25 से शुरू होकर 31 को समाप्त होगी।

### अभ्यर्थी कल तक कर सकते हैं च्वॉइस फिलिंग

**अमृत विचार, लखनऊ :** लखनऊ विश्वविद्यालय बीए (नेप), बीवीए और बीएफए के अभ्यर्थी च्वॉइस फिलिंग की सहूलियत 25 जुलाई तक ले सकते हैं। प्रवेश समन्वयक प्रो. पंकज माथुर ने बताया कि विवि और संबद्ध महाविद्यालयों में काउंसिलिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों को विषयों से जुड़े विकल्प बदलने की सुविधा 23 तक दी गई थी। इसे अब बढ़ाकर 25 कर दिया गया है।

### स्वतंत्रता सेनानी डॉ. दरबारी लाल का जन्मोत्सव आज

**अमृत विचार, लखनऊ :** स्वतंत्रता सेनानी डॉ. दरबारी लाल अस्थाना का जन्मोत्सव बुधवार को प्राथमिक विद्यालय नरही में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक आनंद अस्थाना ने बताया कि डॉ.दरबारी लाल अस्थाना ट्रस्ट की ओर आयोजित इस समारोह में जादूगर सुरेश के दल द्वारा पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति से ओत-प्रोत जादू और कठपुतली की प्रस्तुतियां होंगी। इसके साथ ही सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है।

### टीचिंग ओलम्पियाड में सीएमएस की शिक्षिकाएं टाप 10 में

**अमृत विचार, लखनऊ :** सिटी मोन्टेसरी स्कूल गोमती नगर द्वितीय कैम्पस के कैम्ब्रिज सेक्शन की दो शिक्षिकाओं शान आरा खान एवं शिल्पी अग्रवाल ने इण्टरनेशनल सेन्टा टीचिंग प्रोफेशनल ओलम्पियाड में शानदार प्रदर्शन किया है। इस शिक्षण ओलम्पियाड में पूरे विश्व से 80 हजार से अधिक शिक्षकों ने प्रतिभाग किया, जिनमें शान आरा खान ने सीनियर सेकेण्डरी इंग्लिश कैटेगरी में चतुर्थ इण्टरनेशनल रैंक अर्जित किया, जबकि शिल्पी अग्रवाल ने कम्प्यूटर साइंस में पांचवी इण्टरनेशनल रैंक अर्जित की।

# दो कोर्स दिखाएंगे दिव्यांगों को रोजगार की राह

## पुनर्वास विवि शुरू करने जा रहा है डीआईएसएलआई और डीटीआईएसएल के दो नए कोर्स

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**भारतीय पुनर्वास परिषद ने दी संचालन की अनुमति, विभागीय अधिकारियों ने किया भ्रमण**

**अमृत विचार :** दिव्यांगों के लिए पुनर्वास विश्वविद्यालय के दो नए कोर्स रोजगार के साथ राहत भरी उम्मीदें लेकर आए हैं। विवि के प्रवक्ता ने बताया कि इसकी मदद से छात्रों को सीखने, समझने और समझाने का मौका मिलेगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर दिव्यांगों को आसानी से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। विवि को नए सत्र के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद (रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया) से पाठयक्रमों के संचालन की मान्यता मिल गई है।

डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ. यशवंत विरोदय का कहना है कि डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई) और डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज (डीटीआईएसएल) के दो कोर्स पहली बार आरंभ होने जा रहे हैं। इसी सत्र से शुरू

होने वाले दो कोर्सों के माध्यम से छात्रों को भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएलआई) सिखाने के लिए तैयार किया जाएगा। पाठ्यक्रम के तहत स्नातक छात्रों को आईएसएल के उपयोग में आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस कराया जाएगा, ताकि वे बधिर और सुनने वाले व्यक्तियों को शिक्षित करने में सहायता प्रदान कर सकें। विवि में प्रशिक्षण पूरा होते ही कैंपस चयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

### स्वास्थ्य केंद्रों के लिए तैयार किए जाएंगे छात्र

डॉ. यशवंत विरोदय ने बताया कि डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई) और डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज (डीटीआईएसएल) प्रशिक्षण पाने वाले स्नातक स्कूलों, विश्वविद्यालयों, सामुदायिक केंद्रों, बधिर शिक्षा और वकालत पर केंद्रित संगठनों में आईएसएल शिक्षकों के रूप में कॅरियर बनाने के लिए तैयार किये जाएंगे। ये बधिर व्यक्तियों के लिए भाषाई और सांस्कृतिक सुलभता को बढ़ावा देने और समाज में अधिक समावेशिता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

### नए सत्र में दोनों कोर्स के लिए सीटें आवंटित

नए सत्र में शुरू हो रहे डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई) कोर्स के लिए 30 सीटें आवंटित की गई हैं। वहीं डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज (डीटीआईएसएल) में भी अभ्यर्थियों के लिए 30 सीटें दी गई हैं। दोनों ही पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2024-25 से शुरू किये जाएंगे। पैरामेडिकल एवं रिहैबिलिटेशन संकाय के अधिष्ठाता प्रो. वीके सिंह ने बताया कि पाठ्यक्रमों में आवेदन को लेकर विश्वविद्यालय जल्द ही वेबसाइट पर प्रक्रिया अपलोड कर दी है।

### भाषा विवि में प्रवेश के लिए एक और मौका

**अमृत विचार, लखनऊ :** ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने सभी विषयों में प्रवेश के लिए एक बार फिर मौका दिया है। प्रवेश समन्वयक प्रो. एहतेशाम अहमद ने बताया कि सत्र 2024-25 के लिए बीफार्मा, एमफार्मा, डी फार्मा, एलएलबी, बीएएलएलबी को छोड़कर बीजेएमसी, एमजेएमसी सहित सभी विषयों में बची हुई सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 24 जुलाई तक कर दी गई है।

# छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार :** पिछले वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए दशमोत्तर कक्षाओं के 37 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए आवेदन करने का आज (24 जुलाई) अंतिम अवसर है। आवेदन और दस्तावेजों की जांच के बाद 30 अगस्त तक वंचित रह गए छात्र-छात्राओं के खातों में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की पैसा पहुंच जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में समय से परीक्षा परिणाम न घोषित होने सहित कई कारणों से दशमोत्तर कक्षाओं के 37,793 छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। इनमें सामान्य वर्ग के 9100, पिछड़ा वर्ग के 25,479 और अल्पसंख्यक वर्ग के 3214 छात्र-छात्राएं शामिल थे। इनके लिए 15 जुलाई को दोबारा पोर्टल खोला गया था और आज आवेदन करने की अंतिम तिथि है। 30 जुलाई तक छात्र ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिक्षण संस्थानों में जमा करेंगे। शिक्षण संस्थान इसी दौरान दस्तावेजों का मिलान कर उसे सत्यापित कर अग्रसारित करेंगे। 31 जुलाई से 22 अगस्त तक छात्रवृत्ति पोर्टल संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करेगा और पात्र लाभार्थियों के खातों में 30 अगस्त 2024 तक छात्रवृत्ति का पैसा पहुंच जाएगा।

### पर्यावरण प्रतियोगिता में शामिल होंगे एकेटीयू के छात्र

**अमृत विचार, लखनऊ :** डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों के छात्र राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। पर्यावरण के प्रति छात्रों में जागरूकता के लिए यह प्रतियोगिता 1 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जा रही है। कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने सभी संस्थानों को पत्र जारी कर इस प्रतियोगिता में छात्रों को प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया है।

### लविवि : छह विषयों में शुरू होगा ऑनलाइन एमए

**अमृत विचार, लखनऊ :** लखनऊ विश्वविद्यालय में छह विषयों में ऑनलाइन एमए पाठ्यक्रम शुरू करने को लेकर विभागीय की बैठक का आयोजन किया। बैठक में विषयों से संबंधित प्रोग्राम प्रोजेक्ट रिपोर्ट (पीपीआर) पर विस्तार से मंथन हुआ। इस दौरान ऑनलाइन कोर्स के सिलेबस तैयार करने को लेकर सहमति हुई। बाद में अंतिम निर्णय लिया गया। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में विवि एमए अंग्रेजी, एआईएच, पॉलीटिकल साइंस, संस्कृत, इकनॉमिक्स और एमएसडब्ल्यू विषयों को ऑनलाइन आरंभ करने जा रहा है।

### गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों को दी भावांजलि

**अमृत विचार, लखनऊ :** गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भारतीय संगीत महाविद्यालय द्वारा गुरुओं को सांगीतिक श्रद्धार्पण किया गया। संगीत नाटक अकादमी की वाल्मीकि रंगशाला में हुए कार्यक्रम में तबला को वैश्विक पहचान दिलाने वाले उस्ताद अल्ला रक्खा खां तथा वर्ष 1967 में भारतीय संगीत महाविद्यालय की स्थापना करने वाले उस्ताद शेख पुत्तन समेत गुरुजनों को भावांजलि दी गई। अतिथि के रूप में कला समीक्षक डॉ. एसके गोपाल, कर्नल हरिहरन और अंकित सिंह ने दीप प्रज्ज्वलन किया। कार्यक्रम में मुख्य गायन अंश और अंशिका ने किया।

## नव आगंतुक फार्मासिस्टों का किया स्वागत

**अमृत विचार, लखनऊ :** अन्य जिलों से स्थानांतरित होकर लखनऊ के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में आए चीफ फार्मासिस्ट व फार्मासिस्ट का डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिला शाखा लखनऊ की कार्यकारिणी की ओर से स्वागत व परिचय समारोह आयोजित किया गया। बलरामपुर चिकित्सालय के इमरजेंसी सभागार में आयोजित समारोह जिला अध्यक्ष अरुण अवस्थी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मंच का संचालन रजत यादव ने किया। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष कपिल वर्मा, आरबी मौर्या, अविनाश सिंह, चन्द्रशेखर श्रीवास्तव, राजेश वरुण, अरविन्द सिंह, राज कुमार, जसवंत, रंजीत गुप्ता, अरविन्द त्रिपाठी, रामेश चन्द्र चौधरी, सुनील यादव, केआरएस कनौजिया, शकील खान, मदन गोपाल गुप्ता मौजूद रहे।

# स्कूल एसोसिएशन ने की डीजीपी से मुलाकात

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार :** अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के पदाधिकरियों ने मंगलवार को राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह एवं कोषाध्यक्ष रचित मानस ने डीजीपी को उत्तर प्रदेश के समस्त निजी विद्यालयों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार जताया।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा निजी विद्यालयों के लिए जारी आदेश से समस्त शिक्षक - शिक्षिकाएं, कर्मचारी गण, प्रधानाचार्य एवं प्रबंधतंत्र सुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने डीजीपी से बताया कि विद्यालयों

डीजीपी से मुलाकात करते हुए अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल अग्रवाल साथ में अन्य पदाधिकारी। अमृत विचार

**प्रदेश अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा, अब स्कूल प्रबंधन कर रहे सुरक्षित महसूस**

में जाने-अनजाने घटित घटनाओं के बाद तत्काल विद्यालय प्रशासन शिक्षक कर्मचारी आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था और पुलिस के शोषण का शिकार होना पड़ता था जिससे विद्यालय प्रबंधन अपने को अपमानित महसूस करता था। जारी आदेश से इस पर रोक लगेगी और सभी को राहत मिलेगी।

## महानिदेशक ने लोगों को पौधे लगाने को किया प्रेरित

**अमृत विचार,** लखनऊ: अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (आरडीएसओ) के महानिदेशक अजय कुमार राणा के नेतृत्व में मंगलवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महानिदेशक ने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता के बारे में बताया एवं इसके लिए आरडीएसओ द्वारा किये जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरडीएसओ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। उनसे आग्रह किया कि वे भी एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में अपना योगदान दें।

# लविवि: 64वीं यूपी बटालियन एनसीसी में रैंक वितरण

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**64वीं यूपी बीएन एनसीसी के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर डॉ. रजनीश कुमार यादव ने किया रैंक वितरण**

**अमृत विचार :** 64वीं यूपी बटालियन एनसीसी लखनऊ विश्वविद्यालय के सत्र 2024-25 का रैंक वितरण समारोह आयोजित किया गया। एनसीसी में रैंक के अनुसार सीनियर अंडर ऑफिसर, अंडर ऑफिसर, कंपनी सार्जेंट मेजर, कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट के बाद सार्जेंट, कॉर्पोरल और लांस कॉर्पोरल शामिल रहे।

एनसीसी की सीनियर अंडर ऑफिसर रैंक रत्नाकर राय को दी गयी। अंडर ऑफिसर विनय वर्मा, अंडर ऑफिसर प्रेरणा शर्मा एवं अंडर ऑफिसर गौरव यादव को प्रदान की गई। कंपनी सार्जेंट मेजर माही सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट अर्पित वर्मा, सार्जेंट भूमिका गुप्ता, अंशिका सिंह और राज को प्रदान की गई। इसके बाद 5 कॉर्पोरल और 12 लांस कॉर्पोरल की रैंक वितरित की गई। रैंक वितरण 64 यूपी बीएन एनसीसी के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर डॉ. रजनीश कुमार यादव ने किया। इस अवसर पर सूबेदार मेजर भूपेन्द्र सिंह धामी, नायब सूबेदार राम किशन और अन्य ट्रेनिंग स्टॉफ उपस्थित रहा।

# ग्रीन पार्क में होने वाले टेस्ट मैच को लेकर शुरू हुई तैयारी

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**खेल विभाग और यूपीसीए के अधिकारियों के साथ हुई बैठक**

**अमृत विचार :** कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में खेले जाने वाले भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच (27 सितंबर से 1 अक्टूबर) को लेकर उसे संवारने की तैयारी शुरू हो गई है। इस कड़ी में मंगलवार को खेल विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें यूपीसीए के पदाधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में ग्रीनपार्क स्टेडियम में दर्शक क्षमता बढ़ाने के साथ स्टैंड को अपग्रेड करने पर सहमति बनी। इससे भविष्य में यहां अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन की संभावनाएं बढ़े।

ग्रीनपार्क स्टेडियम में इस समय कुल दर्शक क्षमता 22000 हजार की है। स्टेडियम में पूर्व में हुए बदलाव के चलते क्षमता कम हो गई थी। फिलहाल बैठक में दर्शक क्षमता को 30000 तक पहुंचाने की तैयारी की गई है। सीएसआर (कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलटी) फंड से स्टेडियम के स्टैंड को भी अपग्रेड किया जायेगा। यदि ये दोनों ही काम भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच से पहले पूरे कर लिये जात है तो बीसीसीआई की ओर से कानपुर को और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी मिल सकती है।

प्रमुख सचिव खेल आलोक कुमार ने बताया कि ग्रीनपार्क के सौंदर्यीकरण के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई बिंदुओं पर बात की गई है। उम्मीद है भविष्य में ग्रीनपार्क स्टेडियम में होने वाले अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की संख्या में इजाफा होगा।

# केंद्रीय विद्यालय आईआईएम और आरडीएसओ बने चैंपियन

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

**अमृत विचार :** केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ संभाग के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय आईआईएम में हो रहे क्षेत्रीय खो-खो प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय आईआईएम की छात्राओं ने खो-खो अंडर-14 में प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरा स्थान केंद्रीय विद्यालय वायु सेना बरेली और तीसरा केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट को मिला। अंडर-17 खो-खो प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय आरडीएसओ चैंपियन बना।

फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। केंद्रीय विद्यालय आरडीएसओ ने केंद्रीय विद्यालय आईआईएम की टीम को मात्र एक अंक के अंतर से पराजित कर मैच जीत लिया। तीसरा स्थान पर केंद्रीय विद्यालय हरदोई को मिला। पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ संभाग की सहायक आयुक्त अर्चना जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही।

### केंद्रीय विद्यालय कैंट की लड़कियों ने बिखेरा जलवा

**अमृत विचार, लखनऊ :** केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर में चल रही 53वीं संभागीय कबड्डी प्रतियोगिता के अंतिम दिन केंद्रीय विद्यालय कैंट की लड़कियों ने जलवा बिखेरा। अंडर-17 और अंडर-14 दोनों ही आयु वर्ग के फाइनल में केंद्रीय विद्यालय कैंट की बालिका टीम ने बाजी मारी। अंडर-17 में केंद्रीय विद्यालय कैंट ने केंद्रीय विद्यालय रायबरेली द्वितीय पाली 66-20 के लंबे अंतर से मात दी। अंडर 14 में केंद्रीय विद्यालय कैंट लखनऊ ने केंद्रीय विद्यालय शिवगढ़ को 53-2 से हराया। समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि केंद्रीय विद्यालय लखनऊ संभाग के सहायक आयुक्त विजय कुमार ने विजयी और उपजेता टीमों को विजेता ट्रॉफी प्रदान की। पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर के प्राचार्य संजीव कुमार अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित तीन दिवसीय प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। सहायक उपायुक्त ने केंद्रीय विद्यालय प्राचार्य महोदय के कुशल नेतृत्व की सराहना की। समापन समारोह के अवसर पर उप प्राचार्या प्रथम पाली संगीता सक्सेना, उप प्राचार्य द्वितीय पाली प्रदीप कुमार मिश्रा, प्रधानाध्यापक अरूणेश वैश्य और प्रधानाध्यापिका भारती अवस्थी और खेल प्रशिक्षक अन्य मौजूद रहे।

## जिला फुटबॉल लीग

# संतोष के चार गोल से एलडीए क्लब जीता

**अमृत विचार, लखनऊ :** जिला फुटबॉल लीग के मुकाबलों में एलडीए क्लब (ए) और सहारा स्टेट क्लब ने जीत दर्ज कर पूरे अंक बटोरे। पहले मैच में एलडीए क्लब (ए) ने लखनऊ यूथ क्लब को 5-0 से शिकस्त दी। इसके बाद खेले गए एक अन्य मैच में सहारा स्टेट क्लब ने एलाइट क्लब को 7-2 से हराया। एलडीए क्लब (ए) और लखनऊ यूथ क्लब के बीच खेला गया मुकाबला इकतरफा ही रहा। एलडीए क्लब (ए) ने पहले हाफ में ही 2-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। विजयी टीम की ओर से अभिषेक ने 12वें और प्रियांशु कुमार ने 24वें मिनट में गोल किये। दूसरे हाफ में कांते ने 47वें, नितिन ने 41 वें और प्रियांशु कुमार ने 58 वें मिनट में गोल कर जीत दर्ज की।

## कार्यालयः अधिशासी अभियंता जोन-3 जल कल विभाग, नगर निगम, लखनऊ

पत्र सं0 708/E.E.-3/L.J.S./2024-25 दिनांकः 23/07/2024

**अति अल्पकालीन निविदा सूचना**

जल कल विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु नीचे दिये गये विवरण के अनुरुप कार्य को कराये जाने हेतु मोहरबन्द निविदायें दिनांक 30/07/2024 को 3:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते है। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनाँक 30/07/2024 को 1:00 बजे तक निविदा मूल्य का नगद भुगतान कैश काउन्टर पर करके प्राप्त किये जा सकते हैं। भरी हुई सील्ड निविदायें उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 3:30 बजे तक निविदा बाक्स में प्राप्त की जायेगी। निविदा बाक्स से प्राप्त सभी निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 4:00 बजे सांय काल खोली जायेगी।

| क्र0 सं0 | कार्य/आपूर्ति का विवरण | निविदा का मूल्य | धरोहर धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | जोन-3 के अर्न्तगत शिव मन्दिर के पास शिवपुरम त्रिवेणी नगर-III में मिनी नलकूप की बोरिंग के उपरान्त बाईपास सिस्टम की आपूर्ति व अधिष्ठापन तथा अन्य विद्युत/सिविल सम्बन्धी कार्य। | 300.00 | 5600.00 |

नियम एवं शर्ते निविदा प्रपत्र में दी गई है, जिन्हें देखा जा सकता है। विस्तृत जानकारी अधिशासी अभियन्ता जोन-3 के कार्यालय में सम्पर्क कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। निविदा खुलने के दिनांक को यदि कोई अवकाश हो अथवा किसी कारणवश कार्यालय बन्द हो तो अगला कार्य दिवस ही निविदा खुलने का दिनांक होगा। निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी / महाप्रबन्धक में निहित है।

अधिशासी अभियन्ता, जोन-3
जलकल विभाग, लखनऊ

क्या ऑपरेशन ही एक मात्र समाधान है ?
SINCE 2006
जोड़ों का दर्द, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस में!
कहीं आप इन जटिल रोगों से परेशान तो नहीं? जोड़ो का दर्द, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड अर्थ राइटिस, स्लिपडिस्क, कमर दर्द, कंधे का दर्द/फ्रोजेन शोल्डर, स्याटिका, मांसपेशियों का दर्द, एड़ी का दर्द, वातरक्त (GOUT) इत्यादि।
दर्द की दवाइयाँ खाकर अपने शरीर को नुकसान न पहुंचाये – आयुर्वेद अपनायें
VACHAK वाचक आयुर्वेद®
आइए इसी संबंध में डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी से हुई बातचीत के कुछ अंश

प्रश्न 1: गठिया रोग की पहचान कैसे करें ?
उत्तर : गठिया रोग का सबसे प्रमुख लक्षण है जोड़ों में दर्द होना जब जोड़ों में दर्द व सूजन कुछ दिन या हफ्तों में ठीक ना हो और चलते फिरते या उठते बैठते दर्द होने लगे तो हमें चाहि, कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें

प्रश्न 2: डा0 कहते हैं कि आपके घुटनों का गिरीश सूख गया है तो यह गिरीश क्या होता है?
उत्तर : यहां एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जिसे सायनोवियल फ्लुएड कहते हैं जो आपके जोड़ों को हिलने डुलने में मदद करता है और आपस में रगड़ खाने से रोकता है

प्रश्न 3: रूमेटोइड अर्थराइटिस क्या है?
उत्तर : यह एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें शरीर की इम्युनिटी स्वस्थ कोशिकाओं को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं जो जोड़ों में दर्द सूजन और जकड़न का कारण बनती है इसे आयुर्वेद में आमवात के नाम से जाना जाता है

प्रश्न 4: क्या बिना ऑपरेशन के गठिया में आराम हो सकता है?
उत्तर : आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार गठिया एक जटिल बीमारी है तथा इसमें ऑपरेशन नहीं बताया गया है यह वातव्याधि के अंतर्गत आता है जिसमें वात नाशक व रसायन औषधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे जोड़ो में चिकनाहट बनना शुरू हो जाता है और जोड़ों का दर्द व सूजन कम हो जाने से मरीज को चलने फिरने में आराम हो जाता है

प्रश्न 5: क्या अत्यधिक पेन किलर खाना नुकसानदायक है?
उत्तर : हां अत्यधिक पेन किलर खाने से हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है विशेषतया हमारे पेट व गुर्दे को नुकसान पहुंच सकता है

प्रश्न 6: डॉक्टर साहब बिना दर्द की दवा के मरीज को आराम कैसे मिलेगा?
उत्तर : जोड़ों में दर्द का मुख्य कारण जोड़ों के अंदर उपस्थित गिरीश का कम हो जाना जिससे हड्डियां आपस में रगड़ खाती है जिससे दर्द व सूजन की स्थिति पैदा होती है आयुर्वेदिक औषधियों में एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन Antiinflammatory व रसायन गुण होते हैं जिससे जोड़ों में चिकनाहट उत्पन्न होती है इस कारण हड्डियां आपस में रगड़ कम खाती हैं जिससे दर्द व सूजन में आराम हो जाता है

प्रश्न 7: सवाल घुटनों के दर्द व गठिया में क्या क्या नहीं खाना चाहिए?
उत्तर : आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों का दर्द व गठिया वात व्याधि के अंतर्गत आती है अतः वाद वर्धक आहार-विहार जैसे उड़द की दाल कटहल घुईया बैगन भिंडी राजमा मटर कद्दू वा देर रात तक जागना हानिकारक होता है

प्रश्न 8: गठिया रोग में क्या क्या खाना फायदेमंद होता है?
उत्तर : गठिया रोग में सूप सलाद हरी सब्जियां दूध मट्ठा पनीर अंजीर अखरोट पपीता अनार इत्यादि खाना फायदेमंद होता है

प्रश्न 9: डॉक्टर साहब गठिया से पीड़ित मरीजों को क्या सलाह देना चाहते हैं?
उत्तर : गठिया से पीड़ित मरीजों को नियमित रूप से तेल की मालिश सिकाई व एक्सरसाइज करना चाहिए तथा सीढ़ी ज्यादा ना चढ़े व नीचे ना बैठे तथा जल्द से जल्दआयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह लें जिससे आप की बीमारी आगे ना बढ़े

प्रश्न 10: अच्छा डॉक्टर साहब यदि कोई मरीज ऑपरेशन कराने के बाद भी उसे दर्द या तकलीफ रह जाती है तो क्या ऐसे मरीजों में भी आयुर्वेदिक दवाइयां लाभकारी होंगी?
उत्तर : हां बिल्कुल ऑपरेशन के बाद भी यदि मरीज को दर्द या तकलीफ रह जाती है तो आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज किया जा सकता है

डॉ. ओम प्रकाश वर्मा
MD (आयुर्वेद) आयुर्वेद स्पेशलिस्ट

पुरस्कार एवं सम्मान
- सन 2015 में प्रसिद्ध मीडिया हाउस के द्वारा इन्हें बेस्ट आयुर्वेदिक चिकित्सक के सम्मान से सम्मानित किया गया
- सन 2017 में माननीय यूपी कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी ने मार्वल हेल्थ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया
- सन 2017 में ही माननीय महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक जी द्वारा पर्सनालिटी ऑफ इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया
- श्री बी एस डी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल द्वारा टी.बी. दिवस पर एक कार्यक्रम में डॉक्टर साहब को उनके योगदान हेतु सम्मानित किया गया
- चैनल न्यूज 18 यूपी/उत्तराखंड ने कार्यक्रम लाइफ लाइन में डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा को यूपी के हेल्थ मिनिस्टर माननीय श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी द्वारा सम्मानित किया गया
- संस्कृत संस्थान द्वारा मानव सेवा के कार्य में निशुल्क योगदान के लिए सम्मानित किया गया
- संस्था एक पहल द्वारा माननीय मेयर लखनऊ श्रीमती संयुक्ता भाटिया द्वारा यूपी आई कॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया

Web : www.vachak.in
अपॉइन्टमेंट के लिए सम्पर्क करें –
7080239313
7570060266
आलमबाग
पता: शॉप नं0 206, तालकटोरा रोड, निकट आलमबाग चौराहा, लखनऊ नियर बृजवासी बेकरी
परामर्श समय-
सुबह 10:00 से 02:00 तक
मुंशीपुलिया
पता: 638/010 फरीदीनगर पिकनिक स्पॉट रोड, मुंशीपुलिया, लखनऊ नियर साहू पैलेस
परामर्श समय-
सांय 06:00 से 09:00 तक
रविवार सांय अवकाश

# युवती का कराया गर्भपात दी तेजाब फेंकने की धमकी

## ब्लैकमेल कर वसूले दो लाख रुपये, मड़ियांव कोतवाली में एफआईआर दर्ज

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार : मड़ियांव इलाके में रहने वाली युवती से तौसीफ खान नाम के युवक ने दोस्ती की। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। उसका गर्भपात कराया। वहीं, ब्लैकमेल कर दो लाख रुपये वसूले। पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे तेजाब फेंककर जीवन खराब करने की धमकी दी। पीड़िता ने मड़ियांव कोतवाली में तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया कि युवक शादीशुदा है।

मड़ियांव के फैजुल्लागंज निवासी युवती निजी दफ्तर में काम करती थी। यहीं पर उसकी मुलाकात तौसीफ खान से हुई। साथ काम करने के दौरान नजदीकियां बढ़ने लगी। इसी दौरान तौसीफ ने युवती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। युवती के हामी भरने के बाद आरोपी यौन शोषण करने लगा। विरोध करने पर जल्द शादी करने की बात कही। इस बीच पीड़िता गर्भवती हो गई। यह बात पता चलने पर तौसीफ ने जबरन दवा खिला कर गर्भपात करा दिया। ऐसा दो बार हुआ।

डेढ़ साल से यौन प्रताड़ना झेल रही युवती ने शादी करने का दबाव बनाया। जिस पर तौसीफ उसे धमकाने लगा। आरोपी ने युवती की आपत्तिजनक वीडियो बना ली थी। जिसे वायरल करने की धमकी देने लगा। आरोपी ने पीड़िता से करीब दो लाख रुपये भी वसूल लिए। इसके बाद भी शादी करने को तैयार नहीं हुआ। कुछ वक्त पूर्व युवती को परिचितों से तौसीफ के शादीशुदा होने का पता चला। सच्चाई सामने आने पर पीड़िता ने एतराज जताया। जिस पर तौसीफ ने युवती को तेजाब फेंक कर चेहरा जलाने की धमकी दी। इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।

### लड़कियों की तस्वीरें वायरल करने वाला पकड़ा

अमृत विचार, लखनऊ : एसटीएफ के एएसपी विशाल विक्रम के मुताबिक बाराबंकी निवासी रब्बानी पर किशोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देने के आरोप हैं। जिससे किशोरी डिप्रेशन में चली गई। आरोपी को आज पकड़ा गया।

# रोहित पांडेय के हत्यारोपी गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

**पुलिस ने आरोपियों के घर चलाया बुलडोजर**

अमृत विचार: बलिया के बांसडीह कोतवाली गेट के सामने दिन दहाड़े रोहित पांडेय की हत्या के मामले में सीएम की फटकार के बाद दो आरोपियों अंकित यादव और ओमप्रकाश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जबकि मुख्य आरोपी रोहित यादव ने अपने एक साथी शेखर यादव के साथ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस दौरान प्रशासन ने सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया। सभी आरोपियों के मकान का कुछ हिस्सा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बना हुआ था। यही नहीं आरोपियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने वाले दो आरक्षियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं बहराइच में युवती से छेड़छाड़ करने वाले एवं माहौल बिगाड़ने वाले नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

बता दें कि सीएम योगी को सोमवार को आजमगढ़ में समीक्षा बैठक के दौरान विधायक केतकी सिंह ने उक्त मामले से अवगत कराया था। इस पर सीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

उधर, बहराइच के नानपारा स्थित बुधवा के साप्ताहिक बाजार में 21 जुलाई शाम को कुछ शोहदों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने विशेष टीम गठित कर 24 घंटे के अंदर सभी नौ आरोपियों सलमान कुरैशी पुत्र कलीम कुरैशी, असलम कुरैशी पुत्र कलीम कुरैशी, इब्राहिम पुत्र हलीम, हलीम कुरैशी पुत्र रज्जब अली, गुलफान पुत्र चंगुल उर्फ नईम, रहीश पुत्र हनीफ उर्फ बरसाती, अबरार पुत्र इसरार, शमशेर पुत्र शरीफ और मुबारक अली पुत्र अली अहमद निवासी ग्राम बुधवा थाना कोतवाली नानपारा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

# लविवि में याद किए गए आजाद

अमृत विचार, लखनऊ : चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर लखनऊ विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। एनएसएस की इकाई अध्यक्ष सुधांशु सक्सेना के नेतृत्व कार्यक्रम आयोजित हुआ। विवि परिसर में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।


**पूर्वोत्तर रेलवे**

**ई-निविदा सूचना**

निम्नलिखित कार्यो के लिये ''खुली'' निविदा वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/सा0 पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से आमंत्रित की जाती हैः–

**क्रम सं.-1,** निविदा सं.: वमंविइ-लजं०-सीएचजी-02-2024, कार्य का विवरणः एलजेएन डिवीजन के ऐशबाग और गोरखपुर डिपो के ईओजी/एचओजी कोचों के लिये एलएचबी आरएमपीयू में एनटीसी सेंसर, ओएचपी और ईएसटीआई के स्थान का मानकीकरण का कार्य। अनुमानित लागतः ₹ 34,11,380.00, बयाना राशिः ₹ 68,200/-, निविदा मूल्यः ₹ 0.00, कार्य सम्पादन की अवधिः 04 माह। **क्रम सं.-2,** निविदा सं.: वमंविइ-लजं०-17-2024, कार्य का विवरणः पू०उ०रे० के लखनऊ मंडल में प्लेटफार्म लाइटिंग (30/70%) और स्ट्रीट लाइटिंग की निगरानी और नियंत्रण (भारतीय रेलवे मूल आईओटी आधारित उपज विश्लेषण टेलीमेट्री, रिकार्डिंग और नियंत्रण–आईआर–नियंत्रक) के लिये आईओटी उपकरणों/इंटेलिजेंट फील्ड डिवाइसेस (आईएफडी) का प्रावधान। अनुमानित लागतः ₹ 1,74,85,370.22, बयाना राशिः ₹ 2,37,400/-, निविदा मूल्यः ₹ 0.00, कार्य सम्पादन की अवधिः 04 माह। **क्रम सं.-3,** निविदा सं.: वमंविइ-लजं०-18-2024, कार्य का विवरणः पू०उ०रे० के लखनऊ मंडल में पम्प, लिट, एस्केलेटर सबस्टेशन आदि जैसी विद्युत सामान्य उपकरणों की निगरानी और नियंत्रण (भारतीय रेलवे मूल आईओटी आधारित उपज विश्लेषण टेलीमेट्री, रिकार्डिंग और नियंत्रण– आईआर–नियंत्रक) के लिये आईओटी उपकरणों / इंटेलिजेंट फील्ड डिवाइसेस (आईएफडी) का प्रावधान। अनुमानित लागतः ₹ 1,77,34,400.72, बयाना राशिः ₹ 2,38,700/-, निविदा मूल्यः ₹ 0.00, कार्य सम्पादन की अवधिः 04 माह। **क्रम सं.-4,** निविदा सं.: वमंविइ-लजं०-19-2024, कार्य का विवरणः लखनऊ मंडल के अन्तर्गत गोमतीनगर, गोण्डा, मैलानी, सीतापुर और मंकापुर में हाई मास्ट का प्रावधान। अनुमानित लागतः ₹ 96,81,881.39, बयाना राशिः ₹ 1,93,600/-, निविदा मूल्यः ₹ 0.00, कार्य सम्पादन की अवधिः 04 माह।

• उक्त निविदा बन्द होने की अंतिम तिथि व समयः 14-08-2024 को 15:00 बजे।

नोटः– इस निविदा के विरूद्ध मैनुअल आफर स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे प्राप्त मैनुअल आफर को उपेक्षित कर दिया जायेगा। विस्तृत विवरण व निविदा जमा करने हेतु कृपया भारतीय रेलवे की वेबसाइट *http://www.ireps.gov.in* को देखें।

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/सामान्य
मुजाधि/विद्युत–88 लखनऊ

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।



**उत्तर रेलवे**

आज़ादी का अमृत महोत्सव

**ई–निविदा सूचना**

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/सा0, मंडल रेल प्रबंधक, कार्यालय हज़रतगंज, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ई–निविदा सूचना सं0 | 1101–वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता–उत्तर रेलवे–लखनऊ–चतुर्थ कॉल दिनांक 22.07.2024 |
| 2. | कार्य का नाम | पुराने प्रथम श्रेणी एफ०ओ०बी०, चारबाग स्टेशन से 04 नम्बर एस्केलेटर को लखनऊ मण्डल के अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करना। |
| 3. | अनुमानित लागत | रु० 96,67,103/– (छियानवे लाख सड़सठ हज़ार एक सौ तीन रूपये मात्र) |
| 4. | बयाना राशि | रु० 1,93,400/– (एक लाख तिरानवे हज़ार चार सौ रूपये मात्र |
| 5. | कार्य पूर्ण करने की अवधि | 06 माह। |
| 6. | ई–निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि व समय तथा खोलने की तिथि | दिनांक 14.08.2024 को 15:00 बजे तक तथा खुलने का समय उसी दिन 15:30 बजे वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/सा0, उत्तर रेलवे, हज़रतगंज, लखनऊ के कार्यालय में। |
| 7. | प्रस्ताव की वैधता | ई–निविदा खुलने की तिथि से 60 दिन। |
| 8. | उत्तर रेलवे की वेबसाइट | अतिरिक्त सूचना उत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर चेक की जा सकती है। |

सूचना सं0– 1101–वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता–उत्तर रेलवे–लखनऊ–चतुर्थ कॉल दिनांक 22.07.2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 2233/24



**कार्यालय ''श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद''**
**सिविल लाइन्स, आयुक्त कार्यालय परिसर, अयोध्या।**

पत्रांक: 96/PA/CEO-SAJTVP/2024 दिनांक: 23 जुलाई 2024

**सार्वजनिक सूचना**

श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद्, अयोध्या का गठन दिनांक 6–2–2024 को किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य जनपद अयोध्या की समस्त सांस्कृतिक, स्थापत्य सम्वन्धी विरासत की सौन्दर्य परक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने योजना तैयार करने एव पर्यटन विकास तथा विरासत संरक्षण करने आदि का है। गठित परिषद के पहचान हेतु कार्यालय के प्रतीक चिन्ह (LOGO) तैयार किया जाना है। प्रतीक चिन्ह (LOGO) के तैयार किये जाने हेतु व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रतीक चिन्ह (LOGO DESIGN) की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति प्रतियोगिता में भाग लेकर ''श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद'' के प्रतीक चिन्ह (LOGO) को तैयार कर परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्यालय ''आयुक्त परिसर कार्यालय, सिविल लाइन्स, अयोध्या के पते पर सील बन्द लिफाफे में पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर तक प्रेषित करना है। समस्त प्रतिभागियों के प्राप्त प्रतीक चिन्ह समिति के समक्ष रखे जायेगें। सर्वश्रेष्ठ प्रतीक चिन्ह का चयन समिति द्वारा किया जायेगा। सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को यथोचित पुरूस्कार, प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एंव अन्य समस्त प्रतिभागियों को प्रतिभागिता हेतु प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। किसी भी प्रतिभागी द्वारा तैयार प्रतीक चिन्ह को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार एंव चयनित प्रतिभागी को पुरूस्कार एंव अवशेष प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र दिए जाने का निर्णय परिषद की समिति द्वारा लिया जायेगा।

संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद
अयोध्या


# स्कूल प्रबंधन पर शिक्षक को नौकरी से निकालने का आरोप

कार्यालय संवाददाता लखनऊ

**पीड़ित ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को भेजा शिकायती पत्र**

अमृत विचार: राजधानी के निजी विद्यालय में पिछले 11 सालों से पढ़ा रहे शिक्षक को स्कूल प्रबंधन ने नौकरी से हटा दिया तो उसने गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से इसकी शिकायत भेजी है।

सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाने वाले कुलदीप तिवारी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह कह रहे हैं कि स्कूल ने ये कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि वो धार्मिक टिप्पणियां करते थे, जनहित में डाले गए कई मुकदमों में वादी हैं, तिलक लगाते हैं, कलावा पहनते हैं व शिखा रखते हैं। वो 10 नवंबर 2009 से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ऐशबाग राजेंद्र नगर प्रथम शाखा में गणित पढ़ाते रहे और सेवा में बिना किसी व्यवधान उन्होंने लगभग 15 साल से अध्यापन का काम किया है। उनके अनुसार नौकरी के दौरान वह साधारण भेष-भूषा में रहते थे, केवल हिंदू होने के नाते प्रतिदिन माथे पर तिलक लगाकर हैं, शिखा रखकर स्कूल जाते थे। तिवारी ने बताया कि उनके द्वारा अदालतों में डाले गए मुकदमें और उनकी भेष-भूषा की वजह से स्कूल की प्रिंसिपल जयश्रीकृष्णन एवं रीटा फ्लेमिंग द्वारा कई बार उन्हें कार्यालय में बुलाया गया और तिलक मिटाने व शिखा हटाने के लिए दबाव दिया गया। इसके अलावा उनका कहना है कि उनका अपमान करके कई बार उनका अभद्र ढंग से मजाक भी बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षक के आरोपों को खारिज करते हुए सीएमएस प्रवक्ता ऋषि खन्ना ने आरोपों को गलत बताया है।

# अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना को मिलेगी गति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बजट में ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में विकास और अनुसंधान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा के साथ उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना को और गति मिलेगी।

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि परमाणु रिएक्टरों की स्थापना से देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। इससे औद्योगिकरण के विकास के साथ पारंपरिक सूक्ष्म व लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। बजट में ऊर्जा भंडारण के लिए पम्प स्टोरेज इकाइयों की स्थापना को प्राथमिकता देने से ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। प्रदेश में पम्प स्टोरेज इकाइयों की स्थापना को गति मिलेगी। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही, उद्योग धंधे बढ़ने से आर्थिक तरक्की भी होगी।

उन्होंने कहा कि बजट में नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने व शहरी व्यवस्था के सुनियोजित विकास को महत्व दिया गया है। देश के 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी योजना से शहरों को बेहतर विकास किया जा सकेगा। पीएम आवास योजना के तहत देश के एक करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। शहरों में साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब बनने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।


**उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड**

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या 15/ECTC/2024-25: अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु पृथक निविदा दो भागों (पार्ट–I टेक्निकल बिड एवम् पार्ट–II फाइनेंशियल) में आमंत्रित की जाती है। 15–कार्य का नामः– 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, जेहटा लखनऊ में 33 के0वी0 भूमिगत केबिल के निकास हेतु केबिल ट्रेन्च के निर्माण का कार्य। कार्य की अनुमानित लागतः– रू. 88.58 लाख, कार्यावधिः– 2 माह। उक्त निविदा की Technical Bid एवम् अन्य शर्ते तथा मात्रा बीजक इत्यादि का विस्तृत विवरण www.upptcl.org पर देखा जा सकता है एवम् http://etender.up.nic.in साइट पर देखा एवम् प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 08.08.2024 को दोपहर 14:00 बजे तक साइट पर डाला/अपलोड किया जा सकता है तथा दिनांक 09.08.2024 को 15:00 बजे सार्वजनिक रूप से निविदायें खोली जायेगी। **''राष्ट्र हित में बिजली बचाए'' अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, कक्ष सं. 223 से 226, प्रथम तल, पारेषण भवन, उ0प्र0 एस0एल0 डी0सी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 2780–वि.जा.पा.मं.(ल.)/निविदा दिनांकः 23.07.2024**


## सार-संक्षेप

### 10 वर्ष बाद आयोजित होने वाली परीक्षा निरस्त

अमृत विचार, लखनऊः सवारी डिब्बा कारखाना उत्तर रेलवे आलमबाग में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की मंगलवार को पद से लिए विभागीय परीक्षा होनी थी। तकरीबन 10 वर्ष बाद कंप्यूटर के माध्यम से यह परीक्षा होनी थी। परीक्षा कारखाने से तकरीबन 22 किमी दूर एक निजी सेंटर में परीक्षा आयोजित की जानी थी। कर्मचारी सुबह से ही सेंटर पर पहुंचने गये थे, लेकिन रेल अधिकारियों की लापरवाही और सेंटर प्रबन्धन की मनमानी से सर्वर नहीं चल सके और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। हिन्द मजदूर सभा उत्तर प्रदेश के प्रांतीय मंत्री अरुण गोपाल मिश्र ने बताया कि रेल अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना रवैये लोग परेशान हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि सेंटर जानबूझ कर ऐसा चुना गया था जिससे परीक्षा न हो सके। इस मामले में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। सेंटर की भी जांच कराई जाए कि वह परीक्षा लायक है या नहीं। खासी मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहे कर्मचारी काफी निराश हुए हैं। कर्मचारियों ने शीघ्र पुनः परीक्षा आयोजित की जाने की मांग की है। परीक्षा रजत कॉलेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज में थी।



उप नेता सदन जासमीर अंसारी का स्वागत करते समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी। अमृत विचार

### विधान परिषद के उप नेता सदन जासमीर अंसारी का हुआ स्वागत

अमृत विचार, बख्शी का तालाब : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा पीडीए के तहत मो.जासमीर अंसारी को विधान परिषद में उप नेता सदन बनाए जाने की खुशी में विधानसभा क्षेत्र बख्शी का तालाब में शैलेंद्र सिंह पूर्व प्रधान एवं सपा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के कार्यालय पर विधान परिषद सदस्य जासमीर अंसारी का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव मो.अकील ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित किया। उप नेता सदन जासमीर अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी को अपने-अपने बूथों पर बहुत ही मेहनत और जिम्मेदारी के साथ में पार्टी को आगे बढ़ने का काम करना है। इस मौके पर सपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुनील भदोरिया, मो.अकील खान, हाशिम उद्दीन बेग, इकबाल अफजल, इलियास अहमद, तौहीद खान, हाशिम कुरैशी, अशफाक गाजी, मतलूब रजा, शफीक शेख के अलावा समाजवादी पार्टी के बहुत से पदाधिकारी मौजूद थे।

### 20 महिलाओं को मिलेगा असिटेंट फ्रूट एंड वेजीटेबल प्रॉसेसिंग का प्रशिक्षण

अमृत विचार, लखनऊ : आकांक्षा समिति में कार्यरत महिलाओं के लिए मंगलवार से कौशल उन्नयन कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें समिति की 20 महिलाओं को असिटेंट फ्रूट एंड वेजीटेबल प्रॉसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। समिति की सचिव प्रियंका प्रियदर्शी ने कहा कि इस प्रशिक्षण से महिलाओं की कार्य क्षमता का विकास तो होगा ही साथ वे व्यवसायिक रूप से स्वयं को और अधिक सक्षम व सबल बना सकेंगी।

### यूपी के कौस्तुभ और वैभव क्वार्टर फाइनल में

अमृत विचार, लखनऊ : गोमती नगर विजयंत खंड स्टेडियम में खेली जा रही आइटा चैंपियनशिप सीरीज टेनिस टूर्नामेंट के अंडर– 14 प्री क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश के कौस्तुभ सिंह और वैभव सरोज ने जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उत्तर प्रदेश के कौस्तुभ सिंह ने कनार्टक के सिद्धार्थ को 6–1, 6–0 से हराया। उत्तर प्रदेश के वैभव सरोज ने 6–1,6–1 से शिकस्त दे दी। यूपी के ध्रुव सिंह ने अपने ही प्रदेश के तीसरी वरीयता प्राप्त अर्जुन शर्मा को 7–5, 5–7, 10–7 से हरा कर उनको चैंपियन बनने की दौड़ से बाहर कर दिया।

### द विंची एक्सआई तकनीक से ऑपरेशन होंगे आसान : डॉ. गौरव

अमृत विचार, लखनऊ : गोमतीनगर स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल (सहारा हॉस्पिटल) में मंगलवार से द विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जरी सिस्टम शुरू हो गया है। इस नई टेक्नोलॉजी में मरीजों को कम से कम चीरों वाली जटिल सर्जरी की सुविधा मिलेगी। अस्पताल के डॉ. गौरव अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि द विंची एक्सआई सर्जिकल रोबोट के जरिए शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचा जाता है जहां ऑपरेशन करना चुनौतीपूर्ण होता है। सीने और पेलविस क्षेत्र में कैंसर होने पर यह तकनीक बहुत उपयोगी है।

### शाइन सिटी घाटाले में एक आरोपी गिरफ्तार

अमृत विचार, लखनऊ : शाइन सिटी घोटाला मामले में ईडी ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी हिमांशु कुमार पर आरोप था कि उन्होंने 25 करोड़ रुपये सेल कंपनियों में लगवाए थे। जिस निवेशक का 25 करोड़ रुपये लगा था उसने हिमांशु कुमार के खिलाफ शिकायत की थी। ईडी की जांच में भी हिमांशु कुमार जद में थे। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि हिमांशु कुमार ने स्वयं को शाइन सिटी से अलग कर लिया था।


**उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड**
**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड – प्रथम, कमरा सं0 115–120, पारेषण भवन, विभूति खण्ड– II, निकट मन्त्री आवास, गोमती नगर, लखनऊ–226010 (उ0प्र0)**

अल्पकालिक ई–निविदा संख्या 03/वि0पा0ख0प्र0–(ल0)/ 2024–25:–

अल्पकालिक ई–निविदा संख्या 03–वि0पा0ख0– प्र0(ल0)/2024–25, के विरूद्ध दिनांक 15.08.2024 को ''स्वतन्त्रता दिवस'' के उपलक्ष्य में पारेषण भवन के चारों ओर सजावट के लिए झालर लगवाने के कार्य हेतु निविदा प्रपत्र एवं धरोहर राशि 1200.00 दिनाँक 06.08.2024 को 12:00 बजे तक ई–टेन्डरिंग वेब साईट www.etender.up.nic.in पर अपलोड की जा सकती है। भाग–1 खुलने की तिथि 06.08.2024, समय 13:30 बजे, भाग–2 (प्राइस पार्ट्स) खुलने की तिथि तदानुसार ई–वेबसाईट पर सूचित की जायेगी। निविदा प्रपत्र मूल्य 590.00 मात्र (500.00 + G.S.T. @ 18% अतिरिक्त) कार्य की कुल मात्रा, निविदा विशिष्टीकरण व अन्य नियम एवं शर्ते ई–निविदा पोर्टल पर उपलब्ध है। अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा। निर्धारित तिथि के विस्तार तथा शुद्धि पत्र से सम्बन्धित सूचना यदि कोई होगी तो केवल वेबसाइट पर डाली जायेगी। अतः स्वयं को अपडेट रखने के लिए उपरोक्त वेबसाइट को नियमित देखें। ''राष्ट्रहित में बिजली बचाएं।'' **अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड –प्रथम, लखनऊ। पत्रांकः 923/वि0पा0ख0–प्र0(ल0)/टी0–03/2024–25 दि0 23/07/2024**



**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल–द्वितीय, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, पारेषण भवन, विभूति खण्ड, निकट मंत्री आवास, गोमती नगर, लखनऊ**

**ई–निविदा सूचनाः–** अनुभवी फर्मो/ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु निविदायें दो भागों में आमंत्रित की जाती हैं। ई–निविदा के द्वितीय भाग में मूल्य/दरें वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर ई–निविदा के प्रथम भाग के खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व 17:00 बजे तक अपलोड की जानी है। निविदा सम्बन्धी समस्त जानकारी, नियम व अर्हकारी शर्ते, निविदा प्रपत्र में अंकित है, जो वेबसाइट www.etender.up.nic.in से डाउनलोड कर अवलोकित/अपलोड की जा सकती है, निविदा का प्रथम व द्वितीय भाग वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर ही अपलोड किया जा सकेगा। निविदा से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र, भौतिक रूप से कार्यालय में स्वीकार नही किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कोई कारण बताये किसी अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकार/विभाजित/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। विस्तृत जानकारी, अन्य किसी प्रकार के संशोधन एवं तिथि विस्तार आदि के सम्बन्ध में निविदा अपलोड करने के दिनांक/समय तक कृपया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर लॉग ऑन करें एवं निविदा से सम्बन्धित विवरण www.upptcl.org पर भी देखा जा सकता है। (1) **ई–निविदा संख्या–वि0पारे0मं0–द्वि0/ल0/14/2024–25 (निविदा खुलने की तिथि 23–08–2024):** विद्युत पारेषण खण्ड रायबरेली के अन्तर्गत 400 के0वी0 जी0आई0एस0 उपकेन्द्र सिरसिरा, रायबरेली पर सी0सी0टी0वी0 सिस्टम की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य निविदा प्रपत्र अनुसार : धरोहर धनराशि रू0 59000/– निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 1770/– (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित), (2) **ई–निविदा संख्या–वि0पारे0मं0–द्वि0/ल0/15/2024–25 (निविदा खुलने की तिथि 23–08–2024):** विद्युत पारेषण खण्ड रायबरेली के अन्तर्गत 400 के0वी0 जी0आई0एस0 उपकेन्द्र सिरसिरा, रायबरेली पर पी0एल0सी0सी0 उपकरण, डी0जी0 सेट, अग्नि शमन प्रणाली की स्थापना एवं अन्य विविध कार्य निविदा प्रपत्र अनुसार : धरोहर धनराशि रू0 51000/–, निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 1770/– (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित), (3) **ई–निविदा संख्या– वि0पारे0मं0–द्वि0/ल0/16/2024–25 (निविदा खुलने की तिथि 23–08–2024):** विद्युत पारेषण खण्ड रायबरेली के अन्तर्गत विभिन्न 132 पारेषण उपकेन्द्र पर water purifiers की आपूर्ति एवं स्थापना कार्य निविदा प्रपत्र अनुसार : धरोहर धनराशि रू0 2200/– निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 590/– (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित) (4) **ई–निविदा संख्या–वि0पारे0मं0– द्वि0/ल0/17/2024–25 (निविदा खुलने की तिथि 23–08–2024):** विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, दही चौकी, उन्नाव पर 400 के0वी0 लाइन/ट्रान्सफार्मर बे पर लगे 400 के0वी0 एस0एफ0–6 सर्किट बेकरों की सम्पूर्ण ओवर हॉलिग का कार्य निविदा प्रपत्र अनुसार : धरोहर धनराशि रू0 17500/–, निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 590/– (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित), (5) **ई–निविदा संख्या–वि0पारे0मं0–द्वि0/ल0/ 18/2024–25 (निविदा खुलने की तिथि 23–08–2024) :** विद्युत पारेषण खण्ड उन्नाव के अन्तर्गत 200 के0वी0 उपकेन्द्र उन्नाव पर स्थापित स्काडा प्रणाली के अनुरक्षण का कार्य निविदा प्रपत्र अनुसार : धरोहर धनराशि रू0 2700/–, निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 590/– (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित), (6) **ई–निविदा संख्या– वि0पारे0मं0– द्वि0/ल0/19/2024–25 (निविदा खुलने की तिथि 23–08–2024):** विद्युत पारेषण खण्ड रायबरेली के अन्तर्गत 132 के0वी0 लाइन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले 132 के0वी0 DA+5 के 02 नग टावर 220 के0वी0 भदौरा, गाजीपुर से 132 के0वी0 बछरावां, रायबरेली पर ट्रान्सपोर्टेशन का कार्य निविदा प्रपत्र अनुसार : धरोहर धनराशि रू0 1000/–, निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 590/– (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित), (7) **ई–निविदा संख्या– वि0पारे0मं0–द्वि0/ ल0/20/2024–25 (निविदा खुलने की तिथि 23–08–2024):** विद्युत पारेषण खण्ड उन्नाव के अन्तर्गत विभिन्न पारेषण उपकेन्द्रों पर 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 सी0टी0, सी0वी0टी0/पी0टी0, सर्किट ब्रेकर्स एवं लाइटिंग अरेस्टर को आपातकालीन/ब्रेकडाउन की स्थिति में बदलनें का कार्य निविदा प्रपत्र अनुसार : धरोहर धनराशि रू0 3200/– निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 590/– (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित) **''राष्ट्र हित में बिजली बचायें'' अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल– द्वितीय, उ0प्र0पा0ट्रा0का0 लि0, पारेषण भवन, एस0एल0डी0सी0 कैम्पस, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ– 226010, पत्रांकः 2054/ETC-II/L/वि0पारे0मं0–द्वि0/ल0/निविदा सं0 14–20/2024–25 Date/दिनांकः 23.07.2024**



**पूर्वोत्तर रेलवे**

**ई-निविदा सूचनाः ओटी-11-2024**

उप मुख्य विद्युत इंजीनियर–II/निर्माण, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिये ''खुली'' निविदा आमंत्रित की जाती है। **निविदा सं० : ओटी–11–2024,** कार्य का विवरण : पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मण्डल अन्तर्गत गोरखपुर कैण्ट–बाल्मिकीनगर दोहरीकरण परियोजना के तहत गोरखपुर कैण्ट (Excl) – कप्तानगंज (Incl) खण्ड के ओएचई (2 x 25 केवी, एसी, 50 हर्टज) के डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण एवं कमीशनिंग का कार्य। अनुमानित लागतः रू. 23,45,31,724.06, बयाना राशि : 13,22,700.00, निविदा प्रपत्र का मूल्य–रू० निल, कार्य पूर्ण करने की अवधि – **12** माह। निविदा बन्द होने की अंतिम तिथि व समयः 14.08.2024 को 15.00 बजे, **नोटः** ● इस निविदा के विरूद्ध कोई मैनुअल आफर स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे प्राप्त मैनुअल आफर को उपेक्षित कर दिया जायेगा। विस्तृत विवरण व निविदा जमा करने हेतु, कृपया भारतीय रेलवे की वेबसाईट **www.ireps.gov.in.** को देखें। ● निविदा सूचना में यदि हिन्दी या अंग्रेजी के आलेखों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के ही आलेख मान्य होगा।

उप मुख्य विद्युत इंजीनियर-II/निर्माण
मुजाधि/विद्युत- 84 पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।



**कार्यालयः अधिशासी अभियंता जोन-3**
**जल कल विभाग, नगर निगम, लखनऊ**

पत्र सं0 709/E.E.-3/L.J.S./2024-25 दिनांकः 23/07/2024

**अति अल्पकालीन निविदा सूचना**

जल कल विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु नीचे दिये गये विवरण के अनुरुप कार्य को कराये जाने हेतु मोहरबन्द निविदायें दिनांक 30/07/2024 को 3:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते है। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनाँक 30/07/2024 को 1:00 बजे तक निविदा मूल्य का नगद भुगतान कैश काउन्टर पर करके प्राप्त किये जा सकते हैं। भरी हुई सील्ड निविदायें उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 3:30 बजे तक निविदा बाक्स में प्राप्त की जायेगी। निविदा बाक्स से प्राप्त सभी निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 4:00 बजे सांय काल खोली जायेगी।

| क्र0 सं0 | कार्य/आपूर्ति का विवरण | निविदा का मूल्य | धरोहर धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | जोन–3 के अन्तर्गत शिव मन्दिर के पास शिवपुरम त्रिवेणी नगर–III में मिनी नलकूप की बोरिंग के उपरान्त पुनर्विकास, पीग्रेवल एवं अन्य मैकेनिकल इत्यादि के कार्य। | 450.00 | 8500.00 |

नियम एवं शर्ते निविदा प्रपत्र में दी गई है, जिन्हें देखा जा सकता है। विस्तृत जानकारी अधिशासी अभियन्ता जोन–3 के कार्यालय में सम्पर्क कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। निविदा खुलने के दिनांक को यदि कोई अवकाश हो अथवा किसी कारणवश कार्यालय बन्द हो तो अगला कार्य दिवस ही निविदा खुलने का दिनांक होगा। निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी / महाप्रबन्धक में निहित है।

अधिशासी अभियन्ता, जोन–3
जलकल विभाग, लखनऊ



सभी प्रकार के रोगों का समाधान आयुर्वेद द्वारा



**सैक्स समस्याएं!!**

मर्दाना कमजोरी, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष
सेक्स में कमी, निःसन्तान दम्पत्ति अवश्य मिलें

प्रातः 10 बजे से सायं 07 बजे तक

सेक्स वर्धक दवाओं का उपयोग न करें ये दवाएं लाईलाज कर सकती है।

**राना डिस्पेंसरी** 9919792325 9415810891

पता : लाल कुआँ, मेन रोड (हुसैन गंज) लखनऊ

हर बुधवार सीतापुर में रोडवेज बस अड्डा के पास



अमृत विचार एक सम्पूर्ण अखबार

**क्लासीफाइड**

**NOTICE**

My name in the Discharge book & PPO of my husband service No 1076336K Late Hav Surya Karan Singh R/o kathgar, Dalmau, Raebareli, is wrongly mentioned as Sarswati Devi & Saraswati Devi respectively. My correct name for all purposes is Sarasvati Singh.

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे दो मूल विक्रय पत्र ग्राम तेलियार जिनका विक्रय पत्र संख्या 3286 दिनांकित–17– 8– 2019 व विक्रय पत्र संख्या 6425 दिनांकित– 4– 11– 2020 जोकि उपनिबन्धक कार्यालय निघासन में पंजीकृत हैं। दोनों मूल विक्रय पत्र के अंतिम पृष्ठ कहीं खो गए हैं। जिस पर बैनामा पंजीकृत होने का पूरा विवरण दर्ज है। काफी तलाश करने पर भी नहीं मिले हैं। अगर किसी को मिलें तो निम्न पते पर सूचित करें। **रिहाना खातून पत्नी अजीमुल्ला निवासी ग्राम पठानन पुरवा मजरा तेलियार थाना पढ़ुआ जनपद खीरी मो0–9919256630**

**NOTICE**

I have changed my name from Mohd Shadab to Mohd Shadab Khan for all purposes. S/o Mahmood Ali Khan, 292/173, Victoria Street, Bazar Khala, Lucknow

**सूचना**

सूचित हो कि पहले मेरा नाम BHOLANATH था अब मैंने बदलकर अपना नाम BHOLANATH NISHAD रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये । S/O: RAM MILAN R/O- 63, FATEHPUR SANGAT JAISINGPUR SULTANPUR

**सूचना**

पहले मेरा नाम SHILPI था अब मैंने बदलकर अपना नाम SHILPI SINGH PANWAR रख लिया है भविष्या में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जायेगा । W/O: LACHHMAN SINGH PANWAR, R/O- 101, AARIF APARTMENT, NEW HYDERABAD

**सूचना**

सूचित हो कि मेरी दुकान सं – 596 और 597 ई ब्लाक मार्केट राजाजीपुरम लखनऊ के आवंटन पत्र और कब्ज़ा पत्र की मूल प्रति खो गयी है जिसका प्रयोग अवैध है – **संतोष कुमार पुत्र कनहिया लाल गुप्ता निवासी – D–1/142, विराजखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ**

**सूचना**

सूचित हो कि मेरी हाईस्कूल की मार्कशीट में मेरे पिता का नाम गलती से अकील खान दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पिता का सही नाम अकील उस्मान खान है। इसी नाम से उन्हे जाना व पहचाना जाता है। **अरबाज उस्मान खान पुत्र अकील उस्मान खान, मकान नंबर 30, कुंवरपुर इमलाक, पोस्ट रायपुर खास, तहसील कायमगंज, जनपद फर्रूखाबाद, पिन नं. 209502**

**सूचना**

सूचित हो कि मेरे पिता का नाम पहले गुड्डू था अब सभी दस्तावेजों में गुड्डू प्रसाद दर्ज है दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है हाईस्कूल के अंकपत्र में मेरी जन्मतिथि 16/08/1996 सही दर्ज है। **मनोज कुमार पुत्र गुड्डू प्रसाद, निवासी– ग्राम व पो0, महराज नगर, तहसील–धौरहरा जिला–लखीमपुर खीरी**

**सूचना**

सूचित हो कि मै **सविता कोहली पत्नी स्व0 विजय कुमार कोहली, निवासिनी– 557/24 ख ओमनगर आलमबाग, लखनऊ** मेरे पुत्र अर्जुन कोहली के हाईस्कूल व इण्टरमीडियट के अंकतालिका व प्रमाण पत्र मे त्रुटिवश मेरा नाम सुनीता कोहली अंकित हो गया है जबकि मेरे आधार कार्ड मे मेरा नाम सविता कोहली अंकित है जो कि सत्य व सही है। यहकि सविता कोहली व सुनीता कोहली एक ही महिला के नाम है। अतः मेरे पुत्र अर्जुन कोहली के हाईस्कूल व इण्टरमीडियट अंकतालिका प्रमाण पत्र मे सही नाम सविता कोहली अंकित किया जाय।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मेसर्स लकी ट्रेडर्स विवेकनगर सुलतानपुर उ0प्र0 की साझेदारी से अशोक कुमार सिंह की पुत्र स्व0 राम कुमार सिंह निवासी विवेकनगर सुलतानपुर पृथक हो गए हैं। इनका फर्म के कोई लेना देना सरोकार एवं बकाया नहीं हैं। फर्म में नए साझीदार श्रीमती सुधा सिंह पुत्री स्व0 राम कुमार सिंह निवासी विवेकनगर को सुलतानपुर को शामिल किया गया है।

**साझीदार – राम बहादुर सिंह**

**नीलामी सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि थाना पचपेडवा जनपद बलरामपुर में सीज शुदा दो पहिया वाहनो की नीलामी दिनांक 29.07.2024 को समय 15.00 बजे थाना पचपेडवा परिसर में होगी। इच्छुक व्यक्ति नीलामी प्रकिया में सम्मलित होने के लिए नियत तिथि व समय पर थाना पचपेडवा बलरामपुर परिसर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें । अग्रिम धनराशि 5000/–रूपये जमा करना होगा। **–प्रभारी निरीक्षक थाना पचपेडवा जनपद बलरामपुर।**

**नीलामी सूचना**

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सिद्धौर बाराबंकी परिसर में 31 यूकेलिप्टस 1 गूलर 9 नीम सहित 42 पेड़ों की जिनका मूल्यांकन की राशि 87591 रुपये है कि नीलामी दिनांक 31.7.2024 को किया जा रहा है इच्छुक व्यक्ति नीलामी में पहुंचकर बोली लगाकर पेड़ों की खरीदारी कर सकते हैं।

## एक नजर

### पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को परिवार से मिलाया

**बाराबंकी, अमृत विचार :** महिला पुलिस ने तीन साल के गुमशुदा बच्चे को मंगलवार को दो घंटे में खोजकर परिजनों को सुपुर्द किया। महिला पुलिस को यह बच्चा आनन्द भवन स्कूल के पास भटकता मिला। यह बच्चा अपना घर भूलकर इधर उधर भटक रहा था। पुलिस के पूछने पर घर और पता स्पष्ट नहीं बता पा रहा था। बड़ी देर पूछने पर बच्चे ने बताया कि वह कोतवाली शहर का रहने वाला है पुलिस ने परिजनों का पता लगाकर बच्चे को उसके परिवार के पास सुपुर्द किया।

### चोरी के मोबाइल के साथ युवक गिरफ्तार

**बाराबंकी, अमृत विचार :** जीआरपी रेलवे द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को पुलिस ने उत्तर टोला बंकी निवासी जावेद को रेलवे स्टेशन परिसर में बने अस्पताल गेट से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के पास से पुलिस ने चोरी का एक मोबाइल फोन बरामद किया। जीआरपी पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।

### जुर्माना देकर छूटा आपराधिक मामलों का आरोपी

**बाराबंकी, अमृत विचार :** न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में आरोपी कोतवाली क्षेत्र निवासी गोरख नाथ पुत्र राजबहादुर को लापरवाही से वाहन चलाकर राहगीर को चोटिल करने के मामले में तीन हजार रुपये जबकि मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के निवासी धीरज पुत्र कुंजा को न्यायालय ने मारपीट करने के मामले मे छह सौ रूपये के जुरमाने की सजा के साथ न्यायालय उठने तक उपस्थित रहने की सजा सुनाई। आरोपियों ने जुर्माना भर कर न्यायालय के आदेश का पालन किया और छूट गये।

### पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट

**रामसनेहीघाट, बाराबंकी : अमृत विचार :** कोतवाली रामसनेहीघाट निवासी सिमरन पुत्री मनमीत ने कोतवाली में शिकायत पत्र देकर पति सहित ससुराल वालों पर बारबार मारपीट करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित महिला ने बताया कि पति सरदार भूपिंदर सिंह, ससुर अमरजीत सिंह व सास हरप्रीत कौर निवासी बशीरतगंज नाका हिंडोला राजेन्द्र नगर लखनऊ कम दहेज लाने को लेकर मारपीट करते हैं। साथ ही सास ससुर धमकी भी देते हैं कि दहेज अपने घर से और मंगाओ नहीं तो, पति भूपिंदर सिंह की दूसरी शादी कर देंगे। परिवार के लोग किसी न किसी बात पर दबाव बनाकर अक्सर मारते पीटते हैं। जिस पर मंगलवार को रामसनेहीघाट पुलिस ने शिकायत दर्ज की।

## रीठी सिकंदरपुर में ग्राम प्रधान और बीडीसी पद की सरगर्मी तेज

**हैदरगढ़, बाराबंकी**

**अमृत विचार:** विकास खंड हैदरगढ़ की रीठी सिकंदरपुर ग्राम पंचायत के प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए आगामी 6 अगस्त को मतदान एवं आगामी 8 अगस्त को मतगणना होगी। वहीं प्रत्याशियों के नामांकन के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है।

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रधान पद के लिए रमेश चंद, अरविंद कुमार, माया देवी, चेतराम, दुर्गेश कुमार, राम नेवाज एवं रामखेलावन आदि दावेदारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वहीं यहां की अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित क्षेत्र पंचायत सदस्य सीट के लिए आशा देवी एवं रंजना द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। सोमवार को अंतिम दिन नामांकन के बाद आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। जिसमें सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए। इसके बाद सभी दावेदारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया। दोनों पदों के लिए आगामी 6 अगस्त को मतदान होगा और आगामी 8 अगस्त को मतगणना के बाद कौन प्रधान बनेगा और कौन क्षेत्र पंचायत सदस्य। इसकी तस्वीर तभी साफ हो जाएगी।

## शासन को भेजे प्रस्ताव जल्द होंगे विकास कार्य

**सुबेहा, बाराबंकी: अमृत विचार:** आदर्श नगर पंचायत सुबेहा में सोमवार को हुई बोर्ड बैठक के बाद विस्तारित वार्डो के साथ-साथ अन्य वार्डो में विकास कार्यो की रूपरेखा तैयार कर ली गई। जिसमें गढ़ी वार्ड के अल्पी का पुरवा से चकौरा ग्राम तक आर.सी.सी मार्ग व नाली निर्माण, गढ़ी वार्ड के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक तक रोड़ व विद्यालय में टाइलीकरण तो वहीं पलिया वार्ड में तीन सड़कों का प्रस्ताव भेजा गया है। इसी तरह नव गठित वार्ड सरांय चन्देल में चार जगहों पर नाली व सड़क निर्माण तो हैदरगढ़ -शुक्लबाजार मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लगाये जाने का प्रस्ताव भी शामिल हैं।

## हाईवे पर आपस में भिड़ी पिकअप, लगा जाम

**मसौली, बाराबंकी**

**अमृत विचार:** बाराबंकी-रामनगर हाईवे पर पिकअप की आमने सामने की टक्कर में दोनों चालक घायल हो गए। जिसमें एक कि हालात गम्भीर बताई जा रही है। हाइवे पर एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर पहुंची मसौली पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजकर,हाइवे के भीषण जाम से लोगों को निजात दिलाई।

दोपहर करीब दो बजे बाराबंकी बहराईच हाइवे पर लखनऊ से आम लेकर गोण्डा और रामनगर की तरफ से बाराबंकी जा रही तेज रफ्तार पिकप में जोरदार टक्कर हो गई।

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन और बिखरा सामान। अमृत विचार

**दोनों वाहनों के चालक घायल जिला अस्पताल रेफर**

टक्कर में दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गये और पिकप में लदा आम रोड पर बिखर गया। एक्सीडेंट में पिकप चालक जुबेर पुत्र मो नसीर उम्र 40 वर्ष व दूसरी पिकप का ड्राइवर गम्भीर रूप से घायल हो गया। जो अपना नाम व पता बता पाने में असमर्थ नजर आ रहा था। हादसे की सूचना पर पहुंचे मसौली थाना प्रभारी अरुण प्रताप सिंह, सब इंस्पेक्टर अभय गुप्ता, कांस्टेबल प्रियांशु यादव ने लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। हादसा होने से हाइवे पर दोनों तरफ करीब एक किमी. लम्बा जाम लग गया। ग्रामीणों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ट्रैक्टर लाकर क्षतिग्रस्त गाड़ियों को रोड से हटाकर किनारे कर दिया। दोपहर में भीषण गर्मी होने के कारण जाम लगने से यात्री बेचैन हो उठे लेकिन पुलिस की सूझबूझ से करीब एक घण्टे बाद लोगों को जाम से निजात दिलाया जा सका।

# निखरेगी प्रतिभा, हर स्कूल के होंगे अपने खेल

## जिले में संचालित हैं 323 विद्यालय, खेलों की सूची में शामिल हैं 26 तरह के खेल

**रीतेश श्रीवास्तव, बाराबंकी**

**अमृत विचार:** माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाई के साथ खेलों में अपनी रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को अब और निखारा जाएगा। इसके लिए सरकार ने स्पोर्ट्स फॉर स्कूल योजना की शुरुआत की है। इसके के तहत स्कूलों को अधिकतम पांच या फिर कम से कम दो खेल चिन्हित करना होगा। इसके बाद उसकी एक टीम बनाकर आयोजित प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा कराई जाएगी। इसके बाद उन्हें जिला और मंडल स्तर पर प्रतिभाग कराकर आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। जिले में माध्यमिक शिक्षा के करीब 323 विद्यालय संचालित हैं। जबकि खेलों की सूची में 26 तरह के खेल शामिल किए हैं। वहीं इस व्यवस्था से खिलाड़ियों को काफी हद तक अपने खेल में निखरने का मौका मिल सकेगा।

माध्यमिक स्कूल के खिलाड़ियों को अब अपनी प्रतिभा निखारने के लिए कहीं भटकना नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बेहतर खेल का माहौल बनाया जाएगा। स्पोर्ट्स फॉर स्कूल योजना के तहत अब स्कूलों में प्रतियोगिताएं कराईं जाएंगी। जिसमें गांव की प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इससे खेल का बेहतर माहौल तैयार होगा। गांव के खेल में प्रतिभा रखने वाले युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। दरअसल विद्यालय में छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ ही खेल में प्रतिभाग कराने का नियम है लेकिन विद्यालय में खेल की गतिविधियां नाम मात्र की होती हैं। या यूं कहे की खेल के आयोजन अब न के बराबर ही हैं। जब खेल प्रतियोगिता कराने का आदेश आता है तो कोरम जैसे-तैसे पूरा कराया जाता है। इस नई योजना और व्यवस्था से अब विद्यालय में ही खेल प्रतियोगिताएं करानी होंगी। जिले में 323 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इस योजना के बारें में सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है।

केडी सिंह बाबू स्टेडियम में फुटबॉल खेलतीं महिला खिलाड़ी। (फाइल फोटो)

**माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को चुनना होगा दो से पांच खेल**

**स्पोर्ट्स फॉर स्कूल योजना के तहत होगा स्कूल, खेल और बच्चों का पंजीयन**

### यह है योजना की तैयारी

हर विद्यालय की ओर से अपना एक खेल चुना जाना है। इसमें कबड्डी, खो-खो, दौड़, ऊंचीकूद, लंबीकूद, भाला फेंक, क्रिकेट, फुटबाल, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेक्टिस, टेनिस सहित अलग-अलग 26 खेलों में से अधिकतम पांच या कम से कम दो खेलों को चयनित करना होगा। उसकी विद्यालय स्तर पर टीम तैयार की जाएगी। पहले विद्यालय फिर ब्लॉक स्तर पर समय-समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित कराके खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा का आकलन किया जाएगा, ताकि उन्हीं खिलाड़ियों का जिला और मंडल स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में लाया जा सके इसके बाद यहां के विजेता को आगे जाने का अवसर दिया जाएगा।

> स्पोर्ट्स फॉर स्कूल योजना के तहत 26 खेलों की सूची में से सभी स्कूलों को दो से पांच तक खेलों को चयन करना होगा। इसके लिए स्कूल, खेल और फिर बच्चों का पंजीकरण कराना होगा। पंजीयन का काम चल भी रहा है। ब्लॉक, जिला और मंडल स्तर के विजेताओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा।
>
> -ओपी त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक।

## उत्कृष्ट कार्य और दायित्व निभाने पर मिला सम्मान

**कार्यालय संवाददाता, बाराबंकी:**

**अमृत विचार:** बेसिक शिक्षा विभाग के जिला स्काउट मास्टर, जिला गाइड कैप्टन की तीन दिवसीय कार्यशाला में जिलों में किए जा रहे हैं स्काउट गाइड गतिविधियों की समीक्षा शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश एवं प्रादेशिक संस्था उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड द्वारा की गई। इसके तहत उत्कृष्ट कार्य और अपना दायित्व निभाने पर जिले के स्काउट मास्टर एवं जिला गाइड कैप्टन को सम्मानित किया गया।

गौरतलब है कि प्रादेशिक मुख्य आयुक्त प्रभात कुमार पूर्व आइएएस व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के अनुमोदन पर शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा समस्त विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को निशुल्क स्काउट गाइड शिक्षा प्रदान कर प्रत्येक संवर्ग में एक-एक दल का गठन किया गया है। जिसके यूनिट लीडर (शिक्षकों) को जल्द स्काउट गाइड का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें उत्कृष्ट कार्य एवं दायित्व निर्वहन के लिए प्रदेश स्तर पर जिले के स्काउट मास्टर राजेंद्र त्रिपाठी एवं जिला गाइड कैप्टन ऋतु अग्निहोत्री को प्रदेश स्तर पर मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रयागराज तनुजा त्रिपाठी, प्रादेशिक आयुक्त राजेश मिश्रा, प्रादेशिक सचिव आनंद सिंह रावत ने सम्मानित किया। कार्यशाला का संचालन प्रदेशिक संगठन आयुक्त कामिनी श्रीवास्तव एवं हीरालाल यादव द्वारा किया गया। प्रगतिशील प्रशिक्षण पर प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त अरविंद कुमार श्रीवास्तव द्वारा ट्रेंनिंग शेड्यूल में किए गए नए परिवर्तनों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से जिला स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में सम्मानित करते मुख्य अतिथि।

**टिकैतनगर मुख्य मार्ग के किनारे झाड़ियों में मिला शव**

**टिकैतनगर, बाराबंकी, अमृत विचार :** थाना टिकैतनगर अंतर्गत ग्राम मंझेला मोड़ पर नवनिर्मित शवदाह गृह व भेलसर टिकैतनगर मुख्य मार्ग के किनारे मंगलवार सुबह उधर से गुजर रहे राहगीरों ने झाड़ियों में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ देखा। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा कि शव के ऊपर का अधिकांश हिस्सा सड़ चुका था। जिससे शव पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस ने बताया कि शव देखने में करीब 35 से 40 वर्षीय व्यक्ति का है। शव तीन से चार दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। वही इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक संजीत सोनकर ने बताया कि शव की पहचान अभी नही हो पाई है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण पता लगाया जा सकेगा।

## एससी-एसटी एक्ट में वांछित गिरफ्तार

**बाराबंकी, अमृत विचार:** पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को हैदरगढ़ पुलिस टीम ने एससी-एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त अनुपम मिश्रा निवासी ग्राम पूरे भवानी सिंह का पुरवा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार किया गया अभियुक्त पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था।

## विहिप कार्यकर्ताओं ने की मांस की बिक्री पर लगे प्रतिबंध

**फतेहपुर, बाराबंकी**

**अमृत विचार:** सड़कों पर खुलेआम बिक रहे मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी राजेश विश्वकर्मा को ज्ञापन सौंपा है।

श्रावण माह का पवित्र माह सोमवार से शुरु हो चुका है। जिसमें हजारों की संख्या में कांवडिया कांवर लेकर निकलते हैं। वहीं सड़क किनारे खुलेआम मांस बेचा जाता है। जहाँ तहां तो यह स्थिति होती की सड़क किनारे निकलने वाले शिवभक्तों से जानबूझकर काफी दिक्कतें होती है। बड़ूपुर, घूंघटेर, कुर्सी में मुख्य रास्तों पर यह काम दुकानदारों द्वारा किया जाता है। मांस की खुली बिक्री पर रोक लगाने के लिए विहिप / बजरंगदल पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान बजरंग दल जिला सह संयोजक उमेश यादव, प्रखंड निन्दूरा संयोजक मुकेश सिंह, सह संयोजक आशीष सोनी, विनय वर्मा, पवन कुमार, विजय, मनोज, अभिषेक और डब्बू आदि लोग शामिल रहे।

उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते विहिप कार्यकर्ता। अमृत विचार

## सीज ट्रक की चाभी लेकर मालिक फरार

**सतरिख, बाराबंकी**

**अमृत विचार:** एआरटीओ और खनन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा मंगलवार को चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें एक ओवरलोडिंग ट्रक को सीज करते हुए सतरिख थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। चौकाने वाली बात यह रही कि वाहन स्वामी ट्रक की चाबी निकालकर मौके से भाग गया। पुलिस की मदद से उसे लाकर वाहन को थाने ले जाया गया।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अंकिता शुक्ला, जिला खनन अधिकारी शैलेंद्र कुमार मौर्य ने टीम के साथ मंगलवार को शासन के निर्देश पर अवैध खनन, परिवहन, ओवरलोडिंग को रोकने को लेकर अभियान चलाया। बताते है की सतरिख इलाके में मिट्टी का अवैध और बालू का कारोबार काफ़ी जोरों पर चल रहा है। जिसमें बिना नंबर के डंपर-ट्रक मिट्टी और बालू को लाद कर फर्राटा भर रहे हैं। और ओवरलोडिंग कर राजस्व विभाग को क्षति का भी नुकसान कर रहे हैं। जिसे लेकर परिवहन विभाग की टीम सतर्क हो गई थी। सतरिख कस्बे के पास टीम के द्वारा कई वाहनों की चेकिंग की गई है। जिसमें एक वाहन ओवरलोडिंग मिला है। वाहन चालक द्वारा टीम को वाहन के खनन परिवहन संबंधित कागजात नहीं दिखा पाने पर वाहन को सीज किया गया। टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन पर बालू लदा हुआ पाया गया है। वाहन स्वामी को ट्रक सीज होने की जानकारी पर मौके पर पहुंच गया और टीम को चकमा देकर ट्रक की चाभी को लेकर फरार हो गया। टीम को चाभी पाने के लिए सतरिख पुलिस को भी बुलाना पड़ा। सतरिख पुलिस की मदद और कड़ी मशक्कत के बाद वाहन स्वामी से चाभी मिल सकी। तब जाकर ट्रक को थाने में दाखिल किया जा सका है। एआरटीओ अंकिता शुक्ला ने बताया है कि मोटर अधिनियम के तहत वाहन का चालान करते हुए वाहन स्वामी व चालक के विरुद्ध खनिज अधिनियम और राजस्व विभाग को क्षति पहुंचाने के तहत सतरिख थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

परिवहन विभाग द्वारा सीज किया गया वाहन। अमृत विचार

**एआरटीओ व खनन अधिकारी की संयुक्त टीम ने की थी चेकिंग**

**पुलिस की मदद से पकड़ कर लाने के बाद थाने भेजा गया ट्रक**

## सार-संक्षेप

### लाइसेंस के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन

**कार्यालय संवाददाता, बाराबंकी : अमृत विचार :** जिला कृषि अधिकारी राजित राम ने बताया कि उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक का व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस बनवाने के लिये ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि लाइसेंस नया जारी करवाना हो, नवीनीकरण करवाना हो या फिर डुप्लीकेट कॉपी जारी करवाना हो, सभी के आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। आवेदक आवेदन के लिए विभागीय वेबसाइट में जनहित गारंटी पर जाकर ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन पर क्लिक कर मांगे गए अभिलेख पोर्टल पर ही फीड एवं अपलोड करें। आवश्यक अभिलेख और निर्धारित शुल्क की जानकारी भी ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगी। निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा होता है। इसके बाद पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को नियमानुसार सत्यापन व जांच की कार्रवाई पूर्ण कर लाइसेंस जनरेट किया जाता है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन किए गए आवेदन में अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है या कोई अभिलेख अपूर्ण रहता है, तो इसको सुधार करने के लिए उसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपत्ति लगाकर उसे दुरुस्त करने अवसर दिया जाता है। सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने पर उर्वरक एवं बीज विक्रय का लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। आवेदक अपना लाइसेंस प्रिंट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लाइसेंस की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए किसी भी आवेदक को कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उर्वरक एवं कीटनाशक लाइसेंस के लिए आवेदक के पास बीएससी एजी या कैमिस्ट्री की योग्यता होना जरूर है। इसके साथ ही डिप्लोमा करके भी आवेदक अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं।

### विद्युत कटौती पर दी खामियाजा भुगतने की धमकी

**त्रिवेदीगंज, बाराबंकी : अमृत विचार :** संविदा लाइन मैन ने एक विद्युत उपभोक्ता के खिलाफ थाने पर गाली व जान से मारने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। भिलवल स्थित विद्युत वितरण उप केन्द्र पर कार्यरत संविदा लाइन मैन सूर्य कांत यादव ने थाने पर दर्ज कराई गई प्राथमिकी में भिलवल बाजार निवासी सलमान पर आरोप लगाया है कि उसने हो रही विद्युत कटौती के खिलाफ सूर्य कांत यादव को गाली देना शुरु किया तो लाइन मैन ने कहा कि विद्युत कटौती के सम्बन्ध में उसे गाली देने के बजाय उच्च अधिकारियों से बात करो। इतना सुनते ही सलमान ने आक्रोशित होकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए कहा कि भविष्य में बिजली काटने पर तुम्हें खामियाजा भुगतना होगा। सलमान से जान माल का डर बताते हुए दर्ज कराई गई प्राथमिकी में लिखा है कि वह रात दिन काम करता है उसे जान का खतरा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

### तमंचा के साथ युवक गिरफ्तार

**बाराबंकी, अमृत विचार :** अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को लोनीकटरा पुलिस टीम ने ग्राम तख्ता पो .गदीया निवासी सूरज सिंह पुत्र स्व .नरेन्द्र सिंह को लेकर गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने अभियुक्त के पास से अदद तमंचा व एक अदद कारतूस बरामद किया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

### पुलिसकर्मियों को फूल-माला पहनाकर दी विदाई

पुलिसकर्मियों को विदाई देते थाना प्रभारी रत्नेश पांडेय। अमृत विचार

**रामनगर, बाराबंकी, अमृत विचार :** सुढ़ियामऊ चौकी इंचार्ज सहित थाने में तैनात 11 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण जिले के अन्य थाने पर होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी रत्नेश पांडेय ने सभी को फूलमाला पहनाकर विदाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा की जिस तरह से सभी साथियों ने अभी तक रामनगर थाने पर ईमानदारी पूर्वक जनता के बीच समस्याओं का निस्तारण करने के लिए पूर्ण सहयोग दिया है। उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। सभी कर्मियों ने थाने पर गरीबों, शोषितों व पीड़ितों की समय-समय पर ईमानदारी के साथ मदद की है। ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी आगे भी अच्छे कार्य कर विभाग का नाम रोशन करें। थाना प्रभारी ने उप निरीक्षक राममूर्ति कनौजिया, शुभम तिवारी, कपिल पटेल, कुलदीप, अखिलेश, अमन कुमार, शिव बहादुर, अजय यादव, ऋषभ सिंह, गौरव कुमार व अन्य स्थानांतरित पुलिस कर्मियों को फूलमाला पहनाकर नम आंखों से विदाई दी।

**बदहाली** पीएचसी में बंद ताला, सीएमओ कार्यालय में काम कर रहे वार्ड ब्वॉय और स्वीपर और अस्पताल की बेपटरी हैं स्वास्थ्य सेवाएं

# हालात पैदा कर रहे जिम्मेदार, निजी डॉक्टरों के पास पहुंच रहे मरीज

**सचिन कुमार, सतरिख, बाराबंकी**

**अमृत विचार:** अस्पताल में डॉक्टर से लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी गायब रहे। मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ा। इलाज न मिलने पर मरीजों ने प्राइवेट चिकित्सक का सहारा लिया है। एसीएमओ ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं।

हरख विकास खंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टेरा में मंगलवार को ताला बंद रहा। अस्पताल पहुंचे मरीज बिना इलाज के लौट गए। पनिहल पंचायत के निवासी मुन्ना तथा रिंकू इलाज के लिए मंगलवार की सुबह 9 बजे टेरा अस्पताल गए हुए थे। मरीजों का कहना है कि मुख्य गेट बंद था। एक वृद्ध महिला अंदर मौजूद थी। आवाज लगाने पर उसने गेट खोला। मरीज ने डॉ. साहब के बारे में पूछा तो सवाल पर महिला ने कहा कि आ रहे होंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद बिना दवाई के मरीज लौट आए। टेरा गांव के निवासी ओपी वर्मा ने बताया कि यहां स्टाफ नियमित नहीं आता है। यदि आए भी तो 10 बजे के पहले नहीं आते हैं। कई बार गांव वालों ने सीएमओ कार्यालय में इसकी जानकारी दी है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। यह अस्पताल सिर्फ कागजों पर संचालित हो रहा है और नाम का बचा हुआ है।

मरीजों और लोगों के मुताबिक अस्पताल के हालात बद-से-बतर हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसर अस्पतालों का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। जिस कारण कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं और तैनात कर्मी मनमानी करते हैं। इलाज न मिलने पर मरीज प्राइवेट चिकित्सकों के पास जाने को मजबूर हैं।

पीएचसी टेरा में तैनात डॉक्टर की खाली पड़ी कुर्सी। अमृत विचार

बंद पड़ा औषधि भंडार।

पीएचसी टेरा परिसर में उगी झाड़ियां।

### इनकी स्वास्थ्य कर्मियों की है तैनाती

गौरतलब है कि सीएचसी टेरा में डॉ. ज्योति सिंह, फॉर्मासिस्ट के के सिंह, एलए दीपक मौर्य, एलटी विशाल श्रीवास्तव की तैनाती है। इसके अलावा वार्ड बॉय तथा स्वीपर की तैनाती भी यहां है लेकिन वे काम मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में कर रहे हैं। जबकि दोनों का वेतन सतरिख सीएचसी से निकल रहा है। वहीं अस्पताल में किसी सफाई कर्मी न होने के कारण स्टॉफ के लोग चंदा लगाकर एक वृद्ध महिला से सफाई करवाते हैं।

> अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी को समय से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। यदि अस्पताल में डॉक्टर से लेकर स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुंच रहे हैं और मरीजों को निजी चिकित्सक का सहारा लेना पड़ रहा है, तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
>
> -डॉ. डीके श्रीवास्तव, एसीएमओ।

## विजय दिवस का जश्न

बीकानेर के आर्मी क्षेत्र में मंगलवार को कारगिल विजय दिवस का जश्न मनाया गया। एक के बाद एक कर्तव्य करते हुए भारतीय सेना के जवानों ने लोगों में जोश भर दिया। ● एजेंसी

## आईएएस की पत्नी ने की आत्महत्या, नोट में लिखा मैं निर्दोष

**अहमदाबाद।** गुजरात में आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार जे. की अलग रह रहीं पत्नी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पूर्व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने दक्षिणी राज्य में उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों में खुद को निर्दोष बताया।

पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूर्या (45) की 21 जुलाई को गांधीनगर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। एक दिन पहले उन्होंने अपने पति के सरकारी आवास के पास एक उद्यान में जहर खा लिया था। कुमार 2005 बैच के आईएएस अधिकारी है।

### यूपीएससी परीक्षा में माता-पिता के अलग होने का दावा कर ट्रेनी आईएएस ने गलत तरीके से लिया लाभ

# केंद्र ने वैवाहिक स्थिति की जानकारी मांगी

पुणे, एजेंसी

केंद्र ने पुणे पुलिस को निर्देश दिया है कि वह विवादों में घिरीं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर के माता-पिता की वैवाहिक स्थिति से उसे अवगत कराए।

अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने यह निर्देश पूजा पर यह आरोप लगने के बाद दिया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने माता-पिता के अलग होने का दावा कर यूपीएससी परीक्षा में गलत तरीके से ओबीसी गैर क्रीमी लेयर का लाभ लिया। खेडकर पर महाराष्ट्र के पुणे जिला कलेक्टरेट में प्रशिक्षण के

दौरान ऐसी सुविधाएं और भत्तों की मांग करके ताकत और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप है, जिनकी वह हकदार नहीं थीं। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आस-पास के सभी लोगों को धमकाया और अपनी निजी ऑडी (एक लग्जरी कार) कार के ऊपर लाल-नीली बत्ती (उच्च पदस्थ अधिकारी को दर्शाती) लगाई। पूजा खेडकर के खिलाफ पिछले हफ्ते दिल्ली में गलत जानकारी देने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

### यूपीएससी ने कारण बताओ नोटिस किया जारी

यूपीएससी ने भी 2022 की परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं में भाग लेने से रोकने पर विचार कर रहा है। पुणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि केंद्र सरकार ने यह बताने को कहा है कि क्या पूजा खेडकर की मां मनोरमा और पिता दिलीप का तलाक हो गया है। उन्होंने कहा हमें यह पता लगाने और केंद्र सरकार को सूचित करने को कहा गया है कि क्या पूजा खेडकर के माता-पिता का तलाक हो गया है। संक्षेप में हमसे उनकी शादी/तलाक की वास्तविक स्थिति को सत्यापित करने के लिए कहा गया है। यूपीएससी ने पिछले सप्ताह पूजा खेडकर के खिलाफ फर्जी पहचान के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी से शामिल होने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने सहित कई कार्रवाई की थी।

## एक नजर

### एसआई भर्ती परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले के आरोपी का अवैध मकान ढहाया

**जयपुर।** चूरू नगर परिषद की एक टीम ने राजस्थान पुलिस उप-निरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 के प्रश्नपत्र लीक मामले के आरोपी के अवैध रूप से निर्मित पक्के मकान को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की गई। सहायक अभियंता रवि राघव के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर के साथ पूनिया कॉलोनी पहुंची तथा प्लॉट नंबर 114 व 115 पर बने अवैध मकान को ढहा दिया।

### अज्ञात बदमाशों ने रेलवे लाइन पर सरिया डाला, हादसा टला

**जयपुर।** राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कुछ अज्ञात बदमाशों ने रविवार देर रात रेलवे लाइन पर सरिया डाल दिया। हालांकि, वहां से गुजरने वाली ट्रेन के चालक ने समय पर ब्रेक लगा दिया, जिससे संभावित हादसा टल गया। पुलिस ने बताया कि असारवा-जयपुर एक्सप्रेस के रविवार रात करीब 11 बजे डूंगरपुर स्टेशन से रवाना होने के कुछ ही देर बाद यह घटना घटी। पुलिस के मुताबिक, लगभग चार किलोमीटर की यात्रा के बाद लोको पायलट ने पटरियों पर पड़े सरिये को दूर से देख लिया और ब्रेक लगा दिए।

### प्रख्यात गायक रमन बरुआ का नहीं लगा सुराग

गुवाहाटी। असम पुलिस ने सोमवार से लापता प्रख्यात गायक, संगीतकार और निर्देशक रमन बरुआ की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। गुवाहाटी के लतासिल इलाके में रहने वाले 84 वर्षीय बरुआ सोमवार सुबह मंदिर जाने के लिए घर से निकले थे लेकिन जब देर शाम तक नहीं लौटे तो उनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वह मंदिर के नजदीक स्थित गुवाहाटी उच्च न्यायालय की नई इमारत के पास सुबह करीब सवा 10 बजे आखिरी बार देखे गए थे।

### आठ हजार की रिश्वत के आरोप में अधिकारी गिरफ्तार

**पालघर।** भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पालघर जिले के विक्रमगढ़ में आठ हजार रुपये की रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सहायक अभियंता (श्रेणी-2) संदीप जवाहर विक्रमगढ़ में तैनात है। पालघर एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक दयानंद गावड़े ने बताया कि शिकायतकर्ता ने अपने पिता के नाम पर दो बिजली मीटर लगाने के लिए आवेदन किया था।

# नीट-यूजी : आईआईटी के विशेषज्ञों ने कहा- केवल एक उत्तर ही सही था

## भौतिकी के प्रश्न को लेकर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के तीन विशेषज्ञों की समिति ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 में पूछे गए भौतिकी के एक विवादास्पद प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर था, न कि दो। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने सोमवार को आईआईटी-दिल्ली के निदेशक को भौतिकी के इस विवादित प्रश्न को लेकर तीन विषय विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने तथा मंगलवार दोपहर तक सही जवाब पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

सुनवाई शुरू होने पर सीजेआई ने रिपोर्ट में लिखी बातों का हवाला दिया और कहा हमें आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट मिली है। आईआईटी निदेशक रंगन बनर्जी ने भौतिकी विभाग की एक समिति गठित की और वे बताते हैं कि तीन विशेषज्ञों की एक टीम ने प्रश्न की जांच की। टीम का कहना है कि चौथा विकल्प सही जवाब है। सीजेआई ने कहा कि चौथा विकल्प, जो कहता है कि 'पहला कथन सही है, लेकिन

दूसरा कथन गलत है, सही जवाब है। पीठ ने कहा समिति ने साफ तौर पर कहा है कि केवल एक सही विकल्प था, जो कि चौथा विकल्प है। इसलिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) अपनी उत्तर पुस्तिका में सही थी, जिसमें चौथे विकल्प को सही बताया गया था। अभी इस मामले की सुनवाई जारी है।

केंद्र व एनटीए की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश कर रहे हैं। कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें विवादों में घिरी इस परीक्षा को इस आधार पर दोबारा कराने का अनुरोध करने संबंधी याचिका भी शामिल है कि इसका प्रश्न पत्र लीक किया गया तथा परीक्षा के आयोजन में अन्य अनियमितताएं भी

### वकील से हुई तीखी नोकझोंक, प्रधान न्यायाधीश ने कहा- सुरक्षाकर्मी को बुलाइये

**नई दिल्ली।** उच्चतम न्यायालय में, नीट-यूजी 2024 पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और अपनी बारी आने से पहले बोलने पर आमादा एक वकील के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसपर सीजेआई ने उन्हें अदालत कक्ष से बाहर निकाल देने की चेतावनी दी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि वह किसी भी वकील को अदालत में मनमर्जी नहीं करने देंगे। प्रधान न्यायाधीश ने कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा को उस समय फटकार लगाई, जब उन्होंने बार-बार आग्रह किया कि उन्हें बहस करने की अनुमति दी जाए, जबकि याचिकाकर्ताओं के मुख्य वकील वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र हुड्डा अपनी दलीलें पेश करने वाले थे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने नेदुम्परा से कहा कि पीठ हुड्डा द्वारा अपनी दलीलें पेश करने के बाद उन्हें बहस करने की अनुमति देगी। पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा आप कृपया बैठ जाइए। मुझे आपको अदालत से बाहर निकालना पड़ेगा। उन्होंने गुस्से में कहा मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। हालांकि, नेदुम्परा लगातार शिकायत करते रहे कि उन्हें अदालत में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इस बात से नाराज प्रधान न्यायाधीश ने कहा कृपया सुरक्षाकर्मियों को बुलाइये। हम उनसे इन्हें अदालत से बाहर ले जाने को कहेंगे। वकील ने अपने सहयोगियों की ओर रुख किया, जिसपर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा आप गैलरी में बात नहीं करेंगे। आप मेरी बात सुनेंगे।

थीं। सोमवार को पीठ को दिन भर चली बहस के दौरान भौतिकी के एक प्रश्न को लेकर असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा। ऐसी दलील दी गई कि परमाणु और उसकी विशेषताओं से संबंधित एक प्रश्न के दो सही उत्तर थे और परीक्षार्थियों के एक समूह, जिसने दो सही उत्तर में से एक विशेष उत्तर दिया था, उसे चार अंक दिए गए। कुछ वकीलों ने यह भी कहा कि अभ्यर्थियों के तीन समूह थे, और एक समूह को सही उत्तर के लिए माइनस पांच अंक मिले, दूसरे समूह को दूसरे सही उत्तर के लिए चार अंक मिले, और तीसरे समूह में वे लोग शामिल थे, जिन्होंने या तो जवाब पता न होने या नेगेटिव अंक मिलने के डर से इसे छोड़ दिया था। पीठ को बताया गया कि इसका सफल अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पर काफी असर पड़ेगा।

## सुझाए उत्तर के अनुसार नीट-यूजी मेधा सूची की जाए संशोधित

**नई दिल्ली।** उच्चतम न्यायालय ने एनटीए से कहा कि वह भौतिकी के एक विवादास्पद प्रश्न के लिए आईआईटी-दिल्ली के तीन विशेषज्ञों की समिति द्वारा सुझाये गये उत्तर को सही मानकर अपनी मेधा सूची में संशोधन करे। अब केवल उन छात्रों को प्रश्न के लिए चार अंक मिलेंगे, जिनके उत्तर आईआईटी-दिल्ली द्वारा दिए गए उत्तर से मेल खाते हैं जबकि चार लाख से अधिक ऐसे नीट अभ्यर्थी, जिन्होंने एनसीईआरटी की पुरानी पाठ्यपुस्तक के अनुसार अन्य विकल्प का उत्तर दिया था, उन्हें पांच अंक का नुकसान होगा, ऐसे में उनकी रैंक में फेरबदल होगा।

शीर्ष रैंक पाने वालों में से एक की ओर से पेश वकील तन्वी दुबे ने कहा कि छात्रा ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं और अगर केवल एक उत्तर को सही माना जाता है तो उसकी रैंक काफी नीचे चली जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों उत्तरों को सही माना जाना चाहिए। पीठ ने दलील खारिज कर दी।

# अस्पताल में भर्ती की आड़ में विलासिता की अनुमति नहीं दे सकते

मुंबई, एजेंसी

● मुंबई की एक विशेष अदालत ने धन शोधन के मामले में 80 वर्षीय व्यावसायी की याचिका खारिज की

मुंबई की एक विशेष अदालत ने धन शोधन के मामले में गिरफ्तार 80 वर्षीय व्यवसायी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल में भर्ती होने की आड़ में किसी आरोपी को विलासिता की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने सोमवार को एसोसिएट हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष मनोहरलाल अगीचा की अस्पताल में रहने की अवधि बढ़ाने की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

आरोपी व्यवसायी को ईडी ने नवंबर 2023 में एक बैंक से 149.89 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत के आदेश के अनुसार, न्यायिक हिरासत में रहते हुए अगीचा को मार्च 2024 में 15 दिनों के इलाज के लिए बांद्रा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से, आदेश को कई बार बढ़ाया गया और वह लगातार अस्पताल में भर्ती रहे।

हाल में, अगीचा ने आगे के इलाज के लिए अस्पताल में अपने रहने की अवधि को कुछ और महीनों के लिए बढ़ाने की याचिका दायर की। हालांकि, विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश ए.सी. डागा ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और आर्थर रोड जेल अधिकारियों को आरोपी को मध्य मुंबई की जेल में वापस ले जाने का निर्देश दिया।

# मालेगांव विस्फोट : निर्णायक चरण में सुनवाई

**मुंबई।** मालेगांव में बम विस्फोट के करीब 16 साल बाद इस मामले की सुनवाई निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) मामलों की विशेष अदालत अंतिम दलीलों की सुनवाई बुधवार से करेगी।

वर्ष 2008 में हुए इस बम धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि

● एनआईए अदालत 24 जुलाई से सुनेगी अंतिम दलील

100 से अधिक लोग घायल हुए थे। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज इस मामले के सात आरोपियों में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर शामिल हैं। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने उनमें से एक समीर कुलकर्णी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अदालत ने मंगलवार को बचाव पक्ष के अंतिम गवाह के परीक्षण के साथ साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग पूरी कर ली। न्यायाधीश ए के लाहोटी अब फैसला सुनाने से पहले अभियोजन और बचाव पक्ष की आखिरी बार दलील सुनेंगे।

# मुस्लिमों के बिना अमरनाथ यात्रा संभव नहीं : उमर

श्रीनगर, एजेंसी

● कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का किया स्वागत

नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान भोजनालयों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक लगाने का मंगलवार को स्वागत किया और कहा कि मुस्लिमों के सहयोग के बिना अमरनाथ यात्रा तक संभव नहीं है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों पर उनके मालिकों का नाम प्रदर्शित करने संबंधी आदेश देना नहीं चाहिए था। वार्षिक अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्राओं का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि ये मुसलमानों के सहयोग के बिना संभव नहीं हैं। अमरनाथ यात्री मुसलमानों के कंधों पर यात्रा करते हैं। जो लोग माता वैष्णो देवी यात्रियों को घोड़ों या पिट्ठुओं पर ले जाते हैं, वे किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं? उन्हें (भाजपा को) वहां धर्म नहीं दिखता। आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के केंद्र के फैसले के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा कि अगर उन्हें ऐसा करना है तो सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में शिरकत से भी प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए(

## दुष्कर्म पीड़िता की प्रसव के दौरान मौत, मामला दर्ज

**ठाणे।** यहां के वाशी पुलिस थाने में 18 वर्षीय लड़की की प्रसव के दौरान मौत के बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चूंकि कथित अपराध दिघी में हुआ था इसलिए इस संबंध में शून्य प्राथमिकी दर्ज कर उसे रायगढ़ जिले के दिघी पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया है। श्रीवर्धन निवासी आरोपी हेमंत और पीड़िता की मुलाकात पिछले साल कंप्यूटर की कक्षा के दौरान हुई थी जिसके बाद दोनों दोस्त बन गए। लड़की के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उसने कथित तौर पर दो मौकों पर उसके साथ दुष्कर्म किया जिसके बाद लड़की गर्भवती हो गई।

कर्नाटक के कारवार तट के पास मर्चेंट नेवी के एक जहाज में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बल ने बताया कि तट पर संभावित खतरे के मद्देनजर सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रभावित जहाज गहरे समुद्र में ही रहे। तटरक्षक बल के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि जहाज एमवी मेर्सक फ्रैंकफर्ट में 1,154 कंटेनर लदे हैं जिनमें से कुछ में बेंजीन और सोडियम साइनेट जैसे खतरनाक रसायन हैं।

## राष्ट्रगान गाने को मजबूर किए गए युवक की मौत की जांच सीबीआई को

**नई दिल्ली।** दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 23 वर्षीय एक युवक की मौत से संबंधित मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया, जिसे 2020 में शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुए दंगों के दौरान कथित तौर पर पीटा गया और राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ था।

सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में पुलिस कर्मियों द्वारा फैजान को चार अन्य मुस्लिम पुरुषों के साथ कथित तौर पर राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करते हुए एवं पीटते हुए देखा जा सकता है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने फैजान की मां द्वारा (एसआईटी से जांच कराने के लिए दायर याचिका पर कहा मैं याचिका को स्वीकार कर रहा हूं। मैं मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर रहा हूं। किस्मतुन ने 2020 में दाखिल याचिका में आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके बेटे के साथ मारपीट की और उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा एवं उसे अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किया। इसकी वजह से रिहाई के बाद उसी साल 26 फरवरी को उसकी मौत हो गई।

## इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति वाली याचिका पर रोक

**मुंबई।** बंबई उच्च न्यायालय ने शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को यूरोप की यात्रा पर जाने की अनुमति देने वाले विशेष अदालत के आदेश पर मंगलवार को अंतरिम रोक लगा दी। इंद्राणी मुखर्जी पर 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है और वह फिलहाल जमानत पर है। न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल की एकल पीठ ने कहा कि विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर न्यायमूर्ति एस सी चांडक की नियमित पीठ के समक्ष 29 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति चांडक मंगलवार को उपलब्ध नहीं थे। सीबीआई ने न्यायमूर्ति कोतवाल की वैकल्पिक पीठ के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा कि बेहतर होगा कि याचिका पर नियमित पीठ सुनवाई करे। उन्होंने कहा कि तब तक विशेष अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है।

● शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी हैं इंद्राणी मुखर्जी, यूरोप जाने की मांगी थी अनुमति

**सुनवाई** | आपत्तिजनक पोस्ट पर एक्स, गूगल व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी

# लोस अध्यक्ष की बेटी के खिलाफ पोस्ट हटाने के निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी

● आईआरपीएस अधिकारी की बेटी की भी तस्वीर हटाने के आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक्स कॉर्प और गूगल इंक को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अंतरिम आदेश में अज्ञात पक्षों को अंजलि बिरला द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उल्लेखित कथित मानहानिकारक सामग्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोस्ट करने, प्रसारित करने, संचारित करने, ट्वीट करने या रीट्वीट करने से भी रोक दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट को मध्यस्थों द्वारा 24 घंटे के भीतर हटाया जाएगा और यदि वादी को समान तरह की किसी अन्य

पोस्ट के बारे में पता चलता है, तो वह इसके बारे में एक्स और गूगल को सूचित करेंगी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक्स, गूगल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी किया तथा चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा। अधिकारी ने सोशल मीडिया पर उन पोस्ट को हटाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के कारण पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास कर ली और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी बन गईं।

अंजलि के वकील ने बताया कि वह यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) में शामिल हुई थीं और उनका चयन 2019 की समेकित आरक्षित सूची में हुआ था। वह आईआरपीएस अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हुईं। सुनवाई के दौरान अंजलि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कहा तीन साल बाद, यह सोशल मीडिया अभियान फिर से शुरू हो गया है जो न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी बदनाम करता है, जिसमें उनके पिता भी शामिल हैं जो एक राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ संवैधानिक पद पर आसीन हैं।

### मॉडल का हवाला दे पोस्ट की जा रहीं थीं निजी तस्वीरें

अधिवक्ता ने कहा कि उनकी मुवक्किल 2021 में एक अधिकारी बनी, लेकिन अब नीट और यूपीएससी परीक्षा विवाद के कारण अचानक ये चीजें फिर से सामने आ गई हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट से ऐसा महसूस होता है जैसे हम सब इसका हिस्सा हैं। अधिवक्ता ने कहा कि अंजलि (वादी) की निजी तस्वीरें यह कहते हुए ऑनलाइन पोस्ट की जा रही हैं कि वह एक मॉडल हैं। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि साइबर अपराध विभाग में भी इसकी शिकायत की गई है। अंजलि ने एक्स कॉर्प, गूगल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अज्ञात व्यक्तियों को मुकदमे में पक्षकार बनाया है।

# मातृत्व अवकाश दो बच्चों तक सीमित रखने के नियम पर किया जाए पुनर्विचार

नई दिल्ली, एजेंसी

● दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- तीसरे व उसके बाद के बच्चों का क्या दोष है, जो मातृ देखभाल से वंचित रहें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीएस (अवकाश) नियम पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत महिला सरकारी कर्मचारियों को पहले दो बच्चों के जन्म के समय मातृत्व अवकाश दिया जाता है। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से पूछा कि तीसरे और उसके बाद के बच्चों का क्या दोष है, जिन्हें उस मातृ देखभाल से वंचित होना पड़ता है, जो पहले दो बच्चों को मिली थी।

केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43 के अनुसार, कोई महिला सरकारी कर्मचारी शुरुआती दो बच्चों के जन्म के समय दोनों बार 180 दिन की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार है। अदालत ने कहा तीसरे बच्चे को जन्म के तुरंत बाद और शिशु अवस्था के दौरान मातृ स्पर्श से वंचित रखा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि नियम 43 के अनुसार उस बच्चे की मां से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जन्म के अगले ही दिन ड्यूटी पर लौट आए। अदालत ने कहा यह याद रखना महत्वपूर्ण होगा कि किसी गर्भवती महिला के शारीरिक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तन एक समान रहते हैं, चाहे वह पहली दो गर्भावस्था के दौरान हों, या तीसरे या उसके बाद की गर्भावस्था के दौरान।

### खारिज कर दिया था आवेदन

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ ने कहा कि तीसरा बच्चा पूरी तरह असहाय है, इसलिए न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह हस्तक्षेप करे। पीठ केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें पुलिस को तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली महिला कांस्टेबल को मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया गया था। महिला के पुलिस में भर्ती होने से पहले दो बच्चे थे। उसकी पहली शादी टूट गई और दोनों बच्चे अपने पिता के पास रहने लगे। दूसरी शादी से उसे तीसरा बच्चा हुआ, लेकिन मातृत्व अवकाश के लिए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया।

# केंद्रीय बजट में खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ आवंटित

नई दिल्ली, एजेंसी

जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख परियोजना खेलो इंडिया को एक बार फिर खेल मंत्रालय के लिए केंद्रीय बजट में सबसे अधिक राशि आवंटित हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट में खेल मंत्रालय के लिए 3,442.32 करोड़ रुपये में से खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह रकम पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 880 करोड़ रुपये के संशोधित आवंटन से 20 करोड़ रुपये अधिक है।

इस साल अगस्त में पेरिस ओलंपिक चक्र समाप्त होने वाला है और राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों अभी भी दो साल का समय है। ऐसे में खेल मंत्रालय के बजट में पिछले चक्र की तुलना में केवल 45.36 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि की गई है। खेल मंत्रालय के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के लिए पिछले चक्र का बजट 3,396.96 करोड़ रुपये था। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया में भारी निवेश किया है क्योंकि यह कार्यक्रम देश के सभी हिस्सों से प्रतिभाओं को सामने लाने का काम करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में खेलो इंडिया का वास्तविक आवंटन 596.39 करोड़ रुपये था। अगले साल (2023-24) के बजट में लगभग 400 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इसे हालांकि संशोधित कर 880 करोड़ रुपये किया गया था।

**596.39**

**करोड़ रुपये खेलो इंडिया के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में हुआ था आवंटित**

खेलो इंडिया युवा खेलों 2018 (केआईवाईजी) की शुरुआत के बाद से सरकार ने इसमें और खेल आयोजनों को जोड़ना जारी रखा है। मंत्रालय ने उसी वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेल और 2023 में खेलो इंडिया पैरा खेलों शुरू करने के साथ 2020 में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की शुरुआत की। देश भर में सैकड़ों खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रतिभाशाली उदीयमान खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करना है। खेलो इंडिया के कई एथलीट वर्तमान में भारतीय ओलंपिक दल में शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को सरकार की सहायता में भी 15 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। यह 2023-24 में 325 करोड़ रुपये से बढ़कर नवीनतम बजट में 340 करोड़ रुपये हो गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) का बजट भी 795.77 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 822.60 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें 26.83 करोड़ रुपये का उछाल है। साइ देश भर में अपने स्टेडियमों के रख रखाव अलावा वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) का प्रबंधन भी करता है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को बजट में मामूली वृद्धि मिली है। नाडा और एनडीटीएल का काम खिलाड़ियों की डोपिंग जांच करना है। नाडा के बजट को 21.73 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22.30 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि एनडीटीएल के बजट को 19.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

## महिला एशिया कप

दांबुला, एजेंसी

शेफाली वर्मा (81) और दयालन हेमलता (47) रनों की तूफानी पारियों और उसके बाद दीप्ति शर्मा के 13 रन पर तीन विकेट की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने मंगलवार को महिला एशिया कप के 10वें मुकाबले में नेपाल को 82 रनों से हराकर शान के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

179 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने दूसरे ही ओवर में सलामी बल्लेबाज एस खड़का का विकेट गवां दिया। उसके बाद कविता कुंवर (6) रन बनाकर पवेलियन लौट गई। सीता राणा मगार ने टीम के लिए सर्वाधिक (18) रन बनाये। भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के आगे नेपाल की कोई भी बल्लेबाज अधिक देर तक पिच नहीं टिक सकी। भारतीय गेंदबाजो ने नेपाल को शुरुआत में ही बैकफुट पर कर दिया। नेपाल की टीम निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट पर 96 रन ही बना सकी और 82 रन से मुकाबला हार गई। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम महिला एशियाकप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है।

इससे पहले भारतीय टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 178 रन बनाए। बल्लेबाजी करने उतरी शेफाली वर्मा और दयालन हेमलता की सलामी जोड़ी ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए पहले विकेट लिए 122 रनों की साझेदारी की। 16वें ओवर में मगार ने श्रेष्ठ के हाथों शेफाली वर्मा को स्टंप आउट करा दिया।

### पाकिस्तान ने यूएई को 10 विकेट से हराया

दाम्बुला। बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज गुल फिरोजा के नाबाद अर्धशतक से पाकिस्तान ने महिला एशिया कप टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए में यूएई को 10 विकेट से रौंदकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। यूएई के 104 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुल की 55 गेंद में आठ चौकों से नाबाद 62 रन की पारी और मुनीबा अली (नाबाद 37) के साथ उनकी पहले विकेट की अटूट शतकीय साझेदारी से पाकिस्तान ने 14.1 ओवर में बिना विकेट खोए 107 रन बनाकर बेहद आसान जीत दर्ज की। इस जीत से पाकिस्तान के तीन मैच में दो जीत से चार अंक हो गए हैं और टीम का सेमीफाइनल में जगह बनाने का दावा मजबूत हो गया है।

## खेल डायरी

### हरमनप्रीत, शेफाली 11वें स्थान पर, मंधाना पांचवें पर

दुबई। भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना ने आईसीसी टी-20 महिला क्रिकेट रैंकिंग में पांचवां स्थान बनाए रखा है जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा संयुक्त 11वें स्थान पर हैं। हरमनप्रीत को एक पायदान का फायदा मिला जबकि शेफाली बल्लेबाजों की सूची में चार पायदान ऊपर आ गई। शीर्ष 20 में भारत के चार खिलाड़ी हैं। जेमिमा रौड्रिग्स 19वें स्थान पर हैं। रिचा घोष 24वें स्थान पर है। बेथ मूनी 769 अंक लेकर शीर्ष पर है। गेंदबाजों की सूची में ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा तीसरे स्थान पर है जबकि तेज गेंदबाज रेणुका सिंह नौवे स्थान पर हैं। बायें हाथ की स्पिनर राधा यादव 20वें स्थान पर हैं। इंग्लैंड की सोफी एस्सेलेटोन शीर्ष पर हैं।

### विश्व जूनियर टीम स्क्वाश में भारत के सामने इंग्लैंड

ह्यूस्टन। भारतीय लड़कों ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पांचवें से आठवें स्थान के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया जबकि लड़कियों की टीम इंग्लैंड से इसी अंतर से हार गई। लड़कों की टीम का सामना पांचवें स्थान के लिए इंग्लैंड से होगा जबकि लड़कियों की टीम सातवें स्थान के लिये हांगकांग से खेलेगी। लड़कों की टीम में शौर्य बावा ने कोनोर एर्ल को 12-10, 7-11, 11-6, 11-7 से हराया जबकि अयान वाजिराली ने जुडा फिलिप्स को 11-4, 11-4, 11-8 से हराया। लड़कियों की टीम में शमीना रियाज इंग्लैंड की एमेली हावर्थ से 8-11, 4-11, 10-12 से हार गई जबकि उन्नति त्रिपाठी को एमिली कूचेर पोर्टर ने 11-8, 14-12, 11-4 से हराया।

### वोंड्रोसोवा और हुरकाज ने वापस लिया नाम

पेरिस। तोक्यो ओलंपिक टेनिस रजत पदक विजेता मरकेटा वोंड्रोसोवा ने हाथ की चोट के कारण पेरिस ओलंपिक से नाम वापस ले लिया। पोलैंड के हुबर्ट हुरकाज ने भी घुटने की चोट से कारण नाम वापिस लेने का फैसला किया है। पिछले साल विंबलडन जीतने वाली चेक गणराज्य की वोंड्रोसोवा इस महीने विम्बलडन से पहले दौर में बाहर हो गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर ओलंपिक से हटने की जानकारी देते हुए कहा कि उनका फोकस अगस्त में होने वाले अमेरिकी ओपन पर है। ओलंपिक में टेनिस स्पर्धा के ड्रॉ बृहस्पतिवार को निकाले जायेंगे जबकि मैच शनिवार से शुरू होंगे।

### पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेंगे एंडी मर्रे

पेरिस। दो बार ओलंपिक पुरुष एकल चैंपियन एंडी मर्रे ने पुष्टि की कि पेरिस ओलंपिक के बाद वह खेल से संन्यास लेंगे। 37 वर्ष के मर्रे ने एक्स पर पोस्ट किया अपने आखिरी टेनिस टूर्नामेंट के लिए पेरिस पहुंच गया हूं। पेरिस ओलंपिक में टेनिस स्पर्धा रोलां गैरो पर शनिवार से शुरू होंगी। मर्रे ने पहला स्वर्ण पदक 2012 लंदन ओलंपिक में ग्रासकोर्ट पर जीता था जिसमें उन्होंने रोजर फेडरर को तीन सेटों में हराया था। इसके बाद 2016 में रियो दि जिनेरियो में हार्डकोर्ट पर जुआन मार्टिन देल पोत्रो को हराकर खिताब जीता था। मर्रे ने 2019 में कूल्हे की प्रत्यारोपण सर्जरी कराई थी।

# गंभीर के साथ श्रीलंका पहुंची भारतीय टीम

## तीन मैचों की शृंखला का पहला टी-20 मुकाबला 27 को होगा, वनडे शृंखला के लिए बाद में पहुंचेगे दिग्गज खिलाड़ी

पाल्लेकल, एजेंसी

नए मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम कोलंबो के रास्ते यहां पहुंच गई जिसका गर्मजोशी से स्वागत किया। पंद्रह सदस्यीय भारतीय टीम सहयोगी स्टाफ के साथ सोमवार को मुंबई से रवाना हुई।

इससे पहले गंभीर और चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने मीडिया को संबोधित किया था। कोलंबो में कुछ देर रूकने के बाद टीम सीधे पाल्लेकल पहुंच गई। भारत को श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 और वनडे शृंखला खेलनी है। पहला टी-20 मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा जबकि बाकी दो 28 और 30 जुलाई को होंगे। भारतीय टीम दो, चार और सात अगस्त को तीन वनडे खेलेगी। बीसीसीआई ने एक्स पर लिखा मुंबई से कोलंबो के रास्ते पाल्लेकल। टीम इंडिया श्रीलंका पहुंची।

### टी-20 विश्वकप जश्न पर द्रविड़ चीख और रो रहे थे : अश्विन

चेन्नई, एजेंसी

स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि बारबाडोस में भारत की खिताबी जीत के बाद विराट कोहली का पूर्व कोच द्रविड़ को टी-20 विश्व कप ट्रॉफी सौंपना और कोच का खुशी में चीखना और रोना कुछ ऐसा था जो हमेशा उनकी यादों में रहेगा।

पिछले महीने भारत ने दक्षिण अफ्रीका को करीबी फाइनल में हराकर अपना दूसरा टी-20 विश्व कप जीता था जिसके बाद पूर्व कोच द्रविड़ ट्रॉफी को हाथ में उठाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते नजर आए थे। अश्विन ने स्वीकार किया कि यह 51 साल के द्रविड़ के लिए विशेष लम्हा था जो खिलाड़ी के रूप में आईसीसी का खिताब नहीं जीत पाए लेकिन अंततः कोच के रूप में ऐसा करने में सफल रहे। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल कहा मेरे लिए सबसे शानदार लम्हा वह है जब विराट कोहली राहुल द्रविड़ को बुलाते हैं और उन्हें कप देते हैं। मैंने उन्हें कप को गले लगाते हुए और रोते हुए देखा।

### भारत के खिलाफ टी-20 में असलंका संभालेंगे श्रीलंका की कमान, 16 सदस्यीय टीम घोषित

कोलंबो। श्रीलंका क्रिकेट ने 27 जुलाई से भारत के साथ शुरू होने वाली तीन मैचों की टी-20 शृंखला के लिए चरिथ असलंका को टीम का नया कप्तान बनाया है। श्रीलंका क्रिकेट ने भारत के साथ होने वाली तीन टी-20 मैचों की शृंखला के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। वह हाल ही में कप्तानी से इस्तीफा देने वाले वानिंदु हसरंगा की जगह लेंगे। असलंका ने इस वर्ष की शुरुआत में बंगलादेश दौरे पर दो टी-20 मैचों में श्रीलंका टीम की कप्तानी की थी। उन्होंने श्रीलंका अंडर-19 की भी कप्तानी की है। 34 वर्षीय दिनेश चांदीमल की श्रीलंका की टी-20 टीम में वापसी हुई है। उन्होंने आखिरी बार 2022 की शुरुआत में टी-20 मैच खेला था। इस साल एलपीएल में 168.82 के स्ट्राइक रेट से आठ मैचों में 287 रन बनाए। जो कि उनके करियर के 123.03 के स्ट्राइक रेट से कहीं अधिक है। उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में वानिंदु हसरंगा के छह महीने के कार्यकाल के बाद कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम में चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल जेनिथ परेरा (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), दिनेश चांडीमल, कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, महीश थीक्षाना, चामिंडु विक्रमसिंघे, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा, दुष्मंथा चमीरा और बिनुरा फर्नांडो को शामिल किया गया है।

# यातायात महंगा, सीन की सुरक्षा पर सवाल

पेरिस, एजेंसी

पेरिस ओलंपिक के लिये यहां पहुंचे करीब 45,000 वालिंटियर का यहां आना सार्थक हो गया जब उन्हें हवाई अड्डे पर टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज से मिलने का मौका मिला। पेरिस में 100 साल बाद ओलंपिक हो रहे हैं और वालिंटियर्स के लिए यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला अनुभव है। पेरिस हवाई अड्डे पर एक उत्साही वालिंटियर ने कहा मैं 60 साल का हो चुका हूं और मेरे जीवन में तो पेरिस में फिर ओलंपिक नहीं होने वाला। इसका हिस्सा बनना मेरे लिए जीवन भर नहीं भूलने वाला अनुभव है। बीस मिनट पहले अल्काराज यहां पहुंचे और मैंने उन्हें एक्रिडिटेशन (पहचान पत्र) दिलाने में मदद की। यह अनुभव यादगार हो गया है।

**ओलंपिक 2 दिन शेष**

- 100 साल बाद पेरिस में ओलंपिक, गर्व पर दर्द का भी बना है सबब

### स्थानीय यातायात महंगा

पेरिस में रहने वाले सभी लोग ओलंपिक के आयोजन से खुश नहीं है क्योंकि इसका उनके दैनंदिनी जीवन पर असर पड़ रहा है। स्थानीय यातायात 2.15 यूरो से बढ़कर 4 यूरो तक पहुंच गया है और आठ सितंबर को पैरालंपिक के खत्म होने तक यही किराया रहेगा। ओलंपिक आयोजन स्थलों के आसपास आवागमन पर भी पाबंदियां हैं। शहर के सबसे व्यस्त ट्रेन स्टेशन पर खड़ी विक्टोरी डेलारू ने कहा पेरिसवासियों के लिए ओलंपिक की मेजबानी गर्व का विषय है लेकिन इससे लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए।

### आधे होटल हैं खाली

ओलंपिक के दौरान होटलों की भारी मांग दिखाई गई जिससे पेरिस के कई लोगों ने कमाई के लिए अपने घरों को किराये पर लगा दिया लेकिन होटलों की उतनी मांग है नहीं। पेरिस में यह पर्यटन का मौसम है लेकिन मांग फिर भी कम है। एक होटल के मैनेजर समीर ने कहा इस समय हमारे होटल में एक रात का किराया 120 यूरो रहता है लेकिन हम आधे दाम पर लगा रहे हैं। ओलंपिक की मेजबानी हमारे लिए अच्छी नहीं रही। काफी पाबंदियां हैं और कई जगहों पर जाने के लिए क्यूआर कोड चाहिए।

### क्या वाकई साफ है सीन नदी

ओलंपिक के लिए स्थानीय प्रशासन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीन नदी की सफाई था जहां उद्घाटन समारोह, ट्रायथलन और मैराथन तैराकी होनी है। इतिहास में पहली बार पानी पर उद्घाटन समारोह हो रहा है जिसमें सुरक्षा उपायों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सीन नदी में तैराकी पर 100 साल पहले प्रतिबंध लग गया था लेकिन इसकी सफाई पर डेढ़ अरब यूरो खर्च किए गए। पिछले सप्ताह बारंबार देरी के बाद आखिरकार डुबकी लगाकर इसे तैराकी के लिये सुरक्षित करार दिया।

### असम के मुख्यमंत्री ने अभिनव को ओलंपिक आर्डर मिलने पर दी बधाई

गुवाहाटी, एजेंसी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में उनके असाधारण योगदान के लिये ओलंपिक आर्डर मिलने पर बधाई दी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा उम्मीद है कि वह आने वाली पीढियों को खेलों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने बिंद्रा को बताया कि उन्हें ओलंपिक आर्डर दिया गया है और पुरस्कार समारोह 10 अगस्त को पेरिस में आईओसी के 142वें सत्र के दौरान होगा। असम सरकार ने गुवाहाटी और जोरहट में दो हाई परफार्मेंस खेल ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए असम सरकार के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के 250 सरकारी और गुवाहाटी के निजी स्कूलों में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम (ओवीईपी) लागू करने के लिए भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद बदलती जीवन शैली, एकाग्रता के अभाव और स्कूल से बच्चों का नाम वापिस लेने जैसी समस्याओं से निपटना है।

# विश्वास, टीम भावना सफलता की कुंजी : क्रेग

नई दिल्ली, एजेंसी

पिछले साल भारतीय पुरुष हॉकी टीम से जुड़े कोच क्रेग फुल्टोन का लक्ष्य आपसी विश्वास मजबूत करना था और उन्हें यकीन है कि उनके प्रयासों का नतीजा पेरिस ओलंपिक में पदक के बेहतर रंग के रूप में मिलेगा।

14 माह पहले पदभार संभालने वाले फुल्टोन ने कहा मुझे नहीं पता कि तोक्यो ओलंपिक से पहले क्या तैयारियां थी लेकिन 14 महीने पहले मेरे आने के बाद से फोकस खिलाड़ियों में आपसी विश्वास बेहतर करने पर रहा है। उन्होंने बेहतर नतीजों के लिये दक्षिण अफ्रीका के मानसिक अनुकूलन कोच पैडी उपटन की सेवाएं ली जो 2011 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के साथ काम कर चुके हैं। उपटन टीम के साथ पेरिस में हैं। मानसिक दृढता के लिये उन्होंने इस महीने की शुरूआत में स्विटजरलैंड के माइक होर्न्स बेस में तीन दिन का शिविर लगाया। फुल्टोन ने कहा मैने अल्पकालिन और दीर्घकालिन रणनीति बनाई और उसके हिसाब से काम किया।

- भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुल्टोन बोले- आपसी तालमेल को बेहतर करने पर रहा पूरा ध्यान केंद्रित

उन्होंने कहा हमारी तैयारियां अच्छी रही और स्विट्जरलैंड में तीन दिन का शिविर बहुत अच्छा साबित हुआ। हमने आपसी विश्वास, टीम भावना और एकजुटता बढाने पर काम किया । इसके बाद नीदरलैंड में नौ दिन अभ्यास किया और कुछ अभ्यास मैच भी खेले। तोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक विजेता से अपेक्षाओं के बारे में उन्होंने कहा मुझे अपेक्षाओं का पता है और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। भारत का हॉकी का गौरवमयी इतिहास रहा है और हम उस विरासत को आगे बढाना चाहते हैं। मैं पोडियम पर रहने के बारे में कयास नहीं लगा सकता क्योंकि ओलंपिक में 12 टीमों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। पहले तीन मैच अहम है जिन पर फोकस रहेगा।

### ओलंपिक से इतर हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय शिविर में बुलाया

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया ने सितंबर में चीन में होने वाली एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बेंगलुरू में सीनियर पुरुष टीम के राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में उन खिलाड़ियों को बुलाया है जो पेरिस ओलंपिक की टीम का हिस्सा नहीं हैं। इसमें विकास ग्रुप और जूनियर पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी भी शामिल हैं। ओलंपिक टीम में शामिल खिलाड़ी छोटे ब्रेक के बाद 24 अगस्त से राष्ट्रीय शिविर में भाग लेंगे जो चार सितंबर तक चलेगा। मुख्य कोच क्रेग फुल्टोन ने कहा सीनियर टीम पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शुरूआत की तैयारी में जुटी है लेकिन हमारे पास उससे इतर भी खिलाड़ियों का मजबूत पूल है जो भारत के लिये फिर खेलने के मौके के इंतजार में हैं। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी ओलंपिक के कुछ सप्ताह बाद ही है लिहाजा इसके लिये बेंगलुरू के साइ केंद्र में शिविर लगाया जा रहा है । ये खिलाड़ी उसके लिये तैयारी करेंगे और ओलंपिक टीम 24 अगस्त को उनसे जुड़ेगी।

## बॉलीवुड हलचल

### फिल्म खेल-खेल में का मोशन पोस्टर रिलीज

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म खेल खेल में का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है।कॉमेडी-ड्रामा खेल खेल में अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, वाणी कपूर, अम्मी विर्क, आदित्य सील, प्रज्ञा जैसवाल और फरदीन खान की अहम भूमिका हैं। फिल्म ''खेल खेल में'' का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। टी-सीरीज फिल्म, वाकाऊ फिल्म्स और केकेएम फिल्म प्रोडक्शन की फिल्म खेल खेल में का निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया हैं। यह फिल्म भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डी शाह, अश्विन वर्दे, राजेश बहल, शशिकांत सिन्हा और अजय राय द्वारा निर्मित है। फिल्म खेल खेल में 15 अगस्त 2024 को रिलीज होगी।

### जियो सिनेमा पर 9 से स्ट्रीम होगी घुड़चढ़ी

मुंबई। बॉलीवुड के माचो हीरो संजय दत्त और अभिनेत्री रवीना टंडन की आने वाली फिल्म ''घुड़चढ़ी'' ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर 9 अगस्त से स्ट्रीम होगी। निधि दत्त और बिनॉय के गांधी निर्मित ''घुड़चढ़ी'' का पहला पोस्टर जारी हो गया है। साथ ही रिलीज डेट का भी एलान कर दिया गया है। ''घुड़चढ़ी'' एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें संजय दत्त, रवीना टंडन, पार्थ समथान और खुशाली कुमार की अहम भूमिका है। ''घुड़चढ़ी'' सिनेमाघरों की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर 09 अगस्त से स्ट्रीम होगी। संजय दत्त ने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म घुड़चढ़ी का पोस्टर शेयर किया है।पोस्टर में रवीना-संजय और पार्थ-खुशाली रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। इसके साथ कैप्शन में लिखा गया है, प्यार डबल और कन्फ्यूजन डबल।


स्वामी-रुहेलखंड इंटरप्राइजेज के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक त्रिनाथ शुक्ला द्वारा 25/16-ए, जाप्लिंग रोड, लखनऊ-226001 (उ.प्र.) से प्रकाशित एवं प्लाट नं.-42, निकट बद्री नगर,इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज, लखनऊ-226008 (उ.प्र.) से मुद्रित।
**संपादक-शंभू दयाल वाजपेयी**, 0522-4008111 (कार्यालय), **ईमेल**-amritvicharlucknow@gmail.com **आर.एन.आई नं0**-50986/1989 **(नोट-सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा)।**

## एक नजर

### नेपाल में भारतीयों को टक्कर मारकर घायल वाला चालक गिरफ्तार

**काठमांडू।** नेपाल में एक कार चालक को नशे में वाहन चलाने और उससे (कार से) टक्कर मारकर तीन भारतीय राहगीरों को घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात कालीमाटी-कुलेश्वर सड़क खंड पर हुई। उन्होंने बताया कि गलत लेन से आ रही कार ने फुटपाथ पर चल रहे तीन भारतीयों को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि मेडिकल जांच में पता चला कि कार चालक भूपेंद्र श्रेष्ठ (40) ने मादक पदार्थ का सेवन कर रखा था। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायलों की पहचान प्रियांशु कुमार (18), भोला कुमार (25) और श्याम बाबू ठाकुर (18) के रूप में हुई है।

### अमेरिका में विमान दुर्घटनाग्रस्त, दो की मौत

**सैन फ्रांसिस्को।** अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रांत में सोमवार को एक एयर शो स्थल के पास खेत में विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई। विन्नेबागो काउंटी शेरिफ कार्यालय ने कहा कि कल दोपहर पूर्वी विस्कॉन्सिन शहर नेकिमी में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मृतकों के रिश्तेदारों को सूचना दे दी गई है। मृतकों के नाम का अभी खुलासा नहीं किया गया है। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड विमान दुर्घटना की जांच में जुट गया है।

### म्यांमार के प्रधानमंत्री बने कार्यवाहक राष्ट्रपति

**नाएप्यीडॉ।** म्यांमार के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय प्रशासन परिषद के अध्यक्ष मिन आंग ह्लाइंग को राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद की गतिविधियों से संबंधित मामलों को हल करने के लिए अस्थायी रूप से कार्यवाहक राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं। एमडब्ल्यूडी न्यूज ब्रॉडकास्टर ने यह जानकारी दी। सैन्य सरकार ने कहा, "कार्यवाहक राष्ट्रपति के कर्तव्य राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष को सौंप दिए गए हैं।" रिपोर्ट के मुताबिक, म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति माइंट स्वे बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है।

### अमेरिका की अधीनस्थ अदालत पर साइबर हमला

**लॉस एंजिलिस।** अमेरिका की सबसे बड़ी अधीनस्थ अदालत 'सुपीरियर कोर्ट ऑफ लॉस एंजिलिस काउंटी' पिछले सप्ताह रैनसमवेयर हमले के कारण कम्प्यूटर प्रणाली में खराबी आ जाने के कारण सोमवार को बंद रही। शुक्रवार की सुबह साइबर हमले का पता चलने पर अदालत की कंप्यूटर प्रणाली को बंद कर दिया गया था, जो सप्ताहांत तक बंद रही। अदालतें शुक्रवार को काम-काज के लिए खुली रहीं, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि काउंटी की सभी 36 अदालतें सोमवार को बंद रहेंगी।

### मशहूर कन्नड़ निर्देशक ने धोंडले ने की आत्महत्या

**बेंगलुरु।** जाने-माने कन्नड़ टीवी सीरीज निर्देशक विनोद वी धोंडले ने अपनी पहली फिल्म के बढ़ते बजट और फिल्म के वास्ते लिए गए तीन करोड़ रुपये के व्यक्तिगत ऋण से कथित रूप से परेशान होकर 20 जुलाई को आत्महत्या कर ली। उनके साझेदार और फिल्म के निर्माता 'वृद्धि क्रिएशन' के वर्धन हरि ने कहा कि उन्हें वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि फिल्म की शूटिंग की अवधि निर्धारित दिनों से लगभग दोगुनी हो गई। हरि ने कहा, "हमारा मूल बजट करीब 1.5 करोड़ रुपये था, लेकिन हम कई गुना ज्यादा खर्च कर बैठे। अब हमें कुछ दृश्यों के साथ-साथ एक गाना और एक लड़ाई का दृश्य भी दोबारा शूट करना था। इन सबके लिए और अधिक पैसे की जरूरत थी।"

# अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की मुखिया चीटल का इस्तीफा

वाशिंगटन, एजेंसी

- डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को बताया था सबसे गंभीर चूक

अमेरिकी खुफिया सेवा की निदेशक किंबरले चीटल ने एक रैली में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास की घटना को लेकर मंगलवार को पद से इस्तीफा दे दिया। चीटल ने विभाग के सहयोगियों को किए गए ई-मेल में यह जानकारी दी। चीटल ने अपने ई-मेल में कहा, 'मैं सुरक्षा चूक की पूरी जिम्मेदारी लेती हूं। हाल की घटनाओं के मद्देनजर, भारी मन से मैंने निदेशक पद से इस्तीफा देने का कठिन निर्णय लिया है।'

ट्रंप पर हमले की घटना के बाद से ही खुफिया सेवा पर गंभीर चूक करने के आरोप लग रहे थे। इसे लेकर अगस्त, 2022 से ही निदेशक पद संभाल रहीं चीटल पर इस्तीफा देने का चौतरफा दबाव था। एक दिन पहले ही चीटल ने सांसदों के समक्ष स्वीकार किया था कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या का प्रयास, 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को गोली मारे जाने की घटना के बाद से 'सबसे गंभीर' सुरक्षा चूक है। चीटल ने ट्रंप की हत्या के प्रयास को लेकर सदन की निगरानी व जवाबदेही समिति के समक्ष अपनी पेशी के दौरान यह बात स्वीकार की।

# बजट में पड़ोसियों पर भी दिखाई मेहरबानी

नई दिल्ली, एजेंसी

- मालदीव को मदद बरकरार, भूटान के लिए सबसे ज्यादा आवंटन

भारत ने 'पड़ोसी पहले की नीति' के तहत बजट 2024-25 में भूटान को मदद का सबसे बड़ा हिस्सा दिया है। इस वित्तीय वर्ष में उसे 2,068 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में भूटान में विभिन्न योजनाओं के लिए 2400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। वहीं, बांग्लादेश को मौजूदा आम बजट में 120 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपये था।

वहीं, मॉरीशस के लिए मदद भी 2024-25 के केंद्रीय बजट में वित्तीय मदद कम की गई है। उसके लिए 370 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। पिछले वित्त वर्ष में यह राशि 400 करोड़ रुपये थी। म्यांमार के लिए भी इस साल का बजट 400 करोड़ रुपये से घटकर 250 करोड़ रुपये हो गया।

इस बीच, मालदीव के लिए आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस साल भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए मालदीव को 400 करोड़ रुपये आवंटित किए।

मालदीव और भारत के बीच राजनयिक संबंध इस साल जनवरी की शुरुआत में तनावपूर्ण हो गए थे। दोनों देशों के बीच विवाद उस समय पैदा हुआ, जब मालदीव के कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की। हालांकि, बाद में इन सांसदों को निलंबित भी किया गया। मोहम्मद मुइज्जी के मालदीव के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद विवाद शुरू हुआ। चीन के समर्थन माने जाने वाले मुइज्जी ने मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया था। इस कदम ने भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों को और प्रभावित किया था। इसके अलावा, ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए भी 100 करोड़ रुपये का आवंटन बरकरार रखा गया है।

### नेपाल-श्रीलंका के लिए भी बजट आवंटन में वृद्धि

नेपाल और श्रीलंका के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नेपाल को सहायता के रूप में 700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो कि पिछले साल 550 करोड़ रुपये था। श्रीलंका के लिए इस साल 245 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि पिछले साल यह राशि 150 करोड़ रुपये थी।

## ब्रिटिश निवेशकों ने भारत के बजट को बताया उत्साहजनक

**लंदन।** निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को ब्रिटेन के कारोबारी समुदाय ने उत्साहजनक करार दिया है। उन्होंने विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर 40 से घटाकर 35 प्रतिशत करने और 'एंजल' कर के संबंध में लिए गए निर्णय को सकारात्मक बताया। 'एंजल' कर का मतलब वह आयकर है, जो सरकार गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाती है, यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है। यूके-इंडिया बिजनेस काउंसिल के सीईओ रिचर्ड मैक्कलम ने कहा, 'कॉर्पोरेट कर में कटौती ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत में निवेश करने के संबंध में एक स्वागत योग्य कदम है।'

# कनाडा में एक और मंदिर में तोड़फोड़

## खालिस्तान समर्थकों ने स्वामीनारायण मंदिर की दीवार पर लिखे आपत्तिजनक नारे

ओटावा, एजेंसी

एडमॉन्टन में हिंदू मंदिर पर हमले में खालिस्तान समर्थकों का हाथ बताया जा रहा है।

कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। अलबर्टा प्रांत की राजधानी एडमॉन्टन में एक हिंदू मंदिर में मंगलवार को तोड़फोड़ की गई और उन पर घृणित भित्तिचित्र बनाए गए। इसके पीछे खालिस्तान समर्थकों का हाथ बताया जा रहा है।

कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर को विरूपित किए जाने पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा, "पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा के अन्य स्थानों में हिंदू मंदिरों को घृणित भित्तिचित्रों के साथ नष्ट किया जा रहा है।"

ऐसी घटनाओं को भड़काने वाले चरमपंथी तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहुसांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी वकालत के लिए जाने जाने वाले लिबरल सांसद का कहना है कि सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नून ने पिछले साल सार्वजनिक रूप से हिंदुओं को भारत वापस जाने के लिए कहा था। खालिस्तान समर्थकों ने ब्रैम्पटन और वैंकूवर में घातक हथियारों की तस्वीरें लहरा कर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का सार्वजनिक रूप से जश्न मनाया था।

आर्य ने जोर देकर कहा, "जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं, खालिस्तानी चरमपंथी नफरत और हिंसा की अपनी सार्वजनिक बयानबाजी से आसानी से बच जाते हैं।" उन्होंने मंदिर की क्षतिग्रस्त दीवार की एक तस्वीर के साथ आग्रह करते हुए अपनी पोस्ट समाप्त की, "एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह मैं फिर से कनाडाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का आह्वान करता हूं, इससे पहले कि ये बयानबाजी हिंदू-कनाडाई लोगों के खिलाफ भौतिक कार्रवाई में तब्दील हो जाए।"

तोड़ी गई मंदिर की दीवार पर लिखा है, "प्रधानमंत्री मोदी सांसद आर्य हिंदू आतंकवादी हैं।" पिछले साल नवंबर में एक वकालत संस्था 'कनाडा-इंडिया फाउंडेशन' ने देश के राजनेताओं से अपनी चुप्पी तोड़ने और बहुत देर होने से पहले कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए कहा था।

कनाडाई राजनेताओं और मीडिया ने हालांकि इस खतरे को नजरअंदाज कर दिया। स्थिति के जवाब में उन्होंने एक खुले पत्र में कहा था, "हमें इस बात से और भी निराशा हुई है कि हमारे नेताओं ने इस गंभीर मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। आतंकवाद और खतरों से निपटने के लिए यह चयनात्मक दृष्टिकोण इस दुनिया को सुरक्षित जगह नहीं बनाएगा।"

हाल के दिनों में तोड़े गए हिंदू मंदिरों में मिसिसॉगा में राम मंदिर, रिचमंड हिल में विष्णु मंदिर, टोरंटो में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर, सरे में लक्ष्मी नारायण मंदिर शामिल हैं। इन हमलों को धर्म की स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा जाता है और एक खतरनाक प्रवृत्ति माना जाता है। वकालत संस्था ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि चरमपंथियों ने आम हिंदुओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और उन्हें कनाडा छोड़ने के लिए कहा है।

### हिंदू कनाडाई सच में परेशान हैं: सांसद आर्य

सांसद चंद्र आर्य ने अपनी पोस्ट में खालिस्तानी चरमपंथियों को मिली छूट की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, 'जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं, खालिस्तानी चरमपंथी नफरत और हिंसा की अपनी सार्वजनिक बयानबाजी से आसानी से बच निकलते हैं। मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, हिंदू कनाडाई सच में परेशान हैं। मैं फिर से कनाडा की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का आह्वान करता हूं। इससे पहले कि ये बयानबाजी हिंदू कनाडाई लोगों के खिलाफ हमलों में तब्दील हो जाए।'

## इमरान खान होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, जेल पहुंची फॉरेंसिक टीम

**लाहौर।** पिछले साल 9 मई को पाकिस्तान में हुई अभूतपूर्व हिंसा के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पॉलीग्राफ जांच करने के लिए 12 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम मंगलवार को अडियाला जेल पहुंची। इमरान को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा 19 करोड़ पाउंड के कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद पिछले साल 9 मई को देशभर में व्यापक हिंसा भड़क गई थी। 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की खबर के अनुसार, पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में लाहौर पुलिस की टीम यह जांच कराने के लिए जेल परिसर में पहुंची।

# ऋषि सुनक 2 नवंबर तक नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे

लंदन, एजेंसी

- नवंबर तक सुनक के उत्तराधिकारी का किया जाएगा चुनाव

ब्रिटेन की संसद में पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 2 नवंबर तक अंतरिम नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी की समय सारिणी के अनुसार नवंबर तक उनके उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाएगा और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। टोरी (कंजर्वेटिव पार्टी) का नेतृत्व कौन करेगा, यह तय करने के लिए संसद के बैकबेंच सदस्यों की 1922 समिति ने सोमवार शाम को दो चरण की चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी, जिसके तहत दो नवंबर को नए नेता की नियुक्ति की जाएगी।

भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक (44) ने आम चुनाव में पार्टी की सबसे बुरी हार के बाद 5 जुलाई को अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता, तब तक वह टोरी के अंतरिम नेता की जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहेंगे। सुनक ने कहा, 'पार्टी का नेतृत्व हासिल करने के उम्मीदवारों या इससे जुड़े अभियान के बारे में कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा।'

# कमला हैरिस का डेमोक्रेट उम्मीदवार बनना तय

वाशिंगटन, एजेंसी

- पार्टी का नामांकन हासिल करने के लिए मिला पर्याप्त समर्थन

कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार बनने के लिए पर्याप्त 'डेलीगेट' (प्रतिनिधि) का समर्थन हासिल कर लिया है। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति को संभावित प्रतिद्वंद्वियों, सांसदों, गवर्नर और प्रभावशाली समूहों से समर्थन मिला था। सीएनएन की खबर के मुताबिक, भारतीय-अफ्रीकी मूल की हैरिस को 1976 'डेलीगेट' का समर्थन मिल गया है, जो राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी संख्या से ज्यादा है।

हैरिस ने कहा, "जब मैंने राष्ट्रपति पद के लिए अपने अभियान की घोषणा की थी, तो मैंने कहा था कि मैं यह नामांकन हासिल करना चाहती हूं। आज रात मुझे इस बात पर गर्व है कि मुझे हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक समर्थन मिल गया है।" हैरिस (59) ने कहा, "मैं जल्द ही औपचारिक रूप से नामांकन स्वीकार करने की आशा करती हूं।" बाइडन ने रविवार को घोषणा की थी कि वह राष्ट्रपति पद का आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे।

# फिलिस्तीन के दो विरोधी गुटों हमास और फतह में समझौता

रामल्ला (वेस्ट बैंक), एजेंसी

- वर्षों से जारी मतभेद खत्म करने के लिए बीजिंग में घोषणापत्र पर किए हस्ताक्षर

गाजा पट्टी में गहराते युद्ध संकट के बीच फिलिस्तीन के प्रतिद्वंद्वी समूहों हमास और फतह ने वर्षों से जारी आपसी मतभेदों को खत्म करने के लिए बीजिंग में एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। गाजा पट्टी में गहराते युद्ध संकट के बीच यह घोषणापत्र फलस्तीनी क्षेत्र में मिलकर सरकार बनाने के मकसद से हमास और फतह को एकजुट करने के लिए जारी कई दौर की बातचीत का नतीजा है।

हालांकि दोनों पक्ष आपसी मतभेद दूर करने के लिए पहले भी कई ऐसे घोषणापत्र पर दस्तखत कर चुके हैं, जो विफल रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर संदेह पैदा हो गया है कि क्या चीन प्रायोजित वार्ता से वास्तव में कोई समाधान निकल सकता है। इस घोषणापत्र पर ऐसे समय में हस्ताक्षर किए गए हैं, जब इजराइल और हमास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित संघर्ष-विराम प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जो गाजा पट्टी में नौ महीने से जारी युद्ध को समाप्त कर सकता है और हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजराइली नागरिकों की आजादी का रास्ता खोल सकता है। हालांकि, समझौते पर सहमति बनने के बावजूद युद्ध के बाद गाजा पट्टी की स्थिति को लेकर संशय बरकरार रहेगा, क्योंकि इजराइल इस क्षेत्र के शासन में हमास की किसी भी भूमिका के खिलाफ है। उसने युद्ध समाप्त होने के बाद गाजा को फतह-प्रभुत्व वाले फलस्तीनी प्राधिकरण द्वारा संचालित करने के अमेरिका के आह्वान को भी खारिज कर दिया है।

## इथियोपिया में भूस्खलन से 229 लोगों की मौत

**अदीस अबाबा।** इथियोपिया के एक दूरस्थ क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 229 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासक दागमावी आयेले ने बताया कि दक्षिणी इथियोपिया के केंचो शाचा गोजदी जिले में मिट्टी धंसने की घटना में मारे गए लोगों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। गोफा जोन के संचार कार्यालय के प्रमुख कासाहुन अबेयनेह ने बताया कि इलाके में तलाश अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 229 हो गई। सोमवार रात तक 55 लोगों की मौत की सूचना थी। गोफा जोन वह प्रशासनिक इलाका है, जहां भूस्खलन हुआ है। गोफा जोन में आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी के निदेशक मेलीसे ने बताया, 'हम अब भी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं।' उन्होंने बताया, 'कई बच्चे हैं जो हादसे में अपनी मां, पिता, भाई खो चुके हैं।'

# ब्रिटेन का 'जाकिर नाइक' दोषी करार

## पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश नागरिक अंजम चौधरी को हो सकती है उम्रकैद

लंदन, एजेंसी

- आतंकी संगठन अल-मुहाजिर में कार्यवाहक की भूमिका निभाता था

ब्रिटिश-पाकिस्तानी कट्टरपंथी इस्लामवादी उपदेशक अंजम चौधरी को एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन को दिशा-निर्देश देने का दोषी पाया गया है। संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय जांच के बाद ब्रिटेन में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। अंजम चौधरी को ब्रिटेन का 'जाकिर नाइक' भी कहा जाता है।

अंजम चौधरी (57) को अल-मुहाजिर (एएलएम) में कार्यवाहक की भूमिका निभाते पाया गया था और लंदन के 'वूलविच क्राउन कोर्ट' में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि उसने 2014 के बाद एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए आतंकवादी समूह को दिशा-निर्देश दिए थे और ऑनलाइन माध्यम से की गई बैठकों को संबोधित करके संगठन के लिए समर्थन को प्रोत्साहित किया था। जानकारी के अनुसार 30 जुलाई को उसे सजा सुनाई जाएगी। माना जा रहा है कि उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की ओर से की गई जांच के परिणामरूप दोषसिद्धि हो पाई।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस की आतंकवाद-रोधी कमांड के प्रमुख कमांडर डोमिनिक मर्फी ने कहा, 'अल-मुहाजिर दुनिया भर में अपनी पहुंच बना चुका है और इसका जन सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।' अल-मुहाजिर को पहली बार 2006 में अल घुरबा नाम से ब्रिटेन द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। अल-मुहाजिर को 2010 में वैकल्पिक नाम के रूप में प्रतिबंध में शामिल किया गया। चौधरी इसके मूल तीन सदस्यों में से एक था।

पिछले साल जुलाई में लंदन के एक एयरपोर्ट से चौधरी के एक सहयोगी 29 वर्ष के खालेद हुसैन को हिरासत में लिया गया था। उसे एएलएम का सदस्य होने का दोषी पाया गया था। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि जून 2022 से अपनी गिरफ्तारी होने तक चौधरी ने छोटे-छोटे समूहों में ऑनलाइन उपदेश देकर ब्रिटेन में इस्लामिक स्टेट की स्थापना पर जोर दिया।

## श्रीलंका ने नौ भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार

कोलंबो। श्रीलंका की नौसेना ने मंगलवार को कथित तौर पर अपने जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में नौ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी नौकाएं जब्त कर ली। इसी के साथ इस वर्ष श्रीलंका द्वारा ऐसी घटनाओं में पकड़े गए भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 261 हो गई है। नौसेना ने कहा कि उत्तरी जाफना प्रायद्वीप के डेल्फ्ट द्वीप पर नौ मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और उनकी दो नौकाएं जब्त की गई। नौसेना ने 11 जुलाई को कहा था कि इस साल अवैध शिकार करने को लेकर 252 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। इस माह के आरंभ में श्रीलंका ने भारत के समक्ष एक नौसैनिक की मौत के मामले को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। दोनों देशों के मछुआरों को अक्सर अनजाने में एक-दूसरे के जलक्षेत्र में घुसने के लिए गिरफ्तार किया जाता है।

# सीमा मुद्दों को राजनयिक तंत्र के जरिये करेंगे हल: ओली

काठमांडू, एजेंसी

- नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक सांसद के सवाल का दिया जवाब

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि भारत के साथ लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी जैसे क्षेत्रों सहित सीमा मुद्दों को राजनयिक तंत्र के माध्यम से हल करने के लिए समझ बनी हुई है। ओली ने प्रतिनिधि सभा में एक सांसद के सवाल का जवाब देते हुए सोमवार को उल्लेख किया कि नेपाल-भारत सीमा पर सीमा चौकियों का निर्माण और बहाली चल रही है।

'माई रिपब्लिका' ने ओली के हवाले से कहा, "संघीय संसद, नेपाल सरकार और सभी नेपाली नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संबंध में स्पष्ट और दृढ़ रहे हैं। 17 जून, 2020 को नेपाल के संविधान में दूसरे संशोधन के माध्यम से नए मानचित्रों को संविधान की अनुसूची-3 में शामिल किया गया है और सीमा मुद्दों पर एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय सहमति है। वर्ष 1816 की सुगौली संधि के अनुसार, नेपाल सरकार दृढ़ और स्पष्ट है कि लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख सहित काली (महाकाली) नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र नेपाल के हैं।" उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं के अवसर पर हुई बैठकों के दौरान, स्थापित राजनयिक तंत्र के माध्यम से सीमा मुद्दों को हल करने पर सहमति बनी थी।

**खोज-खबर** सुपरमैसिव ब्लैक होल और डार्क मैटर के आपसी संपर्क को किया उजागर

# भौतिकीविदों का अंतिम पारसेक समस्या के निदान का प्रस्ताव

संवाददाता, नैनीताल

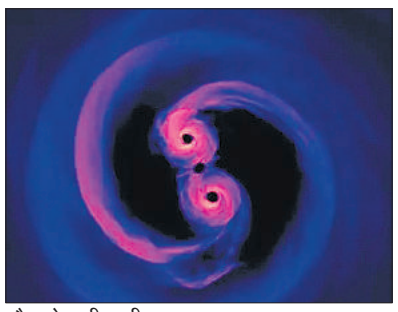

ब्लैक होल की तस्वीर।

**अमृत विचार:** खगोल भौतिकीविदों ने अंतिम पारसेक समस्या के निदान के लिए नया समाधान प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में सुपरमैसिव ब्लैक होल व डार्क मैटर कनेक्शन को उजागर किया गया है। जर्नल फिजिकल रिव्यू लेटर्स में यह शोध प्रकाशित हुआ है।

दरअसल, पारसेक एक खगोलीय मापन मात्रक है, जो सर्वाधिक दूरी को मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। मगर अंतिम पारसेक समस्या वैज्ञानिकों के लिए अभी तक रहस्य बना हुआ था। इसे नए शोध के जरिए सुलझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पर शोधकर प्रस्ताव दिया गया है। शोध में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की कुछ सबसे बड़ी और छोटी वस्तुओं के बीच एक संबंध पाया है।

यह संबंध सुपरमैसिव ब्लैक होल और डार्क मैटर कण के बीच है। उनकी नई गणना से पता चलता है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल (एसएमबीएच) के जोड़े डार्क मैटर कणों के पहले से नजरअंदाज किए गए व्यवहार के कारण एक बड़े ब्लैक होल में विलीन हो सकते हैं और यही अंतिम पारसेक समस्या के समाधान का प्रस्ताव है।

यह शोध प्रतिरूपित डार्क मैटर कणों के बीच परस्पर क्रिया गैलेक्टिक डार्क मैटर हेलो के आकार को भी स्पष्ट करता है। साथ ही डार्क मैटर के व्यवहार में भी प्रकाश डालता है। शोध में टोरंटो विश्वविद्यालय, मैकगिल विश्वविद्यालय, ट्रॉटियर अंतरिक्ष संस्थान, स्विट्जरलैंड के सीईआरएन सैद्धांतिक भौतिकी विभाग के वैज्ञानिक और शोध छात्र शामिल थे।

### खगोलीय मापन की इकाइयां

**नैनीताल:** खगोलीय मापन में तीन प्रकार की इकाइयां उपयोग में लाई जाती हैं। जिनमें सबसे छोटी इकाई को खगोलीय मात्रक यानी पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी को लिया जाता है। इसे एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। दूसरी इकाई प्रकाश वर्ष यानी एक वर्ष में चलने वाले प्रकाश की दूरी होती है। इसके अलावा सबसे लंबी दूरी को मापने के लिए पारसेक इकाई का उपयोग किया जाता है। यह सबसे बड़ा मात्रक है। जिसका मान 3 गुणा 6 प्रकाश वर्ष होता है।

# मुस्लिमों के जबरन दाह संस्कार पर माफी मांगेगा श्रीलंका

कोलंबो, एजेंसी

- श्रीलंकाई सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान विवादित शवदाह नीति की थी लागू

श्रीलंका की सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह कोविड-19 से जान गंवाने वाले मुस्लिम व्यक्तियों के जबरन दाह संस्कार के लिए देश के मुस्लिम समुदाय से औपचारिक रूप से माफी मांगेगी। श्रीलंकाई सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण कोरोना महामारी के दौरान विवादित शवदाह नीति लागू की थी।

वर्ष 2020 में कोविड-19 पीड़ितों के दाह संस्कार का अनिवार्य आदेश जारी किया गया था, जिससे मुसलमानों सहित कई अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित होना पड़ा था। हालांकि, बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच फरवरी 2021 में इस आदेश को रद कर दिया गया था। एक कैबिनेट नोट के अनुसार, श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने सोमवार को एक बैठक में मार्च 2020 में थोपे गए आदेश के लिए मुस्लिम समुदाय से माफी मांगने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने सरकार की ओर से सभी समुदायों से माफी मांगने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने ऐसे विवादास्पद कदमों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कानून लाने का भी निर्णय लिया। बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने धर्म के आधार पर शवों को दफनाने या दाह संस्कार पर एक प्रस्तावित कानून को भी मंजूरी दे दी है।